



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2016/अग्राहायण 7, 1938

No. 427]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2016/AGRAHAYANA 7, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 21 नवम्बर, 2016

सं. टीएमपी/29/2016-वीओसीपीटी.—प्राधिकरण ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48, 49 और 50 के अधीन वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) से उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का इस प्राधिकरण की 17 सितम्बर 2016 को हुई बैठक में निपटान किया गया था। तथापि, संशोधित दरमान के साथ (सुस्पष्ट) आदेश अधिसूचित करने में लगने वाले समय पर विचार करते हुए इस प्राधिकरण ने केवल संशोधित दरमान को तत्काल अधिसूचित करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, 17 सितम्बर 2016 को अनुमोदित दरमान भारत के राजपत्र में 10 अक्टूबर 2016 को राजपत्र सं. 370 द्वारा अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना में कहा गया था कि यह प्राधिकरण एतद्वारा आने वाले समय में सुस्पष्ट आदेश जारी करेगा। तदनुसार, यह प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार वीओसीपीटी से उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव के निपटान से संबंधित सुस्पष्ट आदेश अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/29/2016-वीओसीपीटी

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम:

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(सितम्बर 2016 के 17 वें दिन पारित)

यह मामला वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) से उसके दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 7 मई 2016 से संबंधित है।

2.1. वीओसीपीटी का मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम बार आदेश सं. टीएमपी/47/2012-वीओसीपीटी दिनांक 04 अगस्त 2014 द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे राजपत्र सं. 243 द्वारा 19 अगस्त 2014 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश में निर्धारित वीओसीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता 31 मार्च 2016 तक थी।

2.2. इस प्राधिकरण ने मौजूदा दरमान में निर्धारित पेंशन निधि लेवी सहित वीओसीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को आदेश में उल्लिखित कारणों से 31 अगस्त 2016 तक अथवा संशोधित दरमान के लागू होने की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करते हुए एक आदेश दिनांक 19 मई 2016 पारित किया था। दरमान की वैधता विस्तारित करते समय, यह बताया गया था कि 1 अप्रैल 2016 के बाद की अवधि के लिए वीओसीपीटी को प्रोद्भूत होने वाले अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, का संव्यवहार महापत्तन न्यासों के लिए नई प्रशुल्क नीति, 2015 द्वारा शासित किया जाएगा।

3.1. वीओसीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 07 मई 2016 के कवर में मसौदा दरमान तथा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानकों के साथ प्रशुल्क नीति, 2015 का अनुसरण करते हुए अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव जमा किया था।

3.2. वीओसीपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित निवेदन किए थे:-

- (i). औसत राजस्व अपेक्षा (एआरआर) पत्तन तथा सीएचडी के लिए अलग-अलग मूल्यांकित किया गया है।
- (ii). वीओसीपीटी ने प्रपत्र 3 में प्रस्तावित दर पर राजस्व अनुमानन और प्रपत्र 1 के अधीन वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का विस्तृत परिकलन भेजा है।
- (क). पत्तन (सीएचडी के अलावा) के लिए वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित एआरआर परिकलन की स्थिति का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:
(₹0 लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 1 (2011-12)	वर्ष 1 (2012-13)	वर्ष 2 (2013-2014)
(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	9,081.42	9,618.80	10,479.36
(ii).	प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	5,221.51	5,729.93	6,816.73
(iii).	वित्त तथा विविध व्यय (एफएमई)	4,565.21	5,545.57	5,740.22
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)+(iii)	18,868.14	20,894.30	23,036.31
(2).	घटाएं समायोजन:			
(i).	संपदा संबंधित व्यय			
	(क). परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	636.24	463.86	1,377.83
	(ख). आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	647.64	619.98	899.99
	(ग). आबंटित एफएमई	334.39	384.23	428.09
	उपजोड़ 2 (i)=[(क)+(ख)+(ग)]	1,618.27	1,468.07	2,705.91
(ii).	ऋणों पर ब्याज	-	-	-
(iii).	एकमुश्त व्ययों, यदि कोई हों, का 4/5वां जैसे मजदूरी की बकाया राशियां, पेंशन/ग्रेजुटी की बकाया राशियां, एक्स-ग्रेशिया भुगतान की बकाया राशियां, आदि (प्रत्येक मद की सूची बनाएं)			
	(क).	-	-	-
	(ख).	-	-	-
	(ग).	-	-	-
	उपजोड़ 2 (iii) = [(क)+(ख)+(ग)]	-	-	-
(iv).	पेंशन निधि में अंशदान का 4/5वां	1,300.97	640.00	1,720.00
(v).	परिचालन व्यय तथा मूल्यहास के जोड़ के 25 प्रतिशत से अधिक प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	1,804.84	2,008.71	2,837.17
(vi).	प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन शासित केपटिव बर्थ, यदि कोई हो, के प्रशुल्क निर्धारण हेतु प्रासंगिक व्यय			
	(क). परिचालन व्यय	-	-	-
	(ख). मूल्यहास	58.54	58.83	76.05
	(ग). आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-	-
	(घ). आबंटित एफएमई	-	-	-
	उपजोड़ 2 (vi) = [(क)+(ख)+(ग)+(घ)]	58.54	58.83	76.05
	2 का जोड़ = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	4,782.62	4,175.61	7,339.13
(3).	कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय (3 = 1-2)	14,085.52	16,718.69	15,697.19
(4).	क्र.सं. 3 के औसत व्यय = [वर्ष 1 + वर्ष 2 + वर्ष 3] / 3			15,500.46
(5).	नियोजित पूंजी			
	(i). 31-03-2014 को निवल अचल परिसंपत्तियां			88,644.92

	(लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)	
	(ii). जोड़े: 31-03-2014 को प्रगतिधीन कार्य (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)	9,980.39
	(iii). घटाएं: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31-3-2014 को संपदा गतिविधि से संबंधित अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य।	650.69
	(iv). घटाएं: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को बीओटी परिचालक को स्थानांतरित अचल परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, का निवल मूल्य। (VII बर्थ ₹ 2637.70 लाख + VIII बर्थ ₹ 2375.04 लाख + एनसीबी-1 1732.05)	6,744.79
	(v). घटाएं: प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन केपटिव बर्थों, यदि कोई हों, के लिए सुविचारित किए जाने के लिए प्रासंगिक लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य।	-
	(vi). जोड़े: वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.5 में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार कार्यगत पूंजी।	
	(क). वस्तुसूची	257.19
	(ख). विविध देनदारियां	228.39
	(ग). रोकड़	1,534.78
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़	2,020.35
	(vii). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)(घ)]	93,250.18
(6).	क्र.सं. 5(vii) पर 16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाम	14,920.03
(7).	31 मार्च 2014 को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) [(4)+ (6)]	30,420.49
(8).	वर्ष 2014-15 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 6% (7*1.06)	32,245.72
(9).	वर्ष 2015-16 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 3.82% (7*1.0382)	33,477.51
(10).	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	33,477.51
	घटाएं: 31-3-2014 को एस्करो खाते के अधीन उपलब्ध शेष जमा	5,637.03
	निवल एआरआर	27,840.48
(11).	उपर्युक्त क्र.सं. 10 पर अनुमानित अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित एसओआर पर राजस्व अनुमानन।	27,840.87

(ख). सीएचडी के लिए वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित एआरआर परिकलन की स्थिति का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

(₹0 लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 1 (2011-12)	वर्ष 1 (2012-13)	वर्ष 2 (2013-2014)
(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	5,165.96	5,753.90	5,845.41
(ii).	प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	-	-	-
(iii).	वित्त तथा विविध व्यय (एफएमई) लेखों के अनुसार	1,999.90	1,353.06	1,119.98
(iv).	घटाएं: पेंशन निधि में अंशदान	354.00	294.98	-
(v).	शेष एफ एंड एम व्यय	1,645.90	1,058.08	1,119.98
(vi).	जोड़े: ओपनिंग पेंशन निधि कमी	6,281.76	10,720.69	21,136.00
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)+(v)+(vi)	13,093.62	17,532.67	28,101.39

(2).	घटाएं समायोजन:			
(i).	संपदा संबंधित व्यय			
	(क). परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	-	-	-
	(ख). आर्बिट्रि प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-	-
	(ग). आर्बिट्रि एफएमई	-	-	-
	उपजोड़ 2 (i)=[(क)+(ख)+(ग)]	-	-	-
(ii).	ऋणों पर व्याज	-	-	-
(iii).	एकमुश्त व्ययों, यदि कोई हों, का 4/5वां जैसे मजदूरी की बकाया राशियां, पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशियां, एक्स-ग्रेशिया भुगतान की बकाया राशियां, आदि (प्रत्येक मद की सूची बनाएं)			
	(क). मजदूरी संशोधन बकाया राशियों का भुगतान	-		
	(ख). पेंशन/पेंशन कम्प्यूटेशन की बकाया राशियां	-		
	(ग). ग्रेच्युटी की बकाया राशियां	-		-
	उपजोड़ 2 (iii) = [(क)+(ख)+(ग)]	-	-	-
(iv).	पेंशन निधि में अंशदान का 4/5वां	5,025.41	8,576.55	16,908.80
(v).	परिचालन व्यय तथा मूल्यहास के जोड़ के 25 प्रतिशत से अधिक प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	-	-	-
(vi).	प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन शासित केपटिव बर्थ, यदि कोई हो, के प्रशुल्क निर्धारण हेतु प्रासंगिक व्यय			
	(क). परिचालन व्यय	-	-	-
	(ख). मूल्यहास	-	-	-
	(ग). आर्बिट्रि प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-	-
	(घ). आर्बिट्रि एफएमई	-	-	-
	उपजोड़ 2 (vi) = [(क)+(ख)+(ग)+(घ)]	-	-	-
	2 का जोड़ = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	5,025.41	8,576.55	16,908.80
(3).	कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय (3 = 1-2)	8,068.21	8,956.12	11,192.59
(3 क)	कुल	8,068.21	8,956.12	11,192.59
(4).	क्र.सं. 3 के औसत व्यय = [वर्ष 1 + वर्ष 2 + वर्ष 3] / 3	9,405.64		
(5).	नियोजित पूंजी			
	(i). 31-03-2014 को निवल अचल परिसंपत्तियां (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)	7.77		
	(ii). जोड़ें: 31-03-2014 को प्रगतिधीन कार्य (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)	-		
	(iii). घटाएं: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31-3-2014 को संपदा गतिविधि से संबंधित अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य।	-		
	(iv). घटाएं: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को बीओटी परिचालक को स्थानांतरित अचल परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, का निवल मूल्य।	-		
	(v). घटाएं: प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन केपटिव बर्थ, यदि कोई हों, के लिए सुविचारित किए जाने के लिए प्रासंगिक लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य।	-		
	(vi). जोड़ें: वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.5 में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार कार्यगत पूंजी।			
	(क). वस्तुसूची	-		
	(ख). विविध देनदारियां	-		
	(ग). रोकड़	580.38		
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़	580.38		
	(vii). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)(घ)]	588.15		

(6).	क्र.सं. 5(vii) पर 16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	94.10
(7).	31 मार्च 2014 को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) [(4)+ (6)]	9,499.74
(8).	वर्ष 2014-15 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 6% (7*1.06)	10,069.73
(9).	वर्ष 2015-16 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 3.82% (8*1.0382)	10,454.39
(10).	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	10,454.39
(11).	उपर्युक्त क्र.सं. 10 पर अनुमानित अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित एसओआर पर राजस्व अनुमानन।	10,454.39

- (iii). जहां तक पत्तन का संबंध है, उच्चतर नियोजित पूंजी तथा परिणामस्वरूप वर्धित आरओसीई की वजह से, वार्षिक राजस्व अपेक्षा पीपीपी यातायात को छोड़कर 2014-15 में प्रहस्ति यातायात के लिए अर्जित अर्जनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है।
- (iv). (क). यह प्रस्तावित किया गया है कि वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.11 के अनुसार वीओसीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा जो भी उचित समझा जाए वीओसीपीटी द्वारा व्यवस्थित एस्क्रो खाते में जमाशेष और और एस्क्रो खाते में भावी प्रोद्भूतों का उपयोग किया जाए। 2013-14 में रु0 56.37 करोड़ की राशि उपलब्ध है और इसलिए सकल राजस्व अपेक्षा के प्रति समायोजित किया गया है तथा रु0 278.40 करोड़ की निवल राजस्व अपेक्षा पर विचार किया गया है।
- (ख). इस प्रकार, संक्षेप में, एआरआर 31 मार्च 2014 को एस्क्रो निधि में जमाशेष घटाने के बाद और वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए प्रासंगिक वर्धनों को लागू करने के बाद निर्धारित किया गया है।
- (v). सीएचडी के मामले में, बीमांकक मूल्यांकन के मामले में पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि में भारी कमी को पूरा करने के लिए कोई अधिशेष निधियां उपलब्ध नहीं हैं। परिणामस्वरूप, पेंशन निधि लेवी साथ संवितरण के लिए उपलब्ध करवाए गए वर्किंग दिशानिर्देशों का खंड 2.11 से पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि में भारी कमी को पूरा करने के लिए सीएचडी पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। कमी को पूरा करने के लिए उपयोग करने हेतु सीएचडी में कोई एस्क्रो निधि उपलब्ध नहीं है, सीएचडी में उपलब्ध नहीं है (जोकि निपटारा ज्ञापन दिनांक 27-7-2011 के अनुसार स्वतः-पर्याप्त होना चाहिए)। अतः, बीमांकक मूल्यांकन में कमी कुल व्यय में व्यय रूप में सुविचारित की गई है और इसलिए प्रत्येक वर्ष की ओपनिंग कमी का 1/5वां कमी को पूरा करने के लिए लगातार अंशदान सुनिश्चित करने के लिए व्यय रूप में सुविचारित किया गया है। संक्षेप में, ओपनिंग कमी का 1/5वां वसूली के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस संव्यवहार को प्राधिकरण द्वारा सुविचारित किया जाए।
- (vi). पत्तन परिचालनों से रु0 27,840.48 लाख और सीएचडी से रु0 10,454.39 लाख के अनुमानित एआरआर को पूरा करने के लिए वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क संशोधन निम्नवत् है:-
- (क). वीओसीपीटी द्वारा पोत संबंधित प्रभारों, कार्गो संबंधित प्रभारों और विविध प्रभारों के लिए सभी प्रशुल्क मदों में 27.70 प्रतिशत की एकमसान वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
- (ख). 6.5 प्रतिशत की मौजूदा पेंशन निधि लेवी डिस्पेंस की गई है।
- (ग). पत्तन ने बताया है कि पेंशन निधि लेवी डिस्पेंस करने के बाद, निवल वृद्धि केवल 21.20 प्रतिशत है।
- (घ). सीएचडी के संबंध में, वीओसीपीटी ने सभी प्रशुल्क मदों में 51.20 प्रतिशत की एकसमान वृद्धि प्रस्तावित की है।
- (ङ). सीएचडी के लिए मौजूदा पेंशन निधि लेवी रु0 25.10/टन की दर से डिस्पेंस की गई है।
- (च). पत्तन ने बताया है कि पेंशन निधि लेवी डिस्पेंस करने के बाद सीएचडी में निवल वृद्धि कोयला तथा नमक से इतर कार्गो के लिए 2 प्रतिशत और कोयला जेट्टी में कोयले के लिए 13 प्रतिशत है।
- (vii). (क). प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.5 के अनुसार, सुविचारित किया जाने वाला यातायात वर्ष 2014-15 के लिए केवल पत्तन हेतु अनुमानित समग्र यातायात होगा। पत्तन ने बताया है कि प्रहस्ति वास्तविक यातायात वर्ष 2014-15 के लिए 324.14 लाख टन है। पीपीपी परिचालकों अर्थात् 7 बर्थ कंटेनर टर्मिनल, 8 बर्थ कंटेनर टर्मिनल और मै0 एनएलसी तमिल नाडु पावर लिमिटेड (एनटीपीएल) द्वारा प्रहस्ति कार्गो और पेंशन निधि लेवी से अर्जनों तथा वर्ष 2014-15 के दौरान उपर्युक्त पीपीपी परिचालकों के मामले में निकर्षण लेवी से संबंधित टनभार अतिरिक्त किए गए हैं।
- (ख). ताप कोयला के लिए रु0 38/- प्रति मी.ट. का प्रशुल्क ताप कोयला के लिए दर लागू करने में समस्याओं से बचने के लिए स्टीम (गैर-कोकिंग) कोयला सहित कोयले की सभी श्रेणियों के लिए एकसमान रूप से लागू किया गया है क्योंकि यह महसूस किया गया है कि कोयले में भेद करना जरूरी नहीं था।
- (viii). (क). वीओसीपीटी ने प्रपत्र 3 में 2014-15 के वास्तविक यातायात के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क पर राजस्व अनुमानन भेजा है।

- (ख). प्रस्ताव के साथ संलग्न एआरआर का परिकलन और राजस्व अनुमानन प्रशुल्क नीति तथा वर्किंग दिशानिर्देशों की अपेक्षानुसार प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।
- (ix). वीओसीपीटी ने मसौदा प्रस्तावित दरमान अग्रेषित किए हैं।
- (x). वीओसीपीटी द्वारा प्रपत्र-6 में प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक निम्नवत् हैं:-

क्र.सं.	कार्यनिष्पादन पैरामीटर	प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक
(1).	कार्गो संबंधित सेवाएं	
(क)	प्रमुख कार्गो समूहों के मामले में औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट (टनों में)	
1	काजू गिरी बैगों में	1,125
2	कास्टिक सोडा लाइ	3,750
3	सीमेंट	1,500
4	विलंकर्स	5,250
5	कॉपर सान्द्रण	6,750
6	डीएपी	4,500
7	डीजल ऑयल	6,000
8	भट्टी तेल आईओसी	7,500
9	भट्टी तेल एसपीआईसी	2,250
10	गारनेट सैंड बल्क	6,000
11	सामान्य कार्गो	1,875
12	ग्रेनाइट स्टोन	1,500
13	जिप्सम बल्क में	9,000
14	III/IV बर्थ में कोयला	9,000
15	IX बर्थ में कोयला	18,000
16	लिमिनाइट	8,000
17	लौह तथा इस्पात सामग्री	3,600
18	लौह अयस्क	9,750
19	चूना पत्थर	7,500
20	द्रव अमोनिया	3,750
21	लट्टे	3,450
22	एलपीजी	5,000
23	मशीनरियाँ	900
24	ज्वार	3,000
25	एमओपी	6,750
26	नाप्टा आईओसी	7,500
27	नाप्टा एसपीआईसी	3,000
28	ऑयल केक/कोपरा	1,875
29	पाम ऑयल	3,000
30	मटर (पीला)	5,250
31	पेट्रोलियम कोक	7,500
32	फास्फोरिक एसिड	2,625
33	रॉक फास्फेट	7,500
34	नमक बैगों में	1,875
35	नमक बल्क में	5,250
36	स्टोन एग्रीगेट	2,400
37	स्टोन डस्ट	2,475
38	स्टोन रफ	3,900
39	चीनी बैग में	1,875
40	चीनी (कच्ची)	5,250
41	सल्फर	6,000
42	सल्फरिक एसिड	3,000
43	एनसीबीआई में कोयला	18,750
44	कोयला जेट्टी 1 एवं 2 में कोयला	11,250
45	यूरिया	4,500
46	वीसीएम	2,250

47	गेहूँ	4,875
(ख)	कटैनरों के मामले में औसत फेरे प्रति घंटा (टीईयू में)	21
(2)	पोत संबंधित सेवाएं	
(क)	पोतों का औसत वापसी समय (दिनों में)	3.70
(ख)	पोतों का औसत पूर्व-बर्थिंग समय (दिनों में)	1.50
(3)	पत्तन द्वारा प्रासंगिक पाए गए कोई अन्य पैरामीटर	-

(xi). जहां तक शर्तों में बदलावों का संबंध है, वीओसीपीटी ने प्रस्तावित दरमान में संशोधन/समावेशन/हटाने के संबंध में निम्नलिखित कहा है:-

- (क). नौप्रस्थान पोत के लिए पत्तन देयताओं हेतु मौजूदा पृथक प्रविष्टि को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।
- (ख). पाइलेज शुल्क की परिभाषा में, यह शब्द जोड़े गए हैं कि पाइलेज शुल्क में अधिकतम दो टग कवर होती हैं। दो से अधिक अपेक्षित टगों के लिए अलग से वसूली की जाएगी।
- (ग). अनुसूची 2.4.2 के अधीन नई टिप्पणी 4 कार्गो वार आउटपुट प्रतिमानक और कार्यनिष्पादन मानक निर्धारित करते हुए शामिल की गई है। पत्तन ने बर्थ सं. 9 एवं वीओसी 2 एवं 4 में प्रहस्ति कोयला पोतों और बर्थ सं. 3 एवं 4 और बर्थ सं. 9 में प्रहस्ति कोयले के सिवाय शेष कार्गो के मामले में बर्थ किराया प्रभारों में जुर्माने और छूट का प्रस्ताव किया गया है।
- (घ). पाइलेज तथा बर्थ किराया प्रभारों के मामलों में स्थानांतरण प्रभारों के मामलों में निम्नतर स्लैब जीआरटी के लिए वर्तमान में कोई न्यूनतम प्रभार नहीं है। इसलिए, स्थानांतरण प्रभारों की अनुसूची के अधीन शामिल किए जाने के लिए यह टिप्पणी प्रस्तावित की गई है कि एसबीडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यू में स्थानांतरण बर्थों के लिए पाइलेज अनुसूची के न्यूनतम प्रभारों का 25 प्रतिशत और एसबीडब्ल्यू से एनबीडब्ल्यू और विलोमतः के बीच स्थानांतरण हेतु पाइलेज के न्यूनतम प्रभारों का 50 प्रतिशत। वर्तमान में, स्थानांतरित निम्नतर स्तर जीआरटी पोतों के मामलों में प्रभार बहुत कम हैं।
- (ङ). बर्थ किराया अनुसूची के अधीन एक नई टिप्पणी शामिल की गई है कि यदि रद्द करने की सूचना प्रार्थित सेवाओं के समय के 24 घंटे पहले प्राप्त हो जाती है तो कोई दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार नहीं होंगे; अन्यथा एक दिन का बर्थ किराया वसूल करने का प्रस्ताव किया गया है।
- (च). बर्थिंग अनुसूची में संशोधन के लिए जुर्माना रु0 5000/- प्रति संशोधन की समान दर पर प्रस्तावित किया गया है। पत्तन ने बताया है कि प्रस्तावित दर बर्थिंग अनुसूची में संशोधन के लिए प्रभार्य एक दिन के बर्थ किराया प्रभारों के स्थान पर है।
- (छ). पत्तन ने कुछ मदों के लिए मौजूदादरमान में निर्धारित यथामूल्य घाटशुल्क दर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है और इकाई आधार पर घाटशुल्क दर का प्रस्ताव किया है। मशीनरियों तथा मशीनरी पुर्जों के लिए रु0 150/- प्रति मी.ट. प्रस्तावित की गई है और शेष कार्गो के लिए, रु0 42.00 प्रति मी.ट. की दर से अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किए गए माल की मौजूदा घाटशुल्क दर जमा प्रस्तावित वृद्धि कुल रु0 53.40 प्रति मी.ट. प्रस्तावित की गई है।
- [दरमान रु0 53.63 प्रति मी.ट. प्रस्तावित करता है और वीओसीपीटी द्वारा उल्लिखित रु0 53.40 प्रति मी.ट. नहीं।]
- (ज). उतारे गए धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार रु0 5/- प्रति मी.ट. की दर से प्रस्तावित किया गया है।

4.1. वीओसीपीटी ने पुष्टि की है कि उसने प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 5.2 द्वारा यथा अपेक्षित मसौदा दरमान और प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक अंशधारकों की टिप्पणियों के लिए 06 मई 2016 को वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए थे।

4.2. वीओसीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 17 मई 2015 द्वारा यह पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था कि उसने इसके बारे में सभी प्रासंगिक अंशधारकों/उपयोक्ताओं को सूचना दे दी थी और इस प्राधिकरण को भी सूचित किया था जब कार्रवाई पूरी हो गई थी। वीओसीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 17 जून 2016 द्वारा पुष्टि की है। वीओसीपीटी ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने के लिए बोर्ड की बैठक में पारित बोर्ड संकल्प की प्रति भी भेजी थी।

5.1. यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं. 8/(15)2015-टीएमपी दिनांक 11 मई 2016 द्वारा एमओएस द्वारा अपने पत्र सं.8/(15)2015-टीएमपी दिनांक 17 सितम्बर 2015 द्वारा पहले जारी किए गए निदेश को तब तक अस्थायी तौर पर अगले आदेशों तक निलंबित रखने का निर्णय लिया था जब तक (तत्कालीन) एमएसआरटीएच द्वारा अपने पत्र सं.पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 1/3 जनवरी 2005 और 9 मार्च 2005 द्वारा जारी किए गए नीति निदेश रिस्टर नहीं किए जाते हैं। एमओएस ने इस प्राधिकरण को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 42(3) के अधीन सभी महापत्तन न्यासों और प्राधिकृत निजी परिचालकों में प्रभार्य तटीय कार्गो/कंटेनर/पोत संबंधित प्रभारों को उचित ढंग से निर्धारित करने का निदेश दिया था।

5.2. एमओएस द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त निदेश के मद्देनजर, इस प्राधिकरण ने अपने द्वारा पारित आदेश सं. टीएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 5 अक्टूबर 2015 को बनाए रखते हुए एमओएस द्वारा अपने पत्र सं. 8(15)2015-टीएमपी दिनांक 17 सितम्बर 2015 द्वारा जारी किए गए निदेश को एमओएस से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से आस्थगित रखने के आधार पर एक आदेश सं. टीएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 19 मई 2016 पारित किया था। परिणामस्वरूप, आदेश सं. टीएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 7 जनवरी 2005 और (तत्कालीन) एमएसआरटीएच द्वारा जारी किए गए नीति निदेश दिनांक 1 जनवरी 2005 के आधार पर उक्त आदेश दिनांक 15 मार्च 2005 में संशोधन एमओएस के निदेशानुसार रिस्टर किए गए हैं।

5.3. एमओएस से उपर्युक्त निदेश का वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित तटीय पोत दरों पर प्रभाव पड़ेगा। अतः वीओसीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 20 जून 2016 द्वारा अनुरोध किया गया था कि इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 19 मई 2016 के आधार पर अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव दिनांक 7 मई 2016 की समीक्षा करे और संशोधित प्रस्ताव दाखिल करे। वीओसीपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश सं. टीएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक

19 मई 2016 द्वारा अधिसूचित तटीय रियायत नीति में संशोधन पर विधिवत् विचार करते हुए अपने ईमेल दिनांक 2 जुलाई 2016 द्वारा मसौदा दरमान संशोधित किया था। तथापि, वीओसीपीटी ने सूचकांकित अधिकतम एआरआर रु 27,840.48 लाख और अपने मूल प्रस्ताव दिनांक 7 मई 2016 में यथा अनुमानित प्रपत्र-3 में राजस्व अनुमानों रु 27,840.87 को बनाए रखा है।

5.4. वीओसीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 2 जुलाई 2016 द्वारा अपना ईमेल सभी अंशधारकों/उपयोक्ताओं को अग्रेषित किया था जिसमें यह कहा गया था कि इस प्राधिकरण के आदेश दिनांक 19 मई 2016 के अनुसरण में, मसौदा दरमान 1 नवम्बर 2015 से पहले प्रचलितपद्धति के अनुसार तटीय पोतों के लिए निर्धारित दरें प्रस्तावित करते हुए उपयुक्ततः संशोधित किया गया है और संशोधित दरमान 28 जून 2016 को अपनी वेबसाइट पर डाला गया है।

6. विषय प्रस्ताव पर संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों की एक-एक प्रति वीओसीपीटी को प्रतिपुष्टिसूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी। वीओसीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 15 जून 2016 द्वारा अपना जवाब भेजा था।

7.1. तत्पश्चात्, वीओसीपीटी ने अपने पत्र सं. FIN-OFFCT-SOR-REVIS-VI-15/D1450 दिनांक 13 जून 2016 द्वारा कोचीन पत्तन में प्रति इकाई आधार पर उपलब्ध प्रशुल्क पर विचार करते हुए आरओआरओ पोतों और पीसीटीसी (थोर कार एवं ट्रक कैरियर) के माध्यम से ऑटोमोबाइल्स के प्रहस्तन का प्रस्ताव किया था। वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क निम्नवत् है:-

- (i). 1600 सीसी से कम की कार प्रहस्तन के लिए रु 500/- और 1600 सीसी से अधिक की कार के प्रहस्तन के लिए रु 1000/- की घाटशुल्क दर प्रस्तावित की गई है।
- (ii). ट्रेलर के साथ लदे कंटेनरों वाले वाहन के लिए, प्रशुल्क प्रचलित दरमान के अनुसार कंटेनर की दर अलग से वसूल करते हुए वाहन तथा कंटेनर दोनों को कवर करते हुए समेकित दर पर संग्रहीत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

7.2. पत्तन ने पुष्टि की है कि आरओआरओ के माध्यम से ट्रैक्टर प्रहस्तन में लदे हुए कंटेनरों तथा ऑटोमोबाइल्स के लिए नई प्रस्तावित घाटशुल्क दर भी इसकी वेबसाइट पर डाले गए संशोधित प्रस्तावित दरमान में शामिल की गई है। पत्तन ने मसौदा प्रस्तावित दरमान में किए गए संशोधनों को देखने के लिए सभी अंशधारकों/उपयोक्ताओं से अनुरोध किया था।

8. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, यह पाया गया था कि वीओसीपीटी के प्रस्ताव में कुछ सूचना अन्तर/कमी हैं। अतः वीओसीपीटी ने हमारे पत्र दिनांक 13 जुलाई 2016 द्वारा अपेक्षित सूचना/संशोधित गणना/प्रस्ताव 20 जुलाई 2016 तक भेजने का अनुरोध किया गया था। वीओसीपीटी ने संयुक्त सुनवाई के बाद अपने पत्र दिनांक 9 अगस्त 2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजे थे जिन्हें अनुवर्ती अनुच्छेद में दिया गया है।

9.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 11 जुलाई 2016 को वीओसीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। वीओसीपीटी ने अपने प्रस्ताव की संक्षिप्त प्रस्तुति दी थी। संयुक्त सुनवाई में, वीओसीपीटी तथा संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने अपने निवेदन पेश किए थे।

9.2. संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, वीओसीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 19 जुलाई 2016 और अनुवर्ती अनुस्मारक दिनांक 25 जुलाई 2016 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाई करने का अनुरोध किया गया था:-

- (i). हमारे पत्र दिनांक 13 जुलाई 2016 द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण/सूचना पर जवाब भेजें।
- (ii). डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (टीएनजीईडीसीओ) द्वारा किए गए लिखित निवेदनों पर टिप्पणियां भेजें।
- (iii). टीएनजीईडीसीओ ने पत्तन से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या प्रदूषण अधिभार कोयला जेट्टी 1 और 2 में प्रहस्तित कोयले पर लागू होगा। वीओसीपीटी ने स्पष्ट किया था कि यह लागू नहीं होगा। तथापि, कोयला जेट्टी 1 और 2 प्रदूषण पैदा करता है तो पत्तन चाहे तो इन दो कोयला जेट्टियों पर प्रस्तावित लेवी लागू कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, पत्तन को प्रस्तावित दरमान में शर्त में उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव करना था।
- (iv). संयुक्त सुनवाई में, वीओसीपीटी ने बताया था कि प्रस्तावित उत्पादकता प्रतिमानकों में कुछ फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता है। वीओसीपीटी को फाइन-ट्यूनिंग किए गए उत्पादकता प्रतिमानक भेजने थे और पत्तन द्वारा यथा वांछित उत्पादकता प्रतिमानक 18 जुलाई 2016 तक भेजने थे तथा इसे अपनी वेबसाइट पर अपडेट करना था और उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों को सूचित करना था।
- (v). संयुक्त सुनवाई में, वीओसीपीटी ने बताया था कि प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन उपरिव्यय (एमजीएओ) शीर्षक के अधीन लिए गए कुछ व्यय पत्तन की सभी गतिविधियों के लिए प्रासंगिक हैं। पत्तन द्वारा यथा वांछित, वीओसीपीटी को एआरआर के अनुमान में छोड़े गए एमजीएओ पर पुनर्विचार करने और 18 जुलाई 2016 तक प्रतिसाद देने की अनुमति दी गई थी।

10.1. संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत प्रथम कार्यवाई बिन्दु के संदर्भ में, वीओसीपीटी ने हमारे पत्र दिनांक 13 जुलाई 2016 द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पर अपने पत्र दिनांक 9 अगस्त 2016 द्वारा प्रतिसाद भेजा था। हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण और पत्तन द्वारा प्रेषित उत्तर का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित उत्तर
1.	सामान्य	
(i).	वर्ष 2014-15 की प्रशासनिक रिपोर्ट भेजें क्योंकि 2014-15 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में यातायात आंकड़े नहीं हैं।	यथा अपेक्षित, वर्ष 2014-15 के लिए घटक वार विवरण के साथ वर्ष 2014-15 की प्रशासनिक रिपोर्ट की प्रति भेजी गई है क्योंकि प्रशासनिक रिपोर्ट में प्रहस्तित कार्गो का विस्तृत ब्रेकअप नहीं दिया

		गया है।																									
(ii).	वीओसीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 02 जुलाई 2016 द्वारा सूचित किया था कि संशोधित प्रस्तावित दरमान (एसओआर) 28 जून 2016 को उसकी वेबसाइट पर डाला गया था और इसके बारे में अंशधारकों को स्थिति से अवगत करवाया गया था। तथापि, पत्तन ने संशोधित प्रस्तावित दरमान नहीं भेजा है। पत्तन इसे भेजे।	संशोधित मसौदा दरमान जिसे प्राधिकरण द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के संबंध में अपेक्षित संशोधन शामिल करते हुए 28-6-2016 को पत्तन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, भेजा है।																									
2.	वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) (प्रपत्र सं. 1) (पत्तन)																										
(i).	संपदा संबंधित व्यय (क्र.सं. 2(i)(ख) एवं (ग)): वीओसीपीटी ने संपदा संबंधित गतिविधि के लिए आर्बिट्रि प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्ययों के लिए वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः रु0 647.64 लाख, रु0 619.98 लाख एवं रु0 899.99 लाख अलग रखा है और रु0 334.39 लाख, रु0 384.23 लाख और रु0 428.09 लाख संपदा गतिविधि हेतु आर्बिट्रि एफएमई के लिए अलग रखे गए हैं। प्रपत्र-1 के अधीन टिप्पणी 2 और 3 पत्तन से अपेक्षा करती है कि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित राशि और लागत विवरण में सुविचारित आंकड़ों का मिलान करते हुए गणना भेजे। वीओसीपीटी ने अपेक्षित मिलान गणना नहीं भेजी है। वीओसीपीटी इसे उपलब्ध करवाए।	चूंकि संपदा गतिविधि से संबंधित आर्बिट्रि प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय और वित्त एवं विविध व्यय लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आंकड़े प्रासंगिक वर्ष के लागत विवरण से लिए गए हैं और इसलिए संपदा गतिविधि से संबंधित मूल्यहास सहित प्रचालन व्यय के आंकड़े तत्संबंधी लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के राजस्व लेखा से अनुसूची-13 से लिए गए हैं।																									
(ii).	एकमुश्त व्ययों का 4/5वां, यदि कोई हो, जैसे मजदूरी की बकाया राशि, पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशि, एक्स-ग्रेशिया भुगतान की बकाया राशि आदि (प्रपत्र-1 का क्र.सं. 2 (iii)): पत्तन ने उपर्युक्त मदों के लिए शून्य आंकड़े दर्शाए हैं। पत्तन पुष्टि करे कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के वार्षिक लेखों में एकमुश्त व्ययों जैसे मजदूरी की बकाया राशि, पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशि, एक्स-ग्रेशिया भुगतान की बकाया राशि रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।	2012-13 और 2013-14 में मजदूरी संशोधन देय था। इसलिए, इसकी देयता सृजित की गई थी और तत्संबंधी वर्ष के वेतन तथा मजदूरी हिस्से में शामिल किया गया था। इसलिए, 2013-14 में डब्ल्यूआरसी के निपटान के समय एकमुश्त भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए पत्तन ने टीएएमपी को जमा किए गए प्रस्ताव के प्रपत्र-1 का क्र.सं. 2 ;पपपद्धद में एकमुश्त व्ययों, यदि कोई हो, जैसे मजदूरी की बकाया राशि, पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशि, एक्स-ग्रेशिया भुगतान की बकाया राशि आदि के 4/5वें के कोई आंकड़े नहीं दर्शाए हैं।																									
(iii).	पेंशन निधि में एकमुश्त अंशदान का 4/5वां (प्रपत्र-1 का क्र.सं. 2 (iv)): वर्किंग दिशानिर्देश, 2015 के खंड 2.2 (iii) के अनुसार, पत्तन ने पेंशन निधि में अंशदान के 4/5वें रूप में वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः रु0 1300.97 लाख, रु0 640 लाख और रु0 1720 लाख अलग रखे थे। ये आंकड़े वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित आंकड़ों से अंतर्संबंधित नहीं किए जा सके थे क्योंकि वार्षिक लेखे पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि दोनों में अंशदान रिपोर्ट करते हैं। प्रपत्र-3 के अधीन टिप्पणी 2 और 3 पत्तन से अपेक्षा करती है कि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित राशि और लागत विवरण में सुविचारित आंकड़ों का मिलान करते हुए गणना भेजे। वीओसीपीटी इसे भेजे।	मिलान का विवरण नीचे दिया गया है:- (रु0 लाखों में) <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th>2011-12</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th></tr><tr><td>1</td><td>वार्षिक लेखों के अनुसार पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान</td><td>2000.00</td><td>2000.00</td><td>2500.00</td></tr><tr><td>2</td><td>घटाएं: ग्रेच्युटी निधि</td><td>374.00</td><td>1200.00</td><td>350.00</td></tr><tr><td>3</td><td>शेष</td><td>1626.00</td><td>800.00</td><td>2150.00</td></tr><tr><td>4</td><td>क्र.सं. 3 पर सुविचारित 4/5वां</td><td>1300.97</td><td>640.00</td><td>1720.00</td></tr></table>	क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	1	वार्षिक लेखों के अनुसार पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान	2000.00	2000.00	2500.00	2	घटाएं: ग्रेच्युटी निधि	374.00	1200.00	350.00	3	शेष	1626.00	800.00	2150.00	4	क्र.सं. 3 पर सुविचारित 4/5वां	1300.97	640.00	1720.00
क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14																							
1	वार्षिक लेखों के अनुसार पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान	2000.00	2000.00	2500.00																							
2	घटाएं: ग्रेच्युटी निधि	374.00	1200.00	350.00																							
3	शेष	1626.00	800.00	2150.00																							
4	क्र.सं. 3 पर सुविचारित 4/5वां	1300.97	640.00	1720.00																							
(iv).	प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन शासित केपटिव बर्थ, यदि कोई हो, के प्रशुल्क निर्धारण हेतु प्रासंगिक व्यय (प्रपत्र-1 का क्र.सं. 2 (vi)): वीओसीपीटी ने केपटिव बर्थ के लिए वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः रु0 58.54 लाख, रु0 58.83 लाख और रु0 76.05 लाख के मूल्यहास को अलग रखा है। तथापि, पत्तन ने केपटिव बर्थ के लिए प्रचालन व्ययों, आर्बिट्रि प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय (एमएओ) और आर्बिट्रि वित्त एवं प्रबंधन व्ययों (एफएमई) में से किसी को भी अलग रचना नहीं दिखाया है। इसके कारण स्पष्ट करें। पत्तन केपटिव बर्थ भी दर्शाए जिसके लिए वीओसीपीटी द्वारा यह अलग किया गया है।	चूंकि पत्तन ने तत्संबंधी बर्थों से संबंधित मूल्यहास के सिवाय बीओटी प्रचालकों द्वारा प्रचालित केपटिव बर्थों से संबंधित कोई प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय और वित्त एवं विविध व्यय मदों को प्रोदभूत नहीं किया है, इसलिए पत्तन ने केपटिव बर्थों के लिए प्रचालन व्ययों, आर्बिट्रि प्रबंधन तथा प्रशासन उपरिव्यय (एमएओ) और आर्बिट्रि वित्त एवं प्रबंधन व्ययों (एफएमई) को नहीं दर्शाया है। सुविचारित केपटिव बर्थों में हैं - VII मै0 पीएसए सिकाल द्वारा परिचालित बर्थ कंटेनर टर्मिनल, VIII मै0 डीबीजीटी द्वारा परिचालित बर्थ कंटेनर टर्मिनल																									

		और मै0 एनटीपीएल द्वारा परिचालित नार्थ कार्गो बर्थ-1
(v).	नियोजित पूंजी (प्रपत्र-1 का क्र.सं. 5 (iii) एवं (iv)):	
	<p>(क). नियोजित पूंजी के परिकलन के लिए वर्किंग दिशानिर्देश, 2015 के खंड 2.4 के अनुसार, पत्तन को संपदा गतिविधि से संबंधित अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य को अलग करना होगा और निवल अचल परिसंपत्तियों को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को बीओटी प्रचालकों को हस्तांतरित करना होगा। वीओसीपीटी ने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को बीओटी प्रचालकों को हस्तांतरित अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य के लिए रु0 6744.79 लाख (अर्थात् VII बर्थ रु0 2637.70 लाख + VIII बर्थ रु0 2375.04 लाख + एनसीबी-1 रु0 1732.05) और संपदा गतिविधि से संबंधित अचल परिसंपत्ति के निवल मूल्य के लिए रु0 650.69 लाख को अलग रखा है। एनसीबी-1 के लिए वीओसीपीटी द्वारा अलग रखे गए रु0 1732.05 लाख के संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस बर्थ के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के दौरान, पत्तन द्वारा यह समझा गया था कि वीओसीपीटी द्वारा एनसीबी-1 एमओएस द्वारा अपने पत्र सं. पीडी-11015/5/ 2006-टीपीटी दिनांक 22 अक्टूबर 2009 की मंजूरी के अनुसार जमा शर्तों पर किया गया था। इसके अलावा, परियोजना के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु सुविचारित पूंजी लागत एनएलसी तमिल नाडु पावर लि0 (एनटीपीएल) द्वारा प्रोद्भूत वास्तविक केपेक्स पर आधारित था। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, कृपया एनसीबी-1 के लिए रु0 1732.05 लाख को अलग रखे जाने की समीक्षा करें।</p>	<p>एनसीबी-1 से संबंधित अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य के लिए रु0 1732.05 लाख अलग रखना एनसीबी-1 के परिचालन के लिए पत्तन द्वारा विकसित बर्थ क्षेत्र के चारों ओर सड़क और बिजली संबंधी सामान्य उपयोग के लिए व्यय से संबंधित है और बर्थ से संबंधित नहीं है। इसलिए, इसे अलग रखना सही है और वार्षिक राजस्व अपेक्षा के लिए विचार किए जाने के योग्य है।</p>
	<p>(ख). पत्तन ने कुल प्रचालन व्ययों से केपिटिव बर्थों से संबंधित मूल्यहास को अलग रखा है। तथापि, वीओसीपीटी ने क्र.सं. 5 (v) पर केपिटिव बर्थ से संबंधित तदनुसूची निवल अचल परिसंपत्तियों के लिए किसी कटौती को नहीं दर्शाया है। वीओसीपीटी जांच करें और प्रपत्र-1 में उपयुक्त शोधन करें।</p>	<p>क्र.सं. 2(vi)(ख) में अलग रखा गया मूल्यहास बीओटी बर्थों के लिए है, क्योंकि केपिटिव के अधीन उल्लिखित समान के लिए कोई पृथक पंक्ति उपलब्ध नहीं थी। निवल प्रखंड में, क्र.सं. 5(iv) के अधीन पृथक पंक्ति उपलब्ध थी इसलिए इसके सामने कटौती दर्शाई गई है। इसलिए, प्रपत्र-1 में शोधन की आवश्यकता नहीं है।</p>
(vi).	<p>(क). यह देखा गया है कि रु0 33,477.51 लाख पर अनुमानित अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) से, वीओसीपीटी ने 31.03.2014 को एस्करो खाता शेष जमा होते हुए रु0 5637.03 लाख का समायोजन (कटौती) दर्शाया था और रु0 27840.48 लाख के समायोजित अधिकतम एआरआर पर पहुंचा था जोकि मसौदा प्रस्तावित दरमान में अनुमानित राजस्व से मेल खाता है। प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 4.2 और वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.11 में कहा गया है कि महापत्तन न्यास द्वारा व्यवस्थित एस्करो खातों में जमाशेष संबद्ध महापत्तन न्यासों के न्यासी बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रशुल्क नीति, 2015 और वर्किंग दिशानिर्देश महापत्तन न्यासों से यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि एआरआर के विरुद्ध एस्करो खाता जमाशेष का समायोजन किया जाए। एआरआर अधिकतम स्तर है और पत्तनों के पास अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित दरमान को लेने का अधिकार है। वीओसीपीटी एआरआर से एस्करो खाता जमाशेष के समायोजन के लिए कारण स्पष्ट करें। यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि महापत्तन न्यास जिन्होंने प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन प्रस्ताव दाखिल किया हो, में से किसी ने भी ऐसा समायोजन नहीं किया है।</p>	<p>चूंकि वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.11 में प्रावधान है कि महापत्तन न्यास द्वारा व्यवस्थित एस्करो खातों में जमाशेष संबद्ध महापत्तन न्यासों के न्यासी बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है, पत्तन ने प्रशुल्क विनियम, 2015 में यथा दिए गए सूचकांकित एआरआर से रु0 56.38 करोड़ की कटौती दर्शाई है।</p>
	<p>(ख). प्रकृति और प्रयोजन जिसके लिए एस्करो खाता व्यवस्थित किया जा रहा है, स्पष्ट करें।</p>	<p>एस्करो निधि पत्तन अवसंरचना के विकास के लिए व्यय की पूर्ति करने के लिए व्यवस्थित की गई है और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 के हिस्से के रूप में स्थापित तथा व्यवस्थित की गई है।</p>
3.	प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय संबंधी गणना (प्रपत्र-2):	
	<p>क्र.सं. 2 पर पत्तन द्वारा निर्धारित परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित परन्तु संपदा से संबंधित परिचालन व्यय के अलावा) संपदा गतिविधि के आर्बटित प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों से अलग नहीं रखा गया है जैसाकि प्रपत्र-1 के क्र.सं. 2(i) (ख) में दर्शाया गया है।</p>	<p>चूंकि प्रपत्र-2 के अनुसार, परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित परन्तु संपदा से संबंधित परिचालन व्यय के अलावा) (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार) क्र.सं. 2 द्वारा निर्धारित किया जाना है, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार केवल परिचालन व्यय की</p>

	वीओसीपीटी जांच करें और प्रपत्र-2 में जरूरी शोधन करें और संशोधित प्रपत्र-2 जमा करें।	कटौती की गई है और आबंटित प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों को अलग नहीं रखा गया है, क्योंकि इसे अलग रखने के लिए नहीं कहा गया था।
4.	प्रतिमानों के अनुसार कार्यगत पूंजी का परिकलन (प्रपत्र-4): एक माह के रोकड़ व्ययों का अनुमान लगाने के लिए वीओसीपीटी द्वारा सुविचारित एक्सल गणना में रु0 2963.24 लाख अतिरिक्त है। पत्तन अपने द्वारा सुविचारित रोकड़ व्ययों की विस्तृत गणना भेजे।	रु0 2963.24 लाख की राशि में 2013-14 के लिए पेंशन भुगतान शामिल है। चूंकि यह एक आउटफ्लो है, समानुपातिक मासिक पेंशन भुगतानों को सामान्य राजस्व के अधीन कार्यगत पूंजी में शामिल किया गया है।
5.	राजस्व अनुमानन (प्रपत्र-3):	
(i).	यह देखा गया है कि पत्तन ने प्रस्तावित दरमान पर राजस्व अनुमान लगाने के समय वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित राजस्व पर विचार किया था और प्रस्तावित दरमान पर अनुमानित राजस्व पर पहुंचने के लिए 27.7 प्रतिशत की प्रशुल्क वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। राजस्व का अनुमान लगाने के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार, वीओसीपीटी से अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2014-15 में पत्तन द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात के लिए प्रस्तावित दर पर प्रत्येक प्रशुल्क मर्दों अर्थात् कार्गो, पोतों और विविध सेवाओं के लिए राजस्व का अनुमान लगाया जाए।	प्रपत्र-1 के अनुसार पत्तन की वार्षिक राजस्व अपेक्षा प्राप्त करने के लिए, 210.68 लाख का यातायात थ्रुपुट पीपीपी परिचालकों से टनभार का निवल प्रहस्तित टनभार है। संबंधित कार्गो प्रहस्तन, पत्तन गोदी संबंधित सेवाएं और विविध सेवाएं परिगणित की गई हैं और प्राधिकरण को जमा करने के लिए प्रपत्र 3 में भेजी गई हैं। 2014-15 के वास्तविक अर्जन आधार रूप में प्रयुक्त किए गए हैं और मौजूदा दरमान पर वृद्धि की प्रस्तावित दर परिकलित की गई है।
(ii).	इसके अलावा, प्रपत्र 3 में वीओसीपीटी द्वारा सुविचारित 2014-15 का राजस्व लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित राजस्व से मेल नहीं खाता है। उदाहरणार्थ, पत्तन देयताओं के लिए, वर्ष 2014-15 के लिए वीओसीपीटी द्वारा सुविचारित अर्जन रु0 2,553.95 लाख है जोकि वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित रु0 2835.88 लाख की पत्तन देयताओं से मेल नहीं खाता है।	रु0 281.94 लाख का निकर्षण लेवी घटक वार्षिक लेखे 2014-15 के लिए पत्तन देयताओं के राजस्व में शामिल किया गया है जैसाकि वार्षिक लेखे 2014-15 (अनुसूची 7) में दर्शाया गया है। यह अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि 1-10-2014 से डिस्पेंस किया गया है। इसलिए, मौजूदा प्रस्ताव में, उक्त राशि को अर्जनों में अलग रखा गया था और शेष आंकड़े रु0 2553.95 लाख पर विचार किया गया है।
(iii).	अतः वीओसीपीटी संशोधित राजस्व अनुमान (प्रपत्र-3) राजस्व अनुमानों के समर्थन में विस्तृत गणना के साथ भेजे, जैसाकि उपर्युक्त (क) में बताया गया है। 2014-15 के वास्तविक यातायात के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क पर राजस्व का अनुमान लगाने के लिए वीओसीपीटी से निम्नलिखित भेजने का भी अनुरोध है:-	कृपया उपर्युक्त बिन्दु (ii) के उत्तर का अवलोकन करें। निवेदनों पर विचार करते हुए, पत्तन के परिकलन पर विचार किया जाए।
	<p>(क). पुष्टि करें कि पोत संबंधित प्रभारों के लिए राजस्व अनुमानों में सुविचारित कुल जीआरटी पोत वर्ष 2014-15 के लिए पत्तन द्वारा प्रहस्तित पोत के वास्तविक कुल जीआरटी से मेल खाता है। बेमेल, यदि कोई हो, की स्थिति में, वीओसीपीटी अन्तर का समाधान करें।</p> <p>(ख). पुष्टि करें कि राजस्व अनुमानों में सुविचारित कार्गो की मात्रा प्रहस्तित वास्तविक कार्गो से मेल खाती है और प्रशासनिक रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया है। भिन्नता की स्थिति में, अन्तर का समाधान करें।</p> <p>(ग). राजस्व अनुमानों के लिए सुविचारित विनिमय दर कृपया दर्शाएं।</p> <p>(घ). तटीय पोत से राजस्व का अनुमान लगाने के समय, वीओसीपीटी सुनिश्चित करें कि यह प्राधिकरण द्वारा पारित प्राधिकरण के हाल ही के आदेश सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 19 मई 2016 के अनुसार है।</p>	<p>यह पुष्टि की गई है कि पोत संबंधित प्रभारों के लिए राजस्व अनुमानों में सुविचारित कुल जीआरटी पोत वर्ष 2014-15 के लिए पत्तन द्वारा प्रहस्तित पोत के वास्तविक कुल जीआरटी से मेल खाता है क्योंकि 2014-15 के वास्तविक अर्जनों में निकर्षण लेवी को शामिल नहीं किया गया है और पेंशन निधि लेवी एआरआर का परिकलन करने के लिए वृद्धि की दर पर पहुंचने के लिए आधार रूप में सुविचारित की गई है।</p> <p>यह पुष्टि की गई है कि राजस्व अनुमानों में सुविचारित कार्गो की मात्रा वास्तविक प्रहस्तित कार्गो से मेल खाती है और प्रशासनिक रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया है क्योंकि प्रपत्र-3 में सुविचारित टनभार पीपीपी परिचालकों अर्थात् बर्थ VII और बर्थ VIII कंटेनर टर्मिनल के माध्यम से प्रहस्तित टनभार और एनसीबी 1 में एनटीपीएल परिचालनों का निवल है।</p> <p>2014-15 में किए गए वास्तविक अर्जन आंकड़ों में सुविचारित किए गए हैं।</p> <p>हाँ। तटीय पोत के लिए राजस्व इस प्राधिकरण द्वारा पारित प्राधिकरण के हाल ही के आदेश सं. टीएएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 19 मई 2016 के अनुसार अनुमानित किया गया है। चूंकि आय वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविक पर आधारित है, इसलिए तटीय अर्जन आदेश सं. 4/2004-सामान्य दिनांक 19-5-2016 के मामले में लिए गए हैं।</p>

6.	दरमान:	
(i).	<p>संशोधित वर्किंग दिशानिर्देशों का खंड 2.12 विनिर्दिष्ट करता है कि यदि एक नई शर्त शामिल की जाती है अथवा यदि मौजूदा शर्त को परिचालनात्मक आकस्मिकता की वजह से संशोधित किया जाता है, पत्तन उसके कारणों से ऐसा संशोधन निर्धारित कर सकता है और एआरआर में वित्तीय/राजस्व प्रभाव को ले सकता है। नई मदों के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क के लिए अंगीकृत आधार भेजें और इसके वित्तीय प्रभाव को प्रपत्र-3 में राजस्व अनुमानों में लिया जाए। वीओसीपीटी ने प्रस्तावित दरमान में निम्नलिखित नई प्रशुल्क मदों/शर्तों को शामिल करने और मौजूदा दरमान से निम्नलिखित प्रशुल्क मदों/शर्तों को हटाने का प्रस्ताव किया है:</p>	तथ्यात्मक
	<p>(क). <u>अध्याय-II, अनुसूची 2.1</u> पत्तन देयताएँ:</p> <p>वीओसीपीटी ने क्र.सं. 2 में नौप्रस्थान पोतों के लिए अलग से निर्धारित मौजूदा पत्तन देयताओं को हटाने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में, निम्नलिखित भेजें:</p> <p>(i). नौप्रस्थान पोतों के मामले में पृथक पत्तन देयताओं को हटाने का कारण बताएं। यह देखा गया है कि अन्य अनुसूचियों में, नौप्रस्थान पोत के लिए पृथक प्रशुल्क पत्तन द्वारा जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।</p> <p>(ii). पोतों की इस श्रेणी के लिए पत्तन देयताओं की वसूली हेतु आधार स्पष्ट करें और मौजूदा प्रशुल्क से प्रतिशत वृद्धि भी दर्शाएं। कृपया पुष्टि करें कि पोत की इस श्रेणी के लिए वृद्धि अन्य मदों के लिए पत्तन के प्रस्ताव के अनुसार 27.70 प्रतिशत होगी।</p> <p>(iii). कृपया दर्शाएं कि प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव राजस्व अनुमान में पत्तन द्वारा सुविचारित किया गया है।</p>	<p>अध्याय-2, अनुसूची 2.1 के क्र.सं. 2 पर नौप्रस्थान पोतों के लिए अलग से निर्धारित मौजूदा पत्तन देयताओं को हटाना टाइपलेखन त्रुटि की वजह से है। इसके लिए प्रस्तावित प्रशुल्क बनाए रखा जाना है और इसे प्रेषित किए गए संशोधित मसौदा दरमान में शामिल किया गया है।</p> <p>प्राधिकरण अन्य मदों के लिए पत्तन के प्रस्ताव के अनुसार पोत की इस श्रेणी के लिए 27.70 प्रतिशत तक वृद्धि पर विचार कर सकता है।</p> <p>पत्तन द्वारा पहले से जमा किए गए राजस्व अनुमान में क्र.सं. 1 पत्तन देयताएं द्वारा प्रपत्र-3 में भी प्रभाव शामिल है तथा मसौदा दरमानों में केवल यही शेष रह गया था।</p>
	<p>(ख). <u>अनुसूची 2.2.1 - पाइलटेज शुल्क की अनुसूची टिप्पणी (1)</u></p> <p>पाइलटेज शुल्क परिभाषित टिप्पणी (1) में शब्दावली, "अधिकतम दो टगों के अधीन" जोड़ा गया है और यह एक वाक्य जोड़ा गया है कि निर्धारित अधिकतम संख्या दो से अधिक अपेक्षित टगों के लिए अनुसूची 2.3 (टग किराया शुल्क) के क्र.सं. 1 में निर्धारित दरों पर वसूल की जाएगी। वर्किंग दिशानिर्देशों, 2015 का खंड 10.4 पाइलटेज को समेकित दर बनाने के लिए पाइलटेज-सह-टोवेज शुल्क रूप में परिभाषित करता है और 'पत्तन सुविधा' के लिए पर्याप्त क्षमता की टगों/लांचों की अपेक्षित संख्या और पोतों के स्थानांतरण के साथ एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी संचलन शामिल होगा। वीओसीपीटी स्पष्ट करे कि कैसे वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित परिभाषा वर्किंग दिशानिर्देशों में निर्धारित परिभाषा के अनुसार सही है जिसे सभी महापत्तन न्यासों के दरमान में एकसमान रूप से निर्धारित किया गया है।</p>	दो टगों से अधिक अतिरिक्त टग की प्रस्तावित लेवी को हटाया गया है।
	<p>(ग). <u>अनुसूची 2.2.3 - स्थानांतरण प्रभार, खंड (I) एवं (II)</u></p> <p>पत्तन ने अनुसूची 2.2.3 के अधीन यह एक नई टिप्पणी का प्रस्ताव किया है कि खंड 2.2.3 (I) में निर्धारित स्थानांतरण शुल्क तटीय पोत के मामले में रु० 4385.54 प्रति जलयान और विदेशगामी पोत के लिए अ.डा. 168.18 के न्यूनतम प्रभार के अधीन है। इसी प्रकार, पत्तन ने अनुसूची 2.2.3 (II) के अधीन न्यूनतम स्थानांतरण प्रभारों का प्रस्ताव किया है। न्यूनतम प्रभारों के निर्धारण का आधार स्पष्ट करें।</p>	<p>अनुसूची 2.2.1 में विनिर्दिष्ट स्लैबों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रभार पाइलटेज शुल्कों के 25 प्रतिशत/50 प्रतिशत पर पाइलटेज शुल्क न्यूनतम प्रभारों का 25 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत न्यूनतम प्रभारों के रूप में अनुपाततः अंगीकृत किया गया है और अनुसूची 2७2७3७;५५ और ;५५ में प्रस्तावित किया गया है।</p>
	<p>(घ). अनुसूची 2.2.1, 2.2.2 और 2.2.3 से संबंधित सामान्य टिप्पणियाँ।</p> <p>खंड 9 (ख)(ii), के अधीन अनुसूची 2.2.1, 2.2.2 और 2.2.3 से</p>	

	<p>संबंधित सामान्य टिप्पणियों के अधीन, पत्तन ने बर्थ सं. VII, VIII उत्तर कार्गो बर्थ सं. I एवं II जोड़ा है। मौजूदा खंड में बर्थ सं. VII, VIII उत्तर कार्गो बर्थ सं. I एवं II के परिवर्धन के कारण स्पष्ट करें। पुष्टि करें कि प्रस्तावित संशोधन का राजस्व प्रभाव, यदि कोई हो, जिससे अतिरिक्त राजस्व सृजित हो सकता है को राजस्व अनुमानों में लिया गया है।</p>	<p>चूंकि इसके गैर निष्पादन की वजह से बाह्य लंगरगाह/किसी अन्य बर्थ में पोतों के स्थानांतरण की संभावना है अन्य बर्थों VII, VIII एनसीबी-I एवं एनसीबी-II में बर्थ किए गए/बर्थ किए जाने वाले पोतों के मामले में किया गया प्रावधान संशोधित किया गया है। ऐसे मौके बहुत कम हैं और वित्तीय रूप से नगण्य हैं।</p>
	<p>(ड). अनुसूची 2.3 – टग किराया शुल्क, क्र.सं. 1 अनुसूची 2.3 के अधीन टिप्पणी 1 में विनिर्दिष्ट शब्दावली “और पाइलटज परिचालन के लिए अधिकतम दो टगों से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त टग का किराया भी” के परिवर्धन की उपर्युक्त 6 (ii) (ख) पर हमारे प्रश्न के आलोक में पुनः जांच करें। इसी तरह, अनुसूची 2.3 के अधीन टिप्पणी 1 में प्रस्तावित संशोधन भी दोबारा देखें और उपर्युक्त 6 (ii) (ख) पर हमारे प्रश्न के आलोक में संशोधित करें।</p>	<p>शब्दावली “और पाइलटज परिचालन के लिए अधिकतम दो टगों से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त टग का किराया भी” का परिवर्धन क्र.सं. 6 (ख) द्वारा उत्तर के संबंध में हटाया जाए।</p>
	<p>(च). अनुसूची सं. 2.4.2 अन्य पोतों के लिए बर्थ किराया प्रभार – क्र.सं. 1 से 3 पर विदेशगामी पोतों के अधीन अनुसूची 2.4.2 में निर्दिष्ट रूपया मूल्यवर्गीकरण टाइपलेखन त्रुटि प्रतीत होती है। इसे सही करें। इसके अलावा, 27.7 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि लागू करते हुए अन्य क्राफ्टों के लिए तटीय प्रशुल्क रु० 2.18/जीआरटी/घंटा की प्रस्तावित दर की बजाय रु० 2.12 प्रति जीआरटी/घंटा होता है। पत्तन सभी मदों के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क दरों को दोबारा देखे और सुनिश्चित करें कि कोई टाइपलेखन त्रुटि नहीं हुई हो।</p>	<p>क्र.सं. 1 द्वारा संलग्न किए गए मसौदा दरमान में रूपया मूल्यवर्गीकरण में क्र.सं. 1 से 3 का प्रशुल्क दर्शाते हुए टाइपलेखन त्रुटि को शोधित किया गया है। अन्य क्षेत्रों में टाइपलेखन त्रुटि सत्यापित की गई हैं और शोधन शामिल किए गए हैं।</p>
न	<p>(छ). अनुसूची सं. 2.4.2 अन्य पोतों के लिए बर्थ किराया प्रभार के अधीन टिप्पणियाँ:</p> <p>(i). पत्तन ने टिप्पणी 4 के बाद यह एक टिप्पणी प्रस्तावित की है कि फील्ड शर्त के अनुसार प्रतिमानों में संशोधित करने का अधिकार पत्तन के पास है और इस संबंध में यातायात प्रबंधक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। चूंकि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित (किए जाने वाले) कार्यनिष्पादन मानक का प्रशुल्क में सूचकांकन से संबंध होगा, इसलिए प्रशुल्क चक्र की करेंसी के दौरान प्रतिमानों को संशोधित करने के लिए प्रस्तावित टिप्पणी का प्रशुल्क के सूचकांकन से प्रतिरोध हो सकता है जिसका पूर्व-निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों से संबंध है। अतः प्रस्तावित टिप्पणी की समीक्षा करें।</p> <p>(ii). पत्तन ने बर्थ सं. IX और VOC II एवं IV में प्रहस्ति कोयला पोतों और बर्थ सं. III एवं IV और बर्थ सं. IX में प्रहस्ति कोयले के सिवाय शेष कार्गो के मामले में निर्धारित प्रतिमानों से अधिक अर्जित करने के लिए बर्थ किराया प्रभारों में रियायत और निर्धारित आउटपुट प्रतिमानों को अर्जित नहीं करने के लिए जुर्माने से संबंधित टिप्पणियों का भी प्रस्ताव किया है। इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट करें:</p> <p>(क). बर्थ सं. 9 में कोयले की निकासी के लिए कन्वेयर के माध्यम से अभियंत्रित प्रहस्तन की शुरुआत तक और बर्थ सं. 3 और 4 में 2 एचएमसी की तैनाती तक अधूरी है। प्रस्तावित टिप्पणी के लिए कार्गो के साथ पूर्ण टिप्पणी भेजे।</p> <p>(ख). उत्पादकता के उक्त स्तर के लिए जुर्माना प्रस्तावित करने हेतु बर्थ सं. 3 और 4 में कोयला प्रहस्तन के लिए 12000 मी.ट./दिन/10500 मी.ट./दिन, बर्थ सं. 4 में कोयला प्रहस्तन के लिए 24000 मी.ट./दिन और 21000 मी.ट./दिन का तलचिह्न स्तर उत्पादकता प्रस्तावित करने के कारण और आधार स्पष्ट करें क्योंकि वे वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित कार्गो आउटपुट प्रतिमानों से मेल नहीं</p>	<p>बर्थों में उपलब्ध दिए गए अवसंरचना पर प्रत्येक घटक के लिए अर्जित किए जाने योग्य लक्ष्य स्तरों पर पहुँचने के लिए चरणबद्ध तरीके से खंड 7.2 कार्यनिष्पादन मानक द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए महापत्तनों हेतु शुष्क बल्क के लिए नई बर्थिंग नीति के अनुसार। इस छोर पर, लंगरगाह प्रभारों के साथ विभिन्न घटकों के लिए कार्यनिष्पादन प्रतिमानक सभी पत्तनों द्वारा प्रत्येक सप्ताह परिकलित किए जाएंगे। इसके अलावा, महापत्तनों के लिए शुष्क बल्क कार्गो हेतु बर्थिंग नीति का बिन्दु सं. 8 भेजा गया है। शब्दावली “यातायात प्रबंधक का निर्णय — अंतिम और बाध्यकारी है हटा दिया गया है”।</p> <p>बर्थ में विराम के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए बर्थ किराये पर 3 गुना और 5 गुना जुर्माना मै0 बीसीजी की उसकी रिपोर्ट 04-11-2015 की अनुशंसाओं के आधार पर गणना की गई है (पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा यथा निर्देशानुसार गैर-परिवर्तनीय)। परामर्शदाता की अनुशंसाएं भेजी गई हैं। तथापि, संशोधित किए जाने तक प्रभावी रहने वाली नई बर्थिंग नीति, 2016 के अनुसार अतिरिक्त बर्थ घंटों पर जुर्माने की सीमा 3 गुना रहेगी।</p> <p>बर्थ सं. 9 और बर्थ सं. 3 एवं 4 में कोयला प्रहस्तन पर तलचिह्न उत्पादकता मै0 बीसीजी की उसकी रिपोर्ट 04-11-2015 की अनुशंसाओं के आधार पर तैयार की गई है (पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा यथा निर्देशानुसार गैर-परिवर्तनीय)। परामर्शदाता की अनुशंसाएं संदर्भ के लिए संलग्न की गई हैं। परन्तु वर्तमान में, बर्थिंग नीति, 2016 में शुष्क बल्क कार्गो के लिए संशोधित उत्पादकता प्रतिमानों पर पोत परिवहन मंत्रालय की अनुशंसाओं के आधार पर पत्तन द्वारा प्रस्तावित नए उत्पादकता प्रतिमानक मै0 बीसीजी द्वारा प्रस्तावित उत्पादकता प्रतिमानों का अधिक्रमण करते हैं। परामर्शदाता की</p>

<p>खाते हैं।</p> <p>(ग). इसी तरह, बर्थ सं. 9 में कोयला के लिए 25500 टन/दिन/27000 टन/दिन का उत्पादकता स्तर प्रस्तावित करने और रियायत प्रस्तावित करने के लिए बर्थ सं. 3/4 में प्रहस्तिर कोयले के लिए 13500 टन/दिन/15000 टन/दिन के उत्पादकता स्तर यदि निर्धारित स्तर से अधिक उत्पादकता प्रस्तावित करने के कारण और आधार स्पष्ट करें क्योंकि वे वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित कार्गो आउटपुट प्रतिमानकों से मेल नहीं खाते हैं।</p> <p>(घ). जुर्माना 3 गुना और 5 गुना, बर्थ किराया (घाट क्रेन तत्व के अलावा) और बर्थ किराया प्रभारों में 10 प्रतिशत/20 प्रतिशत प्रस्तावित करने के कारण और आधार स्पष्ट करें।</p> <p>(ङ). टिप्पणियों में भविष्य आउटपुट प्रस्तावित करने के कारण, आधार और औचित्य भी स्पष्ट करें।</p> <p>(च). पत्तन ने कोयला प्रहस्तन के अभियंत्रित परिचालनों की शुरुआत के बाद जुर्माना/रियायत की वसूली के लिए पृथक शर्तों का प्रस्ताव किया है।</p> <p>(i). प्रस्तावित टिप्पणी में सुविचारित प्रत्येक पैरामीटर का आधार विस्तार से स्पष्ट करें।</p> <p>(ii). बर्थ सं. (9) और वीओसी 3 एवं 4 के लिए अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क में जुर्माने की वसूली तथा रियायत प्रदान करने को शासित करने वाली प्रस्तावित शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। अतः वीओसीपीटी ध्यानपूर्वक जांच करे कि क्या प्रस्तावित शर्तों के निर्धारण से बर्थ सं. (9) और वीओसी 3 एवं 4 के सफल बोलीदाताओं के बीच विवाद उत्पन्न हो जाएगा।</p> <p>(छ). पत्तन प्रस्तावित शर्तों की प्रत्येक शर्त के मद्देनजर प्रोद्भूत होने की संभावना वाली अतिरिक्त आय की गणना भेजे और यह भी दर्शाए कि इसे राजस्व अनुमानों में कहाँ लिया गया है।</p>	<p>अनुशंसाएँ संलग्न कर भेजी गई हैं।</p> <p>बर्थ सं. 9 और बर्थ सं. 3 एवं 4 में कोयला प्रहस्तन पर तलचिह्न उत्पादकता मै0 बीसीजी की उसकी रिपोर्ट 04-11-2015 की अनुशंसाओं के आधार पर तैयार की गई है (पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा यथा निर्देशानुसार गैर-परिवर्तनीय)। परामर्शदाता की अनुशंसाएं संदर्भ के लिए संलग्न की गई हैं। परन्तु वर्तमान में, बर्थिंग नीति, 2016 में शुष्क बल्क कार्गो के लिए संशोधित उत्पादकता प्रतिमानों पर पोत परिवहन मंत्रालय की अनुशंसाओं के आधार पर पत्तन द्वारा प्रस्तावित नए उत्पादकता प्रतिमानक मै0 बीसीजी द्वारा प्रस्तावित उत्पादकता प्रतिमानों का अधिक्रमण करते हैं। परामर्शदाता की अनुशंसाएँ संलग्न कर भेजी गई हैं।</p> <p>जुर्माना तथा रियायत योजना मै0 बीसीजी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 04-11-2015 में निरूपित तथा अनुशंसित की गई थी (पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा यथा निर्देशानुसार गैर-परिवर्तनीय)। परामर्शदाता की अनुशंसाएँ संलग्न कर भेजी गई हैं।</p> <p>भविष्य आउटपुट डिनोट करता है कि बर्थ 9 में प्रस्तावित अभियंत्रितकरण के कार्यान्वयन के बाद तलचिह्न आउटपुट को बढ़ाकर 24000 मी.ट. से 28000 मी.ट और इसी तरह किया गया है।</p> <p>बर्थिंग नीति, 2016 के आधार पर अब यह आधार वापिस हो गया है। जुर्माने और प्रोत्साहन जुर्माने पर आधारित हैं और प्रोत्साहन मंत्रालय की बर्थिंग नीति में दिए गए हैं।</p> <p>बर्थ सं. 9, वीओसी 3 एवं 4 में कोई पीपीपी परिचालन नहीं हैं, क्योंकि ये बर्थ वीओसी पत्तन द्वारा परिचालित किए जाते हैं। केवल बर्थ 9 में लाइसेंस आधार पर वर्तमान में एचएमसी तैनात किया गया है। जुर्माना और रियायत प्रदान करना पोत परिचालकों पर होगा।</p> <p>चूंकि यह खंड कम उत्पादकता के लिए जुर्माने और उच्चतर उत्पादकता के लिए प्रोत्साहन से संबंधित है, वित्तीय विवीक्षा अनुमान से परे है तथा यह उत्पादकता में सुधार करने के लिए सरकारी प्रतिमानों पर विचार करते हुए नगण्य होगा।</p>
<p>(ज). अनुसूची सं. 2.4.2 – टिप्पणी क्र.सं. 11</p> <p>(i). पत्तन ने क्र.सं. 11 (i) एवं (ii) पर अनुसूची 2.4.2 के अधीन नई टिप्पणियों का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित टिप्पणियों को शामिल करने के कारण स्पष्ट करें।</p> <p>(ii). रु0 5000/- प्रति संशोधन प्रस्तावित करने का आधार भी स्पष्ट करें।</p> <p>(iii). मौजूदा टिप्पणी (9) एवं प्रस्तावित टिप्पणी सं. (11) बर्थिंग अनुसूची में संशोधन सहित सेवाओं को रद्द करने के लिए एक दिन का बर्थ किराया प्रभार प्रस्तावित करता है। पत्तन के प्रस्ताव में बताया गया है कि मौजूदा प्रावधानों की बजाय एकसमान दर के रूप में रु0 5000 प्रति संशोधन प्रस्तावित किया गया है। तथापि, मौजूदा टिप्पणी (9) को बनाए रखने और नई टिप्पणी 11(ii) प्रस्तावित करने से, समान सेवा के लिए लेवी में डुप्लीकेशन होगा। पत्तन जांच करे और जरूरी संशोधन प्रस्तावित करे। पुष्टि करें कि इसका राजस्व प्रभाव प्रपत्र-3 में राजस्व अनुमानों में सुविचारित किया गया है।</p>	<p>उपयोक्ताओं ने पोतों के संख्यांकन के बाद पोत बुकिंग रद्द करने के लिए वसूल किया गया एक दिन का दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार और इसे एक्सोरबिटेंट मानते हुए बर्थिंग कार्यक्रम में संशोधन अनुरोध को वापिस लेने का अनुरोध किया था। इसलिए, अनुरोध पर विचार करने के लिए और बर्थिंग कार्यक्रम के संशोधन के लिए भी, दो नई टिप्पणियां शामिल करने की शर्त में छूट का प्रस्ताव किया गया है। इस मुद्दे पर राजस्व प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि यह संचयी नहीं है।</p>
<p>(झ). अध्याय 3, अनुसूची 3.1, क्र.सं. 3(ख), (ग):</p> <p>(i). पत्तन ने अनुसूची के अधीन दो मदों को क्र.सं. अर्थात् 3 (ख) कोयला किसी भी नाम से जिसे सीमाशुल्क दस्तावेजों में वर्णित</p>	<p>वर्तमान में कोयले के वर्गीकरणों में स्पष्टता नहीं है कि कौन से बिजली संयंत्रों के लिए हैं और कौन से बिजली संयंत्रों से इतर हैं,</p>

	<p>किया गया हो और ताप बिजली संयंत्रों के लिए उपयोग किया गया हो और 3 (ग) कोयला किसी भी नाम से जिसे क्र.सं. 3 (ख) से इतर सीमाशुल्क दस्तावेज में वर्णित किया गया हो में शामिल किया गया है। वीओसीपीटी प्रस्तावित दरमान में उपर्युक्त प्रत्येक नई प्रशुल्क मदों को शामिल करने के कारण और आधार विस्तार से स्पष्ट करें। यह भी पुष्टि करें कि क्या उपर्युक्त प्रत्येक प्रशुल्क मद का प्रभाव प्रपत्र-3 में राजस्व अनुमानों में लिया गया है।</p> <p>(ii). मौजूदा दरमान अध्याय-2, अनुसूची 3.1 के अधीन क्र.सं. 3 (ख) पर स्टीमिंग (गैर-कुकिंग कोयला) के लिए पृथक घाटशुल्क दर निर्धारित करता है। इस मद को हटाने का कारण स्पष्ट करें। इस कार्गो के लिए संशोधित दरमान के अनुसार प्रभाव घाटशुल्क दर भी स्पष्ट करें।</p>	<p>जैसे सीमाशुल्क दस्तावेज केवल स्टीमिंग (गैर-कुकिंग) कोयला के रूप में वर्गीकृत करता है।</p> <p>सीमाशुल्क दस्तावेजों में ताप कोयला/इतर कोयला के रूप में कोई पृथक विवरण नहीं है। इसलिए कम संग्रहण का मुद्दा सतर्कता और रजिस्ट्रेंट ऑडिट पर्यवेक्षण द्वारा देखा गया है, निर्वहन में अन्तर की वजह से। उपर्युक्त पर विचार करते हुए, कोयले को एकल वर्गीकरण में लाया गया है। उपर्युक्त की वजह से राजस्व वृद्धि का प्रभाव प्रपत्र-3 में राजस्व अनुमानों में उपयुक्ततः लिया गया है।</p> <p>कृपया उपर्युक्त बिन्दु सं. ;पद्ध के उत्तर का अवलोकन करें।</p>									
	<p>(ज). अध्याय 3, अनुसूची 3.1, क्र.सं. 23:</p> <p>मौजूदा दरमान क्र.सं. 23 पर अनुसूची 3.1 में “अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया माल” के लिए पृथक घाटशुल्क दर निर्धारित करता है। पत्तन ने इस प्रशुल्क मद को हटाने का प्रस्ताव किया है। इस मद को हटाने का कारण स्पष्ट करें। पत्तन यह भी स्पष्ट करें कि अवशिष्ट कार्गो श्रेणी के लिए घाटशुल्क दर क्या होगी, यदि कार्गो विशेष अनुसूची में निर्धारित कार्गो मदों में फिट नहीं आता है।</p>	<p>अनुसूची 3.1 में “अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया माल” के लिए दर को हटाया नहीं गया है। प्रशुल्क अध्याय-3, अनुसूची 3.1 के क्र. सं. 16 के अधीन उपलब्ध है।</p>									
	<p>(ट) अध्याय 3, अनुसूची 3.1, घाटशुल्क प्रभार क्र.सं. 24 से 25:</p> <p>आरओआरओ पोतों (रोल ऑन रोल ऑफ) पीसीटीसी (थोर कार एवं ट्रक कैरियर) के माध्यम से ऑटोमोबाइल</p> <p>पत्तन ने आरओआरओ पोतों के माध्यम से ऑटोमोबाइल के प्रहस्तन के मामले में अपने पत्र सं. एफआईएन-ओएफएफसीटी-एसओआर-आरईवीआईएस-VI -15/डी 1450 दिनांक 13 जून 2016 द्वारा 1600 सीसी से कम की कार के प्रहस्तन के लिए रु 500/- और 1600 सीसी से अधिक की कार के प्रहस्तन के लिए रु 1000/- की नई घाटशुल्क मदों का प्रस्ताव किया है। वीओसीपीटी ने बताया है कि यह कोचीन पत्तन (सीओपीटी) में इसी सुविधा के लिए उपलब्ध प्रशुल्क पर आधारित है। इस संदर्भ में, यह कहना है कि आरओआरओ के लिए हाल ही में सीओपीटी के लिए अनुमोदित दर निम्नवत् है:</p> <table border="1" data-bbox="344 1304 836 1470"> <tr> <td>मोटर वाहन सिवाय मोटरसाइकिलें</td><td>तटीय</td><td>विदेशी</td></tr> <tr> <td>आरओ-आरओ प्रणाली द्वारा</td><td>1080.00</td><td>1800.00</td></tr> <tr> <td>आरओ-आरओ प्रणाली से इतर</td><td>2160.00</td><td>3600.00</td></tr> </table> <p>वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें सीओपीटी के दरमान में निर्धारित दरों से मेल नहीं खाती हैं। अतः वीओसीपीटी सही स्थिति दर्शाए कि पत्तन ने कौन सी दर अंगीकृत की है। पत्तन इस संदर्भ में वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 5.7.1 का अवलोकन करें जो नए कार्गो/सेवा/सुविधा के लिए प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित है और उक्त खंड का अनुपालन करते हुए प्रशुल्क का प्रस्ताव करें।</p>	मोटर वाहन सिवाय मोटरसाइकिलें	तटीय	विदेशी	आरओ-आरओ प्रणाली द्वारा	1080.00	1800.00	आरओ-आरओ प्रणाली से इतर	2160.00	3600.00	<p>1600 सीसी से कम की कार के प्रहस्तन के लिए रु 500/- और 1600 सीसी से अधिक की कार के प्रहस्तन के लिए रु 1000/- की दर से आरओ आरओ पोतों के माध्यम से ऑटोमोबाइल प्रहस्तन के लिए दर निर्धारित करने हेतु प्रशुल्क चेन्सई पत्तन न्यास के प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि प्रस्तावित दर कोचीन पत्तन न्यास में उपलब्ध दर पर आधारित है। प्राधिकरण से अनुरोध है कि प्रस्तावित दर के अनुमोदन पर विचार किया जाए।</p>
मोटर वाहन सिवाय मोटरसाइकिलें	तटीय	विदेशी									
आरओ-आरओ प्रणाली द्वारा	1080.00	1800.00									
आरओ-आरओ प्रणाली से इतर	2160.00	3600.00									
	<p>(ठ). अध्याय 5, अनुसूची 5.03 क्र.सं. 1 से 4</p> <p>मौजूदा दरमान क्र.सं. 1 से 4 पर मोबाइल क्रेन/फोर्क लिफ्ट ट्रक/मार्शल दिमाग क्रेन किराये पर लेने के लिए पृथक प्रभार निर्धारित करता है। पत्तन ने इन प्रशुल्क मदों को हटाने का प्रस्ताव किया है। इन मदों को हटाने का कारण स्पष्ट करें।</p>	<p>चूंकि क्र.सं. 1 से 4 पर उक्त मोबाइल क्रेन/फोर्क लिफ्ट ट्रक/मार्शल दिमाग क्रेन बहुत पहले सर्वेक्षण किए जा चुके हैं और पत्तन के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए उक्त मदों के लिए प्रशुल्क को हटाया जाना है।</p>									

	<p>(ड) अध्याय 5, अनुसूची 5.03 टिप्पणी:</p> <p>मौजूदा दरमान यह टिप्पणी निर्धारित करता है कि जलयान तट स्थानांतरण, घाट से भंडारण यार्ड और विलोमतः के लिए कॉलम 5 में दर तटीय कार्गो और रियायती प्रशुल्क के लिए पात्र कंटेनरों के लिए लागू होगी। पत्तन ने इस टिप्पणी को हटाने का प्रस्ताव किया है। इस टिप्पणी को हटाने का कारण स्पष्ट करें। इस टिप्पणी को जारी रखा जा सकता है क्योंकि यह पोत परिवहन मंत्रालय की तटीय रियायत नीति से आती है।</p>	<p>यह टिप्पणी प्राधिकरण को जमा किए गए प्रस्तावित मसौदा दरमान में जानबूझकर शामिल नहीं की गई है। इसे क्र.सं. 1 द्वारा संलग्न किए गए मसौदा दरमान में शामिल किया गया है।</p>
<p>(ii).</p>	<p>पत्तन द्वारा प्रेषित प्रपत्र 3 से यह देखा गया है कि वीओसीपीटी ने निम्नलिखित कुछ मदों के लिए प्रस्तावित दरमानों में राजस्व का अनुमान नहीं लगाया है:</p> <p>(क). अनुसूची 2.2.2 – विविध पाइलटेंज शुल्क</p> <p>(ख). अनुसूची 2.3 – टग किराया शुल्क</p> <p>(ग). अनुसूची 4.1., 4.2 एवं 4.3 – कंटेनर संबंधित प्रभार</p> <p>(घ). अनुसूची 5.01 – जोन क एवं ख के लिए भारतोलन प्रभार</p> <p>(ङ). अनुसूची 5.5. – जलयान भंडारों/बंकर ऑयल से जलयान परिवहन के लिए पत्तन पाइपलाइनों का प्रयोग करने के लिए प्रभार।</p> <p>(च). अनुसूची 5.6 – पोत परिवहन परिचालन के संबंध में उपयोग के लिए प्रभार।</p> <p>(छ). अनुसूची 5.9 – नौप्रस्थान पोत के स्वामियों को शुष्क गोदी किराये पर देने और अन्य राज्य सरकारी विभाग को उनके पोत के शुष्क गोदीकरण के लिए प्रभार।</p> <p>(ज). अनुसूची 5.10 – सरकारी विभाग को औजार और संयंत्र किराये पर देने के लिए किराया प्रभार।</p> <p>(झ). अनुसूची 5.11 – कॉपर लाइसेंस शुल्क</p> <p>(ञ). अनुसूची 5.12 – फोटो परमिट जारी करने के लिए प्रभार</p> <p>(ट) अनुसूची 5.13 – अस्थायी पास जारी करने के लिए प्रभार।</p> <p>(ठ). अनुसूची 5.14 – फोटोग्राफ/फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रभार</p> <p>(ड). अनुसूची 5.15.1 एवं 5.15.2 – सामानों के साल्वेज/ड्राईवर की सेवाओं के लिए शुल्क</p> <p>(ढ). अनुसूची 5.17 – यात्री भाड़ा</p> <p>(ण). अनुसूची 5.18 – डुप्लीकेट बिल प्रति आदि जारी करना</p> <p>(त). अनुसूची 5.19 – नौप्रस्थान पोतों के लिए लकड़ी के लट्ठों हेतु प्रभार</p> <p>(थ). अनुसूची 6.1(4) – कंटेनर भरण/खाली करना परिचालन के लिए सीएचडी</p> <p>(द). 1600 सीसी से कम कार के प्रहस्तन के लिए रु0 500 और 1600 सीसी से अधिक की कार के प्रहस्तन के लिए घाटशुल्क</p> <p>(न). ट्रैलरों के साथ लदे हुए कंटेनरों वाले वाहनों के लिए, प्रशुल्क प्रचलित दरमान के अनुसार कंटेनर की दर अलग से वसूल करते हुए वाहन तथा कंटेनर दोनों को कवर करते हुए समेकित दर पर संग्रहीत किया जाएगा।</p> <p>वीओसीपीटी से अनुरोध है कि उपर्युक्त मदों के लिए प्रस्तावित दरों पर भी राजस्व का अनुमान लगाया जाए। विकल्पतः, वीओसीपीटी उपर्युक्त कुछ ऐसी मदों के प्रशुल्क का ध्यान रखने के लिए अनाच्छादित एआरआर की उचित राशि छोड़ सकता है जिसके लिए राजस्व का अनुमान नहीं लगाया गया है।</p>	<p>चूंकि उठाए गए प्रश्न में क्र.सं. (क) से (थ) तक अर्जन बहुत कम राशि है और इसलिए इसे मूल पोत संबंधित आय में जोड़ा गया है और राजस्व अनुमानन परिगणित किया गया है। इसलिए, प्राधिकरण से अनुरोध है कि दाखिले के लिए इसपर विचार करें।</p> <p>चूंकि भविष्य में इस नए कार्गो मद की संभावना है, इसलिए इसके वित्तीय प्रभाव को परिमाणित नहीं किया जा सका।</p>
<p>(iii).</p>	<p>अनुसूची 5.20 निजी परिचालक द्वारा संस्थापित हारबर मोबाइल क्रेनों</p>	<p>सहमत हैं। समीक्षा के आधार पर और यदि अपेक्षित प्रस्ताव पर</p>

	<p>(एचएमसी) के उपयोग के लिए प्रभार</p> <p>वीओसीपीटी ने प्रस्तावित अनुसूची में 27.7 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एचएमसी के लिए मौजूदा प्रशुल्क मानक आधार पर आदेश सं. टीएमपी/22/2007-टीपीटी दिनांक 30 दिसम्बर 2009 के अनुसार है जो दरमान के पिछले सामान्य संशोधन में निर्धारण जारी रखा गया था।</p> <p>प्रशुल्क नीति 2015 में, खंड 9.1 से 9.3 पत्तन द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित प्रभारों के प्रशुल्क विनियमन हेतु प्रावधान निर्धारित करते हैं। प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा परिचालित सामान्य एसओआर से एचएमसी के लिए 27.7 प्रतिशत प्रशुल्क संशोधन लागू करते हुए वीओसीपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव उक्त दिशानिर्देश प्रावधान के अनुसार नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में, वीओसीपीटी मानक आधार पर प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाई गई एचएमसी के लिए दर में संशोधन के लिए पृथक प्रस्ताव दाखिल करे।</p>	अलग से कार्यवाही की जाएगी।
(iv).	<p>रु0 5/- प्रति मी.ट. की दर से उतारे गए धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार।</p> <p>वीओसीपीटी ने धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार के लिए नए प्रशुल्क का प्रस्ताव किया है। वीओसीपीटी ने प्रस्तावित प्रदूषण अधिभार वाली प्रशुल्क मदों के लिए कोई आधार नहीं भेजा है। वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 5.7.1 के अनुसार, जब कभी किसी सेवा/कार्गो के लिए विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध नहीं होता है तो उस पत्तन विशेष का, संबद्ध महापत्तन न्यास किसी अन्य महापत्तन न्यास में तुलनीय कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए निर्धारित प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानकों, यदि कोई हों, को अपनाते हुए नए कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए दर का प्रस्ताव कर सकता है। यदि किसी अन्य महापत्तन न्यास में कोई दर उपलब्ध नहीं है अथवा यदि उपलब्ध दर प्रस्तावित नए कार्गो/सेवा/सुविधा का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, तो पत्तन सेवा/सुविधा/उपस्कर की दरित क्षमता अथवा तकनीकी विशेषता के आधार पर अथवा 2008 के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए निर्धारित सर्वोत्तम क्षमता के संदर्भ में उक्त नए कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव दाखिल कर सकता है। यदि उपर्युक्त निर्धारित विकल्पों के आधार पर प्रशुल्क का निर्धारण संभव नहीं हो तो महापत्तन न्यास पर्याप्त कारण देने के बाद लागत जमा 16 प्रतिशत प्रतिलाभ सूत्र के आधार पर दरों का प्रस्ताव कर सकता है। इस संदर्भ में, वीओसीपीटी से अनुरोध है कि वह यह स्पष्ट करे कि किस विकल्प के अधीन धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार की दर वर्किंग दिशानिर्देशों में निर्धारित विकल्पों में से प्रस्तावित की गई है। यदि पत्तन समान मदों के लिए अन्य महापत्तन न्यास में निर्धारित दर से दर अंगीकृत करता है तो कृपया ऐसी अंगीकृत दर का संदर्भ दर्शाएं। यदि पत्तन ने लागत + 16 प्रतिशत प्रतिलाभ के आधार पर दर का प्रस्ताव किया हो तो प्रस्तावित दर के लिए विस्तृत गणना भेजे।</p>	<p>धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार पृथक सेवा नहीं है। घाट क्षेत्र की सफाई पर खर्च हुई राशि वसूल करने और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) अपेक्षाओं का अनुपालन करने का प्रयास करते हुए धूलपूर्ण कार्गो पर रु0 5/- प्रति मी.ट. की दर से प्रदूषण अधिभार का प्रस्ताव किया गया है। संग्रहीत की जाने वाली राशि राजस्व अपेक्षा में समायोजित की गई है। इसलिए, प्राधिकरण से अनुरोध है कि धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार के लिए प्रशुल्क अनुमोदित किया जाए।</p>
7.	<p>वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) (प्रपत्र सं. 1) कार्गो प्रहस्तन प्रभाग (सीएचडी):</p>	
(i).	<p>पेंशन निधि कमी का समायोजन:</p> <p>(क). वीओसीपीटी ने सीएचडी के एआरआर का अनुमान लगाते समय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः रु0 6281.76 लाख, रु0 10720.69 लाख और रु0 21136.00 लाख की राशि पेंशन निधि में ओपनिंग कमी का 1/5वां जोड़ा गया है। वीओसीपीटी द्वारा अंगीकृत दृष्टिकोण प्रशुल्क नीति 2015 और वर्किंग दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों में नहीं आता है और इसलिए इस</p>	<p>सीएचडी के मामले में, एक्ज्यूटिवल मूल्यांकन के मामले में पेंशन तथा ग्रेज्युटी निधि में भारी कमी को पूरा करने के लिए अधिशेष निधियां उपलब्ध नहीं हैं। परिणामस्वरूप, पेंशन निधि लेवी के साथ डिस्पेंस करने के लिए वर्किंग दिशानिर्देशों का खंड 2.11 के परिणामस्वरूप पेंशन तथा ग्रेज्युटी निधि में भारी कमी को पूरा करने के लिए सीएचडी पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। चूंकि सीएचडी में</p>

	<p>संबंध में प्रशुल्क नीति 2015 और वर्किंग दिशानिर्देशों से विपथन के कारणों का औचित्य बताएं।</p> <p>(ख). एआरआर परिकलन में सुविचारित उपर्युक्त आंकड़ों की विस्तृत गणनाएं और आधार बताएं।</p>	<p>कोई एस्करो निधि नहीं है, इसलिए कमी को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करना सीएचडी में संभव नहीं है (जोकि निपटान ज्ञापन दिनांक 27-7-2011 के अनुसार स्वतः पर्याप्त होगा), इसलिए संदर्भित प्रत्येक वर्ष की ओपनिंग कमी के 1/5वें को व्यय रूप में कवर करने का प्रस्ताव किया गया है।</p> <p>पेंशन निधि कमी 01-4-2011 को रु 6281.76 लाख और 1-4-2012 को रु 10720.69 लाख को क्रमशः टीएएमपी आदेशों दिनांक 11-10-2011 में बिन्दु क्रमांक 10.1.(viii) आदेश दिनांक 04-8-2014 में बिन्दु सं. 5.1 (xiv) (ड) द्वारा उपलब्ध है। 01-4-2013 को शेष जमा भेजा गया है।</p>
(ii).	<p>एकमुश्त व्ययों, यदि कोई हों, का 4/5वां, जैसे मजदूरी की बकाया राशियां, पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशियां/एक्स-ग्रेशिया भुगतान की बकाया राशियां आदि (प्रपत्र-1 का क्र.सं. 2(iii)):</p> <p>वीओसीपीटी ने एकमुश्त व्ययों जैसे मजदूरी की बकाया राशियों, पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशियों/एक्स-ग्रेशिया भुगतान की बकाया राशियों को शून्य माना है। तथापि, वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों में बताया गया है कि डब्ल्यूआरसी बकाया राशियों और एसीपी बकाया राशियां क्रमशः रु 10,90,62,275 और रु 11,65,857 वर्ष 2013-14 के लिए हैं। वीओसीपीटी से अनुरोध है कि एआरआर में ऐसे एकमुश्त व्ययों के 4/5वें पर विचार नहीं करने के कारण स्पष्ट करें। इसे लेते समय, इस परिकलन में वीओसीपीटी को वर्किंग दिशानिर्देशों के साथ निर्धारित प्रपत्र-1 में टिप्पणी 2 (ii) पर विचार करना चाहिए।</p>	<p>मजदूरी संशोधन बकाया राशियों और पेंशन बकाया राशियों का भुगतान लेखों में वर्ष 2013-14 के लिए संशोधन के प्रभाव से संबंधित है क्योंकि डब्ल्यूआरसी बकाया राशियों का रु 10,90,62,275 और एसीपी बकाया राशियों का रु 11,65,857 केवल वर्ष 2013-14 की अवधि से संबंधित है। अतः भविष्य के लिए अवलंबित एकमुश्त व्ययों के 4/5वें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि पिछला व्यय उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल नहीं है।</p>
(iii).	<p>पेंशन निधि में अंशदान (क्र.सं. प्रपत्र-1 का 2(iv))</p> <p>वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः रु 354 लाख, रु 294.98 लाख और रु शून्य का पेंशन निधि में अंशदान रिपोर्ट करते हैं। इसका 4/5वां रु 283.2 लाख, रु 235.98 लाख और शून्य होता है। इसके विपरीत, वीओसीपीटी ने वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः रु 5025.41 लाख, रु 8576.55 लाख और रु 16908.80 लाख पर विचार किया है। यह प्रत्येक वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित पेंशन निधि में अंशदान के 4/5वें से मेल नहीं खाता है। वीओसीपीटी 2013-14 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित आंकड़ों के आधार पर आंकड़े परिकलित और विचार करें।</p>	<p>पेंशन अंशदान पर विचार करने की बजाय क्र.सं. 1 ;अपद्ध द्वारा प्रपत्र-1 के अधीन, प्रासंगिक वर्ष की शुरुआत में पेंशन निधि कमी पर विचार किया गया है और इसलिए क्र.सं. 2 ;पअद्ध के अधीन भी इसके अनुसार शुरुआत में पेंशन निधि कमी का 4/5वां समायोजन के लिए सुविचारित किया गया है।</p>
(iv).	<p>राजस्व अनुमानन - सीएचडी (प्रपत्र-3):</p> <p>सीएचडी द्वारा प्रहस्तित वास्तविक कार्गो यातायात दर्शाएं। पुष्टि करें कि प्रपत्र 3 में सुविचारित 2014-15 का यातायात सीएचडी द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात है। किसी भिन्नता के मामले में, कृपया भिन्नता के कारण देते हुए समाधान करें।</p>	<p>यह पुष्टि की गई है कि 2014-15 में सीएचडी द्वारा प्रहस्तित वास्तविक कार्गो यातायात 158.80 लाख टन है और प्रपत्र-3 में भी इसपर विचार किया गया है।</p>
(v).	<p>दरमान - खंड 6.1. - कार्गो प्रहस्तन प्रभाग से कार्गो प्रहस्तन कामगारों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रभारों की वसूली</p> <p>पत्तन ने सीएचडी लेवी में 51.20 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। पत्तन परिचालनों के लिए प्रस्तावित 27.75 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध कार्गो प्रहस्तन परिचालनों के लिए सीएचडी से लेबर की आपूर्ति हेतु मौजूदा लेवी में 51.20 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य बताएं। वीओसीपीटी से अनुरोध है कि सीएचडी प्रशुल्क मदों जोकि 27.70 प्रतिशत तक पत्तन परिचालनों में प्रस्तावित सामान्य वृद्धि से उच्चतर हैं, में प्रस्तावित वृद्धि में सुधार करने की संभावना का पता</p>	<p>सीएचडी के मामले में 51.20 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि प्रपत्र-1 (सीएचडी) के अनुसार अपेक्षित वार्षिक अपेक्षा के अनुसार रु 104.54 करोड़ की वार्षिक राजस्व अपेक्षा प्राप्त करने के लिए सीएचडी के मामले में 51.20 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि 2014-15 में 158.80 लाख टन के यातायात थ्रुपुट पर विचार किया गया है जबकि 27.70 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि 324.14 लाख टनों से पीपीपी टनभार</p>

	<p>लगाए।</p>	<p>(113.46 लाख टन) के निवल 210.68 लाख टन के यातायात थ्रुपुट पर विचार करते हुए। इसलिए, वृद्धि का प्रतिशत पत्तन तथा सीएचडी के मामले में विभिन्न आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। सीएचडी को आमेलन निपटान शर्त के अनुसार पृथक स्व पर्याप्त इकाई के रूप में कार्य करना होता है।</p>
8.	<p>प्राधिकरण ने सभी महापत्तन न्यासों के लिए निम्नलिखित सामान्य अंगीकरण आदेश पारित किया था। उसके अलावा, महापत्तन न्यासों से क्र.सं. (ग) और (घ) में दिए गए हमारे पत्रों द्वारा दरमान में उपयुक्त टिप्पणी शामिल करने का भी अनुरोध किया गया था:</p> <p>(क). महापत्तन पर तटीय पोतों की वरीयता बर्थिंग पर दिशानिर्देशों से संबंधित आदेश सं. टीएमपी/52/2014-सामान्य दिनांक 28 नवम्बर 2014।</p> <p>(ख). एमओएस पत्र सं. पीडी/14033/101/2015-पीडी.वी दिनांक 3 फरवरी 2016 के अनुसरण में महापत्तन न्यासों और वहां पर परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों द्वारा नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभारों में विशेष छूट एवं कार्गो तथा पोत संबंधित सेवाओं के लिए निम्नतर प्रभारों के निर्धारण से संबंधित आदेश सं. टीएमपी/14/2016-विविध दिनांक 9 फरवरी 2016।</p> <p>(ग). इस तरह से रक्षा भंडारों के लिए घाटशुल्क दरों की अनुप्रयोजनीयता के संबंध में उनके तत्संबंधी दरमान में उपयुक्त टिप्पणी निर्धारित करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों को यह निदेश देने वाला पत्र सं. टीएमपी/35/2013-विविध दिनांक 7 अगस्त 2014 कि निर्धारित दरों को लागू करने पर उपयोक्ताओं के दिमाग में कोई विसंगति नहीं आए।</p> <p>(घ). आयात सामान्य विनिहित (आईजीएम) अथवा निर्यात सामान्य विनिहित (ईजीएम) में कार्गो रूप में विनिहित पोत पर घाटशुल्क प्रभारों संबंधी टीएमपी पत्र सं. टीएमपी/53/2002-विविध दिनांक 25 मार्च 2015 का अनुसरण करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों को निदेश देने वाला एमओएस का पत्र सं. पीडी-25021/7/2015-पीडी.1 दिनांक 16 अप्रैल 2015।</p> <p>(ङ) तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए रियायती प्रभारों की वसूली से संबंधित स्पष्टीकरण आदेश सं. टीएमपी/53/2015-बीओसीपीटी दिनांक 10 जून 2016।</p> <p>तथापि, यह देखा गया है कि पत्तन ने प्रस्तावित दरमान में उपर्युक्त सामान्य अंगीकरण आदेशों/पत्र में निर्धारित प्रावधानों को शामिल नहीं किया है। पत्तन से अनुरोध है कि मसौदा प्रस्तावित दरमान में इसे शामिल करे। राजस्व अनुमानों पर प्रभाव, यदि कोई हो, को प्रपत्र-3 में लिया जाए।</p>	<p>सभी सामान्य आदेशों के अधीन शामिल प्रावधान सामान्य संशोधन प्रस्ताव के जमा करने में सुविचारित किए गए हैं और शामिल वित्तीय विवीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है।</p>
9.	<p>अतिरिक्त अधिशेष का समायोजन:</p> <p>प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 4.1 के अनुसार, (क) पूर्व प्रशुल्क आदेशों में टीएमपी द्वारा मूल्यांकित अतिरिक्त अधिशेष जो असामयोजित रह गया था, को पत्तन न्यास की इच्छा के अनुसार किसी निधि में महापत्तन न्यासों द्वारा अंतरित किया जाएगा। (ख) इस नीति के अधीन निर्धारित नए दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक मौजूदा दरमानों के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान महापत्तन न्यासों को प्रोद्भूत अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, मूल्यांकित किया जाना चाहिए और सामान्य आरक्षित में अंतरित किया जाना चाहिए और पत्तन अवसंरचना सुविधाओं के विकास, सृजन और/अथवा आधुनिकीकरण के लिए निधियों का उपयोग किया जाना चाहिए।</p>	<p>(ख) के संबंध में, क्योंकि वर्तमान दरमान प्रस्तावित दरमान से 21.20 प्रतिशत तक कम है, संशोधित दरों के संशोधन तक मौजूदा प्रशुल्क के विस्तार की वजह से अतिरिक्त प्रोद्भूत का कोई प्रोद्भूत नहीं होगा।</p>

	उपर्युक्त (क) के संबंध में, यह देखा गया है कि वीओसीपीटी के मामले में कोई पूर्व अवधि असमायोजित अधिशेष नहीं है। उपर्युक्त (ख) के संबंध में, वीओसीपीटी से अनुरोध है कि उक्त प्रशुल्क नीति के खंड 4.1 के अधीन यथा अपेक्षित अतिरिक्त अधिशेष का निर्धारण करे और सूचनार्थ भेजे।	
10.	कार्यनिष्पादन मानक	
(i).	वीओसीपीटी ने प्रपत्र-6 में कार्यनिष्पादन मानकों का प्रस्ताव किया है। वीओसीपीटी से अनुरोध है कि प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानकों का आधार स्पष्ट करें।	नई बर्थिंग नीति के मद्देनजर इसे वापिस लिया गया है।
(ii).	प्रशुल्क नीति 2015 का खंड 3.2 विनिर्दिष्ट करता है कि खंड 2.8 में यथा उपलब्ध करवाया गया एसओआर का सूचकांकन महापत्तन न्यासों द्वारा प्रतिबद्ध कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन होगा। यदि पत्तन विशेष कार्यनिष्पादन मानक को पूरा नहीं करता है तो अगले वर्ष के दौरान सूचकांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः वीओसीपीटी खंड 3.2 में विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार सूचकांकन पर दरमान में उपयुक्त खंड शामिल करे।	हाँ। मसौदा दरमान में उपयुक्ततः शामिल किया गया प्रासंगिक खंड भेजा गया है।

10.2. अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजते समय, वीओसीपीटी ने हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पर विधिवत् विचार करते हुए मसौदा दरमान में मामूली संशोधन भी किया था। वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित मसौदा दरमान दिनांक 9 अगस्त 2016 में मुख्य संशोधनों में से कुछ नीचे दिए गए हैं:-

- (i). पत्तन ने नौप्रस्थान पोतों के लिए पत्तन देयताओं का प्रस्ताव किया है जिसे पूर्ववर्ती प्रस्तावित दरमान में हटाया गया बताया गया था।
- (ii). पत्तन ने पाइलटज शुल्क की मौजूदा परिभाषा को बनाए रखा है।
- (iii). पत्तन ने बताया है कि उसने प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों के लिए प्रस्ताव में पत्तन द्वारा पहले प्रस्तावित परिचालन व्यय की 25 प्रतिशत सीमा के अलावा कार्गो ग्रहस्तन सेवाओं तथा पत्तन एवं गोदी सुविधा से संबंधित पत्तन सुरक्षा, कल्याण तथा चिकित्सा के हिस्से के रु० 19.21 करोड़ के औसत व्यय का दाखिल करने का प्रस्ताव किया है। उक्त व्यय के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
1	पत्तन सुरक्षा	646.48	806.28	1087.24
2	लेबर कल्याण और चिकित्सा व्यय	1174.87	981.60	1066.64
3	कुल	1821.35	1787.88	2153.88
औसत व्यय		1921.03		

- (iv). कार्यनिष्पादन मानक:
पत्तन ने संशोधित कार्यनिष्पादन मानकों का प्रस्ताव किया है जो नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	कार्यनिष्पादन पैरामीटर	अर्जित कार्यनिष्पादन 2015-16	प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक (2016-17)
1	कार्गो संबंधित सेवाएं		
क)	औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट (टनों में)		
(i).	कंटेनर	21,018	21,500
(ii).	ब्रेक बल्क	2,113	2,120
(iii).	शुष्क बल्क - मेक	13,187	13,500
(iv).	शुष्क बल्क - कॉन	10,331	10,400
(v).	लिविड बल्क	3,829	3,830
	समग्र	10,239	10,500
ख)	कंटेनर के मामले में औसत फेरे प्रति घंटा (टीईयू में)	21	21
2	पोत संबंधित सेवाएं		
क)	पोतों का औसत टीआरटी (दिनों में) (पत्तन + गैर-पत्तन लेखा)		
(i).	कंटेनर	1.35	1.30
(ii).	ब्रेक बल्क	5.33	5.30
(iii).	शुष्क बल्क - मेक	5.13	5.10
(iv).	शुष्क बल्क - कॉन	6.48	6.40
(v).	लिविड बल्क	2.96	2.90
	समग्र	3.73	3.30
ख)	पोतों का औसत पीबीडी (दिनों में) (पत्तन + गैर-पत्तन लेखा)		
(i).	कंटेनर	0.28	0.25
(ii).	ब्रेक बल्क	2.21	2.20

(iii).	शुष्क बल्क — मेक		1.41	1.40
(iv).	शुष्क बल्क — कॉन		3.00	2.90
(v).	लिविविड बल्क		0.98	0.90
	समग्र		1.41	1.40
3	पत्तन द्वारा प्रासगिक पाए गए कोई अन्य पैरामीटर			
(i).	सकल उत्पादकता (सकल/मी.ट./दिन)	कोयला — अभियंत्रित सीजेआई एवं सीजेआईआई में	12,030	12,630
(ii).		कोयला — परंपरागत बर्थ 9 में	23,305	24,470
(iii).		कोयला — परंपरागत बर्थ 3 एवं 4 में	10,551	11,606
(iv).	निकासी यार्ड थ्रुपुट (मी. ट. प्रति वर्ग मी.)	कोयला — परंपरागत	15.35	16.00
(v).	डीबीजीटी के साथ अल्पावधि अनुबंध (एमएमटी/वर्ष)	कॉपर संकेंद्रित बर्थ 8 में प्रहस्तित	0.18	0.30
4	बर्थ में निष्क्रिय समय का %			
(i).	कंटेनर		0.00	0.00
(ii).	ब्रेक बल्क		32.35	31.40
(iii).	शुष्क बल्क — मेक		13.34	12.95
(iv).	शुष्क बल्क — कॉन		27.16	26.35
(v).	लिविविड बल्क		23.14	22.45
	समग्र		20.84	20.21

10.3. तत्पश्चात, वीओसीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 26 अगस्त 2016 द्वारा स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित दरमान में सीमाशुल्क दस्तावेज में निर्धारित किसी नाम से कोयले हेतु घाटशुल्क दर और जोन-क में तटीय के लिए ताप बिजली संयंत्रों के लिए प्रयुक्त को रु0 29.12/टन की बजाय रु0 48.53/टन पढ़ा जाए और वीओसीपीटी ने धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार की प्रस्तावित वसूली को शामिल करने का भी अनुरोध किया था क्योंकि जिसके अधीन हालांकि प्रस्ताव में प्रस्तावित को प्रस्तावित दरमान में शामिल नहीं किया गया है:

“अनुसूची 3.5 : प्रदूषण कम करने के उपायों हेतु अधिभार।

प्रदूषण कम करने के उपायों के लिए अधिभार पत्तन में उतारे गए धूलपूर्ण कार्गो के मामले में रु0 5/- प्रति मी.ट. पर वसूल किया जाएगा (बन्द कन्वेंयर्सों के माध्यम से प्रहस्तित कार्गो के अलावा)।”

11.1. ऊपर बताया गया संयुक्त सुनवाई में निर्णीत कार्रवाई के दूसरे बिन्दु के संदर्भ में, वीओसीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 9 अगस्त 2016 द्वारा उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भेजी थीं।

11.2. ऊपर उल्लिखित संयुक्त सुनवाई में निर्णीत तीसरे कार्रवाई बिन्दु के संदर्भ में, वीओसीपीटी ने कोयला जेट्टी-1 और 2 में प्रहस्तित कोयले के लिए प्रदूषण अधिभार लागू करने के संबंध में स्पष्ट किया है कि चूंकि कोयला बन्द कन्वेंयर प्रणाली में कोयला जेट्टी-1 और 2 में प्रहस्तित किया जा रहा है, इसलिए उक्त प्रदूषण अधिभार लागू नहीं होगा और इसलिए प्रस्तावित दरमान में उपयुक्त संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

11.3. ऊपर उल्लिखित संयुक्त सुनवाई में निर्णीत चौथे कार्रवाई बिन्दु के संदर्भ में, वीओसीपीटी ने बताया है कि जहां तक उत्पादकता मानकों का संबंध है, उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों के साथ परामर्श से मंत्रालय के निदेशों के अनुसार उत्पादकता मानकों को अंतिम रूप देने की कार्रवाई की जा रही है और इसलिए पहले से जमा किए गए और पत्तन वेबसाइट पर अपलोड किए गए उत्पादकता मानकों पर अंतिम रूप दिए जाने तक विचार किया जाए।

11.4. ऊपर उल्लिखित संयुक्त सुनवाई में निर्णीत पांचवें कार्रवाई बिन्दु के संदर्भ में, वीओसीपीटी का प्रस्ताव पहले ही बताया गया है।

वीओसीपीटी ने अनुरोध किया है कि रु0 1921.03 लाख की राशि को उपयुक्ततः शामिल किया जाए। हालांकि प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन के अधीन उपर्युक्त व्यय पर विचार करने के बाद वृद्धि की संशोधित दर 36.69 प्रतिशत होती है, पत्तन ने केवल 27.70 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि पर विचार करने तथा अनुमोदित करने का अनुरोध किया है जैसाकि इसके पत्र दिनांक 7 मई 2016 द्वारा पहले प्रस्तावित किया गया था। पत्तन ने बताया है कि आगामी बोर्ड बैठक में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

12.1. जैसाकि पहले बताया गया है, इस प्राधिकरण ने मौजूदा दरमान में निर्धारित पेंशन निधि लेवी को 31 अगस्त 2016 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, सहित वीओसीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करते हुए वीओसीपीटी के अनुरोध के आधार पर एक आदेश दिनांक 19 मई 2016 पारित किया था।

12.2. इस संबंध में, टीएनजीईडीसीओ ने अपने पत्र सं. सीई/कोल/एसई/ई2/ए4/एफ.टीएमपी/डी.18/2016 दिनांक 27 मई 2016 द्वारा इस प्राधिकरण से मामले में हस्तक्षेप करने और वीओसीपीटी को 1 अप्रैल 2016 से 6.5 प्रतिशत की दर से पेंशन निधि लेवी वसूल करने पर जोर नहीं देने का निर्देश देने का अनुरोध किया था क्योंकि इस प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना विस्तार के लिए प्रस्ताव के आधार पर पेंशन निधि लेवी संग्रहीत करने का कोई प्राधिकार नहीं है। इसके अलावा, टीएनजीईडीसीओ ने प्रस्ताव पर कोई आदेश पारित करने से पहले वीओसीपीटी द्वारा पेंशन निधि लेवी के विस्तार के लिए प्रस्ताव पर उनके विचार प्राप्त करने का अनुरोध किया था।

13. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

14. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित बिन्दु प्रकट होते हैं:-

- (i). वीओसीपीटी का दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार अगस्त 2014 में संशोधित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 4 अगस्त 2014 द्वारा अनुमोदित वीओसीपीटी के दरमान की वैधता 31 मार्च 2016 तक है। उक्त आदेश में, अनुमानित लागत स्थिति के आधार पर, इस प्राधिकरण ने वीओसीपीटी के तत्कालीन मौजूदा दरमान में यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया था और निकर्षण के लिए विशेष दर को समाप्त कर दिया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा 6.5 प्रतिशत की पेंशन निधि लेवी अनुमोदित की गई थी जिसे 1 अप्रैल 2016 से लागू करने से रोक दिया गया था। इस संबंध में, कार्गो प्रहस्तन प्रभाग (सीएचडी) से लेबर की तैनाती के लिए लेवी, अन्य मुख्य पूल कार्गो, कोयला जेट्टी 2 में कोयला तथा नमक के लिए क्रमशः 167 प्रतिशत, 223 प्रतिशत और 207 प्रतिशत की वृद्धि अनुमोदित की गई थी। सीएचडी के लिए पेंशन निधि लेवी रु० 25.10 प्रति टन की दर से अनुमोदित की गई थी।

वीओसीपीटी ने प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए 7 मई 2016 को अपना प्रस्ताव दाखिल किया था।

जैसाकि तथ्यात्मक स्थिति बताते हुए पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है, वीओसीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 मई 2016 द्वारा दाखिल किए गए मसौदा प्रस्तावित दरमान में, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) का पूर्व निर्देश दिनांक 17 सितम्बर 2015 जिसके आधार पर इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 5 अक्टूबर 2015 पारित किया था, पर विचार किया गया था। उक्त आदेश के अनुसार, वीओसीपीटी ने, तटीय दर के लिए दर के प्रति एक टिप्पणी प्रस्तावित की थी कि तटीय पोत के लिए दर विनिमय दर उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए परिगणित विदेशगामी पोत के लिए (जूटापोस्ट दर के) 60 प्रतिशत तक भारतीय रूपयों में वसूल की जाएगी। तत्पश्चात, एमओएस ने अपने पत्र दिनांक 11 मई 2016 द्वारा, इस प्राधिकरण को अपना पूर्ववर्ती निर्देश दिनांक 17 सितम्बर 2015 आस्थगित रखने का निर्देश दिया था और एमओएस के 1/3 जनवरी 2015 और 9 मार्च 2005 के निर्देश को बहाल किया था। एमओएस के उक्त निर्देश के अनुसरण में, इस प्राधिकरण ने आस्थगित आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2015 को बनाए रखने के लिए एक आदेश दिनांक 19 मई 2016 पारित किया था। इस बारे में ध्यान दिलाये जाने पर, वीओसीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 जुलाई 2016 द्वारा आदेश दिनांक 19 मई 2016 और संशोधित कार्यनिष्पादन मानकों के अनुसार तटीय पोत के लिए विशिष्ट दर प्रस्तावित करते हुए संशोधित प्रस्तावित दरमान भेजा था।

जैसाकि पूर्व अनुच्छेदों में बताया गया है, वीओसीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 13 जुलाई 2016 द्वारा अनुरोध किया गया था कि अपने प्रस्ताव के संदर्भ में सूचना/स्पष्टीकरण 20 जुलाई 2016 तक भेजें। नियमित फॉलो अप करने के बाद, पत्तन ने संशोधित मसौदा दरमान और संशोधित कार्यनिष्पादन मानक के साथ अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण अपने पत्र दिनांक 9 अगस्त 2016 द्वारा भेजे थे। मामले की कार्यवाही के दौरान पत्तन द्वारा किए गए निवेदनों और संशोधित प्रस्तावित दरमान के साथ वीओसीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 9 अगस्त 2016 द्वारा प्रेषित सूचना/स्पष्टीकरण इस विश्लेषण में सुविचारित किए गए हैं। इस मामले को अंतिम रूप पत्तन से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही दिया जाएगा।

- (ii). (क). प्रशुल्क नीति 2015 का खंड 2.1 प्रत्येक महापत्तन न्यास से अपेक्षा करता है कि वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का मूल्यांकन करें जोकि प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.2. में यथा निर्धारित कुछ अतिरिक्तों और इस प्राधिकरण द्वारा जारी वर्किंग दिशानिर्देशों जमा प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत तथा प्रबंधन लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित 31 मार्च 2014 को प्राप्त करते हुए पूंजी प्रगतिधीन सहित नियोजित पूंजी पर 16 प्रतिशत से प्रतिलाभ के अधीन तीन वर्षों 2011-12 (वर्ष 1), 2012-13 (वर्ष 2) और 2013-14 (वर्ष 3) के अंतिम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय का औसत है।

- (ख). वीओसीपीटी ने प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित तीन वर्षों अर्थात् 2011-12 (वर्ष 1), 2012-13 (वर्ष 2) और 2013-14 (वर्ष 3) के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) मूल्यांकित किया है। वीओसीपीटी ने वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए औसत वार्षिक व्ययों पर पहुंचने के लिए एआरआर परिकलन में अस्वीकार्य व्ययों को अलग रखा है। प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.2. और वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.2. में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वीओसीपीटी द्वारा किए गए निम्नलिखित समायोजन स्पष्ट किए गए कारणों से एआरआर परिकलन किए जाने के लिए अपेक्षित कुछ संशोधन के साथ विशिष्ट उल्लेख के लिए दिए गए हैं:-

- (i). प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.2. (ii) और वर्किंग दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋण पर ब्याज को अलग रखा जाना है। वीओसीपीटी ने ऋण पर ब्याज के लिए किसी राशि पर विचार भी नहीं किया है। तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को देखने पर, यह देखा गया है कि ऋण पर ब्याज शून्य है। इसलिए वीओसीपीटी द्वारा दिया गया संव्यवहार सही पाया गया है।

- (ii). (क). प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.2. (iii) और वर्किंग दिशानिर्देशों के अनुसार, मजदूरी संशोधन की वजह से एकमुश्त व्ययों जैसे मजदूरी, पेंशन/ग्रेच्युटी, एक्स-ग्रेशिया भुगतानों के 1/5 को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) में शामिल किया जाना है। इसी प्रकार, पेंशन निधि में अंशदान का 1/5वां एआरआर की गणना के लिए शामिल किया जाना है। इसका अर्थ है उपर्युक्त व्ययों का 4/5वां एआरआर परिकलन में अलग रखा जाना है।

- (ख). पत्तन ने एकमुश्त व्ययों जैसे मजदूरी, पेंशन/ग्रेच्युटी, एक्स-ग्रेशिया भुगतान की बकाया राशियों के लिए शून्य आंकड़े दर्शाए हैं। पत्तन ने पुष्टि की है कि उपर्युक्त लेखों पर एकमुश्त भुगतान नहीं है। स्थिति पर विश्वास किया गया है।
- (ग). पत्तन ने पेंशन निधि में अंशदान के 4/5वें रूप में वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः ₹0 1300.97 लाख, 640 लाख और 1720 लाख अलग रखे हैं। पत्तन ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के प्रत्येक वर्ष के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित आंकड़ों से आंकड़ों का मिलान किया है। पत्तन द्वारा प्रेषित मिलान विवरण से यह देखा गया है कि पत्तन के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित आंकड़े पेंशन निधि में अंशदान और ग्रेच्युटी निधि के लिए हैं। पत्तन ने निधियों में इन दोनों अंशदान के लिए ब्रेकअप दिया है और प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.2 (iii) के अनुसार यथा अपेक्षित अलग रखने के लिए पेंशन निधि में अंशदान के 4/5वें पर विचार किया है।
- (iii). प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.2. (iv) और वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.2 के अनुसार, प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन उपरिव्यय (एमजीएओ), प्रचालन व्यय तथा मूल्यहास के जोड़ के 25 प्रतिशत की सीमा के अधीन, एआरआर गणना में सुविचारित किया जाना है।
लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित एमजीएओ वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः ₹0 5221.51 लाख, ₹0 5729.93 लाख और ₹0 6816.73 लाख है।
प्रपत्र 1 में, स्वीकार्य एमजीएओ पर पहुंचने के लिए, वीओसीपीटी ने वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः ₹0 14302.93 लाख, ₹0 15348.73 लाख तथा ₹0 17296.09 लाख के परिचालन व्यय तथा प्रबंधन एवं सामान्य उपरिव्यय के जोड़ पर विचार किया है। उससे संपादा के परिचालन व्यय को अलग रखने के बाद, वीओसीपीटी ने आखिरकार ₹0 3416.67 लाख, ₹0 3721.22 लाख और ₹0 3979.57 लाख की एमजीएओ सीमा पर पहुंचने के लिए वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः ₹0 13669.69 लाख, ₹0 14884.87 लाख और ₹0 15918.26 लाख पर 25 प्रतिशत निर्धारित किया है। चूंकि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार प्रतिवेदित एमजीएओ 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक है, इसलिए वीओसीपीटी ने एआरआर निर्धारण के समय कुल व्यय से अतिरिक्त के ₹0 1 में वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः ₹0 1804.84 लाख, ₹0 2008.71 लाख और ₹0 2837.17 लाख पर विचार किया है।
पत्तन ने मामले की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट किया था कि कुछ व्ययों जैसे सीआईएसएफ व्यय, जांच संबंधी व्यय, आईटी संबंधित व्यय एमजीएओ के अधीन लिए गए हैं और इसलिए 25 प्रतिशत सीमा से अधिक एमजीएओ के परिकलन की पुनः जांच की जाएगी। तत्पश्चात, पत्तन ने एमजीएओ के अधीन प्रतिवेदित पत्तन सुरक्षा तथा लेबर कल्याण व्यय तथा चिकित्सा व्यय की राशि भेजी है जोकि कार्गो प्रहस्तन सेवाओं तथा पत्तन एवं गोदी सुविधा से संबंधित ₹0 1821.35 लाख, ₹0 1787.88 लाख और ₹0 2153.88 लाख है। वीओसीपीटी ने इस प्राधिकरण से एमजीएओ के लिए परिचालन व्यय की 25 प्रतिशत सीमा पर पहुंचने के समय इसके कोगनिजेंस को लेने का अनुरोध किया था। वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के मददेनजर, उपर्युक्त व्यय जोकि कार्गो तथा पोत संबंधित गतिविधि से संबंधित बताए गए हैं, एमजीएओ से अलग रखे गए हैं और प्रपत्र 2 में परिचालन व्यय में जोड़े गए हैं। यह कार्यवाही वीओसीपीटी द्वारा किए गए निवेदनों के मददेनजर एमजीएओ की स्वीकार्य सीमा पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए ही की गई है कि कार्गो त्ति पोत संबंधित गतिविधि से संबंधित व्ययों के दो शीर्ष एमजीएओ में लिए गए हैं। यह बताना प्रासंगिक होगा कि इसी तरह का समायोजन एनएमपीटी द्वारा भी किया गया था जिसे इस प्राधिकरण द्वारा एनएमपीटी का दरमान संशोधित करते समय स्वीकार किया गया था।
उपर्युक्त विश्लेषण के अधीन, परिचालन व्ययों के 25 प्रतिशत की दर से एमजीएओ पर सीमा वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः ₹0 2566.63 लाख ₹0 2735.71 लाख और ₹0 2813.85 लाख परिगणित होता है। चूंकि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार प्रतिवेदित एमजीए 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक है, इसलिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक अर्थात् वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः ₹0 833.53 लाख, ₹0 1206.35 लाख और ₹0 1849.00 लाख को एआरआर के परिकलन के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कुल व्ययों से अलग रखा गया है।
- (iv). इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.2(v) के अनुसार, केपटिव बर्थों के लिए प्रासंगिक सभी व्यय एआरआर के परिकलन से अलग रखे गए हैं। वीओसीपीटी ने केपटिव बर्थों के लिए क्रमशः वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः ₹0 58.54 लाख, ₹0 58.83 लाख और ₹0 76.05 लाख के मूल्यहास को अलग रखा है। तथापि, पत्तन ने केपटिव बर्थ के लिए प्रचालन व्ययों, आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासन उपरिव्यय (एमएओ) और आबंटित वित्त एवं प्रबंधन व्यय (एफएमई) के किसी अतिरिक्त को नहीं दर्शाया था। वीओसीपीटी ने स्पष्ट किया है कि पत्तन ने तत्संबंधी बर्थों से संबंधित मूल्यहास के सिवाय बीओटी परिचालकों द्वारा परिचालित केपटिव बर्थों से संबंधित कोई प्रत्यक्ष परिचालन व्यय और वित्त एवं विविध व्यय मदों को प्रोद्भूत नहीं किया है। इसलिए, पत्तन ने केपटिव बर्थों के लिए प्रचालन व्ययों, आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासन उपरिव्यय (एमएओ) और आबंटित वित्त एवं प्रबंधन व्यय (एफएमई) के किसी अतिरिक्त को नहीं दर्शाया था। वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर विश्वास किया गया है।
- (iii). प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.3 और वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.3 में निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए औसत व्ययों की मात्रा वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित ₹0 15500.46 लाख के स्थान पर ₹0 16421.08 लाख निर्धारित किया गया है।
- (iv). नियोजित पूंजी के परिकलन के लिए वर्किंग दिशानिर्देश 2015 के खंड 2.4 के अनुसार, पत्तन ने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को बीओटी परिचालकों को हस्तांतरित संपदा गतिविधि और निवल अचल परिसंपत्तियों से संबंधित अचल परिसंपत्ति के निवल मूल्य को अलग रखना है। वीओसीपीटी 31 मार्च 2014 को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर नियोजित पूंजी आंकड़े ₹0 93,250.18 लाख पर पहुंचा है जिसमें निवल अचल परिसंपत्तियों के लिए ₹0 88,644.92 लाख + प्रगतिधीन के मूल्य के लिए ₹0 9,980.39 लाख + कार्य पूंजी के लिए ₹0 2020.35 लाख - संपदा गतिविधि से संबंधित निवल अचल परिसंपत्तियों के लिए ₹0 650.69 लाख - बर्थ सं. 7, 8 और केपटिव बर्थ नार्थ कार्गो बर्थ

(एनसीबी)-1 के मामले में बीओटी परिचालकों को हस्तांतरित अचल परिसंपत्ति के निवल मूल्य संबंधी रु 6,744.79 लाख शामिल है। इस संबंध में, वीओसीपीटी द्वारा एनसीबी-1 के लिए रु 1,732.05 लाख को अलग रखा गया है, यह बताना प्रासंगिक है कि इस बर्ध के लिए अप्रकृत प्रशुल्क के निर्धारण के दौरान, पत्तन द्वारा यह समझ लिया गया था कि एनसीबी-1 एमओएस द्वारा पत्र सं. पीडी-11015/5/2006-टीपीटी दिनांक 22 अक्टूबर 2009 की मंजूरी के अनुसार जमा शर्तों पर वीओसीपीटी द्वारा निर्माण किया गया था। जब इस मद को अलग रखने की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था तो वीओसीपीटी ने स्पष्ट किया था कि यह अतिरिक्त करना एनसीबी-1 के परिचालन के लिए पत्तन द्वारा विकसित बर्ध क्षेत्र के चारों ओर सड़क तथा बिजली के संबंध में सामान्य उपयोग के लिए व्यय से संबंधित है और बर्ध से संबंधित नहीं है। पत्तन ने पुष्टि की है कि इसे अलग रखना सही है। कार्यगत पूंजी में वस्तुसूची, विविध देनदारियां और रोकड़ जमाशेष शामिल हैं। वीओसीपीटी ने वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.5 में निर्धारित प्रतिमानक के अनुसार कार्यगत पूंजी रु 2,020.35 लाख का परिकलन किया था। वीओसीपीटी द्वारा यथा प्रेषित नियोजित पूंजी पर विश्वास तथा विचार किया गया है।

(v). वीओसीपीटी द्वारा निर्धारित नियोजित कुल पूंजी रु 93,250.18 लाख है। 16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाम रु 14,920.03 लाख है जो एआरआर परिकलन में सुविचारित किया गया है।

(vi). वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित एआरआर तीन वित्तीय वर्षों 2011-12 से 2013-14 के लिए व्यय का औसत जमा 16 प्रतिशत आरओसीई रु 14,920.03 लाख 31 मार्च 2014 को सकल रु 30,420.09 करोड़ है। इसके अलावा, वीओसीपीटी ने वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.7 के अनुसार वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए क्रमशः 6 प्रतिशत और 3.82 प्रतिशत पर लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से उक्त एआरआर सूचकांकित किया था और वर्ष 2015-16 के लिए रु 33,477.51 लाख पर एआरआर अग्रेषित करते हुए अधिकतम सूचकांकित एआरआर पर पहुंचा था। अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा रु 33,477.51 लाख से, वीओसीपीटी ने 31-3-2014 को एस्क्रो खाता जमाशेष होते हुए रु 5637.03 लाख के समायोजन (कटौती) को दर्शाया है और रु 27840.48 लाख के समायोजित अधिकतम एआरआर पर पहुंचा है तथा रु 27840.48 लाख पर मसौदा प्रस्तावित दरमान में अनुमानित राजस्व से मिलान किया था।

प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 4.2 और वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.11 में बताया गया है कि महापत्तन न्यास द्वारा व्यवस्थित एस्क्रो खातों में जमाशेष संबद्ध महापत्तन न्यासों के न्यासी बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रशुल्क नीति, 2015 और वर्किंग दिशानिर्देश महापत्तन न्यासों से यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि एआरआर के विरुद्ध शेष एस्क्रो खातों का समायोजन किया जाए। एआरआर अधिकतम स्तर है और पत्तन के पास अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित दरमान तैयार करने का अधिकार है। जब इस स्थिति के बारे में ध्यानाकर्षित किया गया था तो वीओसीपीटी ने स्पष्ट किया था कि चूंकि वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.11 में दिया गया है कि महापत्तन न्यास द्वारा व्यवस्थित एस्क्रो खातों में जमाशेष संबद्ध महापत्तन न्यासों के न्यासी बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है, पत्तन ने सूचकांकित एआरआर से रु 5637.03 लाख की कटौती दर्शाई है।

यह बताना प्रासंगिक है कि अन्य पत्तन न्यासों अर्थात् न्यू मैंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी), कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी), विशाखापत्तन पत्तन न्यास (वीपीटी), कांडला पत्तन न्यास (केपीटी), मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) जिन्होंने प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन प्रस्ताव दाखिल किया है, में से किसी ने भी ऐसा समायोजन प्रस्तावित नहीं किया है। प्रशुल्क नीति, 2015 महापत्तन न्यासों से यह अपेक्षा नहीं करती है कि एआरआर के विरुद्ध एस्क्रो खातों के जमाशेष का समायोजन किया जाए। एआरआर अधिकतम स्तर है और पत्तन के पास अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित दरमान तैयार करने का अधिकार है। इसलिए, एआरआर से कटौती रूप में एस्क्रो खाता जमाशेष पर विचार करने का यह समायोजन हमारे द्वारा तैयार किए गए संशोधित एआरआर परिकलन में नहीं दर्शाया जा रहा है। एआरआर में इस समायोजन को नहीं दर्शाने का यह मतलब नहीं है कि पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत एस्क्रो जमाशेष में निधियों का उपयोग करने के लिए प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन उनके पास ऐसा करने का अधिकार है।

(vii). उपर्युक्त संशोधन के अधीन, वीओसीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 मई 2016 द्वारा प्रेषित एआरआर गणना जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है, पर विश्वास किया गया है। वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित और इस प्राधिकरण द्वारा यथा सुविचारित अधिकतम सूचकांकित एआरआर का सार उपर्युक्त विश्लेषण में स्पष्ट किए गए संशोधन के अधीन नीचे दी गई है:-

(राशि रु लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वीओसीपीटी द्वारा यथा अनुमानित	इस प्राधिकरण द्वारा यथा सुविचारित
1.	वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए औसत व्यय	15,500.46	16421.08
2.	31-3-2014 को निवल अचल परिसंपत्ति, प्रगतिधीन पूंजी सहित नियोजित पूंजी और प्रतिमानकों के अनुसार कार्यगत पूंजी	93,250.18	93,250.18
3.	16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाम	14,920.03	14,920.03
4.	31 मार्च 2014 को एआरआर (4=1+3)	30,420.49	31,341.11
5.	वर्ष 2014-15 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन (6%)	32,245.72	33,221.58
6.	वर्ष 2015-16 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन (3.82%)	33,477.51	34,490.64
7.	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	33,477.51	34,490.64
8.	प्रस्तावित दरमान में वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित राजस्व	27,840.48	27,840.48

(viii). प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.6 के अनुसार, महापत्तन न्यास वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बाजार की ताकतों को प्रतिसाद देने के लिए दरें निर्धारित कर सकता है और प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित सूचकांकित एआरआर की अधिकतम सीमा के भीतर दरमान

तैयार कर सकता है। पत्तन ने पोत संबंधित प्रमारों, कार्गो संबंधित प्रमारों तथा विविध प्रमारों के लिए सभी प्रशुल्क मदों में 27.70 प्रतिशत की एकसमान वृद्धि प्रस्तावित की है। 6.5 प्रतिशत पेंशन निधि लेवी डिस्पेंस की गई है। पेंशन निधि लेवी डिस्पेंस करने के बाद, निवल वृद्धि केवल 21.20 प्रतिशत है।

यह देखा गया है कि पत्तन ने प्रस्तावित दरमान पर राजस्व का अनुमान लगाने के समय वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित राजस्व पर विचार किया था और प्रस्तावित दरमान पर अनुमानित राजस्व पर पहुंचने के लिए 27.7 प्रतिशत की प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि द्वारा वृद्धि की गई है। पत्तन ने सीमाशुल्क दस्तावेजों में वर्णित किसी भी नाम द्वारा कोयला कार्गो के लिए एकसमान घाटशुल्क दर प्रस्तावित की है। इसके अलावा पत्तन ने रु 5/टन की दर से धूलपूर्ण कार्गो पर नया प्रदूषण अधिभार प्रस्तावित किया है। पत्तनने मौजूदा शर्तों में कुछ संशोधन का भी प्रस्ताव किया है और नई शर्तों का भी प्रस्ताव किया है जिनपर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

राजस्व अनुमानित करने के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार, वीओसीपीटी से यह अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2014-15 में पत्तन द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात के लिए प्रस्तावित दर पर प्रत्येक प्रशुल्क मदों अर्थात् कार्गो, पोत तथा विविध सेवाएं के लिए राजस्व का अनुमान लगाए। वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.9 के अनुसार यथा अपेक्षित वर्ष 2014-15 में प्रहस्तित तदनुसूची यातायात के लिए प्रस्तावित दरमान में प्रत्येक प्रशुल्क मद दर्शाते हुए राजस्व अनुमान की विस्तृत गणना भेजने का अनुरोध करने के बावजूद, वीओसीपीटी ने अपने निर्णय को बनाये रखा है कि 2014-15 के वास्तविक अर्जन आधार रूप में उपयोग किए जाते हैं और मौजूदा दरमान पर प्रस्तावित प्रशुल्क पर राजस्व अनुमान पर पहुंचने के लिए उसपर लागू प्रस्तावित वृद्धि परिकलित की गई है। पत्तन ने पुष्टि की है कि पोत संबंधित प्रमारों के लिए राजस्व अनुमानों में सुविचारित कुल जीआरटी पोत वर्ष 2014-15 के लिए पत्तन द्वारा प्रहस्तित पोत के वास्तविक कुल जीआरटी से मेल खाता है। पत्तन ने यह भी पुष्टि की है कि राजस्व अनुमानों में सुविचारित कार्गो की मात्रा वास्तविक प्रहस्तित कार्गो से मेल खाता है और पीपीपी परिचालक अर्थात् बर्थ 7 और बर्थ 8 कंटेनर टर्मिनल तथा एनसीबी 1 के माध्यम से प्रहस्तित टनभार के वर्ष 2014-15 निवल में प्रतिवेदित किया गया है। धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार के लिए रु 5 प्रति टन की दर से प्रस्तावित नई प्रशुल्क मद के संबंध में, वीओसीपीटी ने राजस्व अनुमानों में रु 542.72 लाख के राजस्व अनुमान को लिया है।

पत्तन से मांगी गई सूचना को तालिकाबद्ध करते हुए पूर्ववर्ती अनुच्छेद कुछ प्रशुल्क मदें सूचीबद्ध करते हैं जिसके लिए प्रस्तावित दरमानों पर राजस्व अनुमानित किया नहीं पाया गया है। वीओसीपीटी से उपर्युक्त मदों के लिए प्रस्तावित दरों पर राजस्व का अनुमान लगाने का अनुरोध किया गया था। विकल्पतः, वीओसीपीटी उपर्युक्त कुछ मदों के प्रशुल्क का ध्यान रखने के लिए अनाच्छादित एआरआर की उचित राशि छोड़ सकता है जिसके लिए राजस्व का अनुमान नहीं लगाया गया है। पत्तनने स्पष्ट किया है कि इसमें सूचीबद्ध उन मदों के लिए, राजस्व कम है और इसलिए मूल पोत संबंधित आय के अधीन मिला दिया गया है तथा राजस्व अनुमानन परिकलित किया गया है। नई प्रशुल्क मद जैसे कार तथा वाहनों के प्रहस्तन के लिए घाटशुल्क दर हेतु, पत्तन ने बताया है कि चूंकि भविष्य में नई कार्गो मद की उम्मीद नहीं है, इसलिए वित्तीय विवेक्षा का प्रभाव परिमाणित नहीं किया जा सका था।

पत्तन द्वारा प्रेषित उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधारपर और यह स्वीकार करते हुए कि राजस्व अनुमान प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है, वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित राजस्व पर विश्वास किया गया है।

पत्तन ने प्रस्तावित दरमान तथा कार्यनिष्पादन मानक अनुमोदित करने वाले वीओसीपीटी के बोर्ड संकल्प की प्रति भी भेजी है।

- (ix). वीओसीपीटी द्वारा यथा प्रेषित एआरआर का परिकलन अनुबंध-1 रूप में संलग्न किया गया है। उपर्युक्त विश्लेषण के अधीन, संशोधित अधिकतम सूचकांकित एआरआर वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित रु 33,477.51 लाख के स्थान पर रु 34,490.64 लाख परिगणित होता है। संशोधित एआरआर का परिकलन अनुबंध-2 रूप में संलग्न किया गया है। प्रस्तावित दरमान पर वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित राजस्व रु 27,840.87 लाख है। जैसाकि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है, वीओसीपीटी ने बताया है कि कुछ प्रशुल्क मदों/शर्तों के लिए, राजस्व परिमाणित नहीं किया जा सकता। अनुवर्ती अनुच्छेद में यथा निर्धारित समग्र पत्तन के लिए अधिकतम सूचकांकित एआरआर, और प्रस्तावित प्रशुल्क पर राजस्व अनुमान के बीच राजस्व अन्तर पर विचार करते हुए, कुछ नई प्रशुल्क मदों/शर्तों के लेखा पर होने वाली आय और मौजूदा शर्तों में संशोधन जिसके लिए आय अनुमानित नहीं की गई है, समग्र पत्तन के लिए अनुवर्ती अनुच्छेद में दिए गए विश्लेषण में यथा अनुमानित रु 3899.31 लाख के राजस्व अन्तर में सबसम किया जाएगा।

- (x). पत्तन ने कहा है कि सीएचडी मर्जर निपटान शर्त के अनुसार पृथक स्वतः-पर्याप्त इकाई के रूप में कार्य करने के लिए है। वीओसीपीटी ने निर्धारित प्रपत्र-1 में अपने सीएचडी के लिए एआरआर का पृथक परिकलन भेजा है। वीओसीपीटी ने प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित तीनों वर्षों अर्थात् 2011-12 (वाई 1), 2012-13 (वाई 2) और 2013-14 (वाई 3) के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित सीएचडी के लिए आंकड़ों के आधार पर वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) निर्धारित किया है। सीएचडी के लिए वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित एआरआर तथा उसपर किए गए संशोधनों पर नीचे चर्चा की गई है:

- (क). तीन वर्षों अर्थात् 2011-12 (वाई 1), 2012-13 (वाई 2) और 2013-14 (वाई 3) के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर औसत व्यय पर पहुंचने के लिए, वीओसीपीटी ने इन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए वीओसीपीटी के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित परिचालन व्यय को लिया है जिसपर विचार किया गया है।

- (ख). इस संबंध में, वित्त तथा विविध व्यय (एफएमई), पत्तन ने तीनों वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए वीओसीपीटी के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित एफएमई को लिया है और वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्रमशः रु 354.00 लाख, रु 294.98 लाख तथा रु शून्य पर प्रतिवेदित वीओसीपीटी के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित सीएचडी के लिए पेंशन निधि में अंशदान को उससे अलग रखा है तथा शेष एफएमई अर्थात् रु 1645.90 लाख, रु 1058.08 लाख तथा रु 1119.98 लाख पर विचार किया है। वीओसीपीटी ने उपर्युक्त वर्षों के प्रत्येक वर्ष में रु 6281.76 लाख, रु 10720.69 लाख तथा रु 21136.00 लाख की पेंशन निधि में ओपनिंग कमी को जोड़ा था।

पत्तन ने क्रमशः रु 13093.62 लाख, रु 17532.67 लाख तथा रु 28101.39 लाख की दर से समायोजनों से पूर्व कुल व्यय निर्धारित किया था। प्रशुल्क नीति, 2015 में निर्धारित सभी समायोजन सिवाय एक समायोजन के वीओसीपीटी द्वारा शून्य माना गया है। पत्तन ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए क्रमशः रु 5025.41 लाख, रु 8576.55 लाख तथा रु 16908.80 लाख की दर से कुल व्यय से पेंशन निधि में ओपनिंग कमी के 4/5 को अलग रखा है। पत्तन ने बताया है कि 01-04-2011 को रु 6281.76 लाख और 01-04-2012 को रु 10720.69 लाख की दर से पेंशन निधि कमी इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित क्रमशः आदेश दिनांक 11-10-2011 में पैरा सं. 10.1.(viii) और आदेश दिनांक 04-08-2014 के पैरा सं. 5.1.(xiv) (ड) में उपलब्ध है। रु 21,136.00 लाख के लिए आधार अस्पष्ट रह गया है।

अन्य शब्दों में, वीओसीपीटी ने सीएचडी के एआरआर का अनुमान लगाने के समय क्रमशः वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए पेंशन निधि में ओपनिंग कमी के 1/5वें को जोड़ा है। पत्तन ने बताया है कि सीएचडी के मामले में, बीमांकक मूल्यांकन के मामले में पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि में भारी कमी को पूरा करने के लिए कोई अधिशेष निधियां उपलब्ध नहीं हैं। वर्किंग दिशानिर्देशों का खंड 2.11 पेंशन निधि लेवी में डिस्पेंसिंग करने के लिए है। इसके परिणामस्वरूप पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि में भारी कमी को पूरा करने के लिए सीएचडी पर भारी वित्तीय बोझ होगा। पत्तन ने तर्क दिया है कि चूंकि सीएचडी में एस्क्रो खाता उपलब्ध नहीं है, इसलिए कमी को पूरा करने के लिए सीएचडी में इसका उपयोग करना संभव नहीं है (जोकि निपटारा ज्ञापन दिनांक 27-7-2011 के अनुसार स्वतः-पर्याप्त हो सकता है)। पत्तन ने संदर्भित प्रत्येक वर्ष के ओपनिंग कमी के 1/5वें को कवर करने का प्रयास किया है।

पेंशन निधि में ओपनिंग बैलेंस में कमी के 1/5वें को जोड़ते हुए एआरआर पर पहुंचने के लिए वीओसीपीटी द्वारा अंगीकृत दृष्टिकोण प्रशुल्क नीति, 2015 तथा वर्किंग दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नहीं है। कांडला पत्तन न्यास, न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास सहित अन्य महापत्तन न्यासों जहां पृथक सीएचडी है, जिनका प्रशुल्क प्रशुल्क नीति, 2015 का अनुसरण करते हुए निर्धारित किया जाता है, पेंशन निधि में ओपनिंग कमी का ऐसा समायोजन सीएचडी के लिए प्रशुल्क अनुमोदित करते समय किया गया है। इसके अलावा, वीओसीपीटी द्वारा उल्लिखित दो आदेशों दिनांक 11 अक्टूबर 2011 और 4 अगस्त 2014 में मूल्यांकित ओपनिंग कमी पर विचार करने के लिए वीओसीपीटी द्वारा अंगीकृत दृष्टिकोण सही नहीं है क्योंकि उक्त आदेशों में, मूल्यांकित कमी के आधार पर, इस प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2011 में रु 9/टन और आदेश दिनांक 4 अगस्त 2014 में रु 25.10/टन की दर से सीएचडी हेतु पेंशन निधि लेवी अनुमोदित की है। चूंकि पेंशन निधि में वर्ष 2011-12 से 2013-14 में पेंशन निधि में ओपनिंग कमी के 1/5वें पर विचार करने के लिए वीओसीपीटी द्वारा अंगीकृत दृष्टिकोण 2015 में प्रशुल्क नीति के प्रावधान के अनुसार नहीं है, इसलिए केवल वीओसीपीटी के मामले में प्रशुल्क नीति, 2015 से विषयन करने के लिए कोई असाधारण स्थिति नहीं है। इसलिए, सीएचडी के एआरआर परिकलन में वीओसीपीटी द्वारा किए गए इस समायोजन पर विचार नहीं किया गया है।

इस प्रकार, हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत विवरण में, वार्षिक लेखों में यथा प्रतिवेदित एफएमई पर विचार किया गया है। वीओसीपीटी ने ऋण पर ब्याज, कपेटिव बर्थ, संपदा तथा प्रबंधन एवं सामान्य उपरिव्यय के संबंध में किसी समायोजन के बारे में नहीं बताया गया है जिसे स्वीकार किया गया है। पेंशन निधि में अंशदान के 4/5वें का समायोजन प्रत्येक वर्ष के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित आंकड़ों के आधार पर किया गया है जोकि वर्ष 2011-12 से 2013-14 में क्रमशः रु 283.20 लाख, रु 235.98 लाख तथा रु शून्य होता है। यह समायोजन प्रशुल्क नीति 2015 में निर्धारण के अनुसार है।

(ग). वीओसीपीटी ने एकमुश्त व्ययों जैसे मजदूरी की बकाया राशियां, पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशियां/एक्स-ग्रेशिया की बकाया राशियां आदि के लिए किसी राशि पर विचार नहीं किया है। तथापि, वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों में बताया गया है कि रु 10,90,62,275 और रु 11,65,857 वर्ष 2013-14 के लिए क्रमशः मजदूरी संशोधन बकाया राशियां और एसीपी बकाया राशियों के लिए है। इस बारे में ध्यान दिलाये जाने पर, वीओसीपीटी ने स्पष्ट किया था कि यह प्रभाव केवल वर्ष 2013-14 से संबंधित है और लेखों में डिस्टिंग्विशी दर्शाया गया है। पत्तन ने पुष्टि की है कि इस लेखा पर कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है। इस स्थिति पर विश्वास किया गया है क्योंकि आंकड़े प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित किए गए हैं।

(xi). कार्यगत पूंजी में वस्तुसूची, विविध देनदारियों तथा रोकड़ जमाशेष शामिल हैं। पत्तन ने सीएचडी के लिए वस्तुसूची तथा विविध देनदारियों पर विचार नहीं किया है। वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित रोकड़ जमाशेष वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.5 में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार परिकलित किए देखे गए हैं। वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित कार्यगत पूंजी रु 580.38 लाख को लेखा में लिया गया है।

(xii). वीओसीपीटी द्वारा निर्धारित कुल नियोजित पूंजी रु 588.15 लाख है। 16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ रु 94.10 लाख है जिसपर एआरआर परिकलन में विचार किया गया है।

(xiii). वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित एआरआर तीन वित्तीय वर्षों 2011-12 से 2013-14 के लिए व्यय का औसत रु 9405.64 लाख जमा आरओसीई रु 94.10 लाख दिनांक 31 मार्च 2014 को कुल रु 9499.74 लाख है। इसलिए, वीओसीपीटी ने क्रमशः 6 प्रतिशत और 3.82 प्रतिशत की दर से वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.7 के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से उक्त एआरआर सूचकांकित किया है और वर्ष 2015-16 के लिए रु 10454.309 लाख पर अधिकतम सूचकांकित एआरआर अग्रेषण पर पहुंचा है।

(xiv). वीओसीपीटी द्वारा यथा प्रेषित सीएचडी के लिए एआरआर का परिकलन अनुबंध-3 रूप में संलग्न किया गया है। उपर्युक्त विश्लेषण के अधीन, वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित अधिकतम सूचकांकित एआरआर संशोधित किया गया है। संशोधित एआरआर का परिकलन अनुबंध-4 रूप में संलग्न किया गया है। उपर्युक्त संशोधन के अधीन, वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए औसत व्यय रु 6906.34 लाख जमा वीओसीपीटी द्वारा यथा अनुमानित 16 प्रतिशत आरओसीई कुल रु 7703.93 लाख है। उपर्युक्त विश्लेषण में स्पष्ट किए गए संशोधन के सिवाय, वीओसीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 मई 2016 द्वारा प्रेषित एआरआर गणना, जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है, पर विश्वास किया गया है। सीएचडी के लिए वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित अधिकतम सूचकांकित एआरआर और उपर्युक्त विश्लेषण में स्पष्ट किए गए संशोधन के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा यथा सुविचारित का सार नीचे दिया गया है:-

(राशि रु0 लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वीओसीपीटी द्वारा यथा अनुमानित	इस प्राधिकरण द्वारा यथा सुविचारित
1.	वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए औसत व्यय	9,405.64	6,906.34
2.	31-3-2014 को निवल अचल परिसंपत्ति, प्रगतिधीन पूंजी सहित नियोजित पूंजी और प्रतिमानकों के अनुसार कार्यगत पूंजी	588.15	588.15
3.	16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	94.10	94.10

4.	31 मार्च 2014 को एआरआर (4=1+3)	9,499.74	7,000.45
5.	वर्ष 2014-15 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन (6%)	10,069.73	7,420.47
6.	वर्ष 2015-16 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन (3.82%)	10,454.39	7,703.93
7.	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	10,454.39	7,703.93
8.	अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर वीओसीपीटी और टीएमपी द्वारा अनुमानित राजस्व	10,454.39	10,454.39

- (xv). पत्तन ने रु 10454.39 लाख के अनुमानित एआरआर को पूरा करने के लिए सीएचडी लेवी में 51.20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। सीएचडी में रु 25.10/टन की मौजूदा पेंशन निधि लेवी को प्रशुल्क नीति, 2015 के वर्किंग दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्पेंस किया गया है। पत्तन ने बताया है कि पेंशन निधि लेवी डिस्पेंस करने के बाद सीएचडी में निवल वृद्धि कोयला तथा नमक से इतर कार्गो के लिए 2 प्रतिशत है और कोयला जेट्टी में कोयले के लिए 13 प्रतिशत है।
- पत्तन ने पुष्टि की है कि सीएचडी द्वारा प्रहस्तित वास्तविक कार्गो यातायात 158.80 लाख टन है और राजस्व अनुमानों में इसपर विचार किया गया है। 51.20 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धिपर वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित राजस्व रु 10454.39 लाख है। वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क पर अनुमानित राजस्व और अधिकतम एआरआर को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है जिसपर विश्वास किया गया है। तथापि, उपर्युक्त विश्लेषण के मददेनजर संशोधित एआरआर रु 7,703.93 लाख परिगणित होता है।
- जैसाकि पहले बताया गया है, पत्तन ने पत्तन परिचालनों और सीएचडी के लिए अलग-अलग प्रशुल्क का प्रस्ताव किया था और एआरआर का निर्धारण किया था। अन्य सामान्य संशोधन प्रस्तावों जैसे एनएमपीटी, केपीटी, एमबीपीटी में, पत्तन ने प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन संशोधन की मांग करते समय सीएचडी सहित समग्र पत्तन के लिए एआरआर का निर्धारण किया था हालांकि उनके मामलों में भी सीएचडी के लेखे अलग से व्यवस्थित किए गए हैं।
- यदि समग्र पत्तन के लिए स्थिति का विश्लेषण किया जाता है तो पत्तन परिचालनों के लिए कुल संशोधित अधिकतम सूचकांकित एआरआर जमा सीएचडी रु 42,194.57 लाख परिगणित होता है अर्थात् पत्तन परिचालनों के लिए मूल्यांकित रु 34,490.64 लाख और सीएचडी के लिए रु 7703.93 लाख है। जैसाकि पहले बताया गया है, पत्तन परिचालनों में 27.7 प्रतिशत की प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि पर पत्तन परिचालनों से राजस्व अनुमान रु 27,840.87 लाख है। शेष एआरआर रु 14353.70 लाख अर्थात् (रु 42,194.57 लाख - रु 27,840.87 लाख) है जो बिना कवर किया रह गया है। सीएचडी के लिए 51.20 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि पर वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित राजस्व रु 10454.39 लाख है। रु 14353.70 लाख के राजस्व अन्तर पर विचार करते हुए, वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित 51.20 प्रतिशत की प्रशुल्क वृद्धि पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित स्वीकार की गई है। इससे अब भी रु 3899.31 लाख का राजस्व अन्तर रह जाएगा। मौजूदा शर्तों में कुछ नई प्रशुल्क मदों/शर्तों से होने वाली आय जिसके लिए आय का अनुमान नहीं लगाया गया है, रु 3899.31 लाख के राजस्व अन्तर में सबसम्भ किया जाएगा।
- इस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.11 के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पेंशन निधि लेवी, यदि कोई हो, को डिस्पेंस किया जाना है। इसलिए, सीएचडी के लिए मौजूदा पेंशन निधि लेवी के साथ डिस्पेंस किए जाने का वीओसीपीटी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।
- (xvi). मूल प्रस्तावित दरमान में, वीओसीपीटी ने क्र.सं. 2 पर नौप्रस्थान पोतों के लिए अलग से निर्धारित मौजूदा पत्तन देयताओं को हटाने का प्रस्ताव किया था। इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, पत्तन ने स्पष्ट किया है कि उक्त हटाया जाना टाइपलेखन त्रुटि थी और अन्य मदों के लिए यथा प्रस्तावित 27.7 प्रतिशत प्रशुल्क वृद्धि लागू करते हुए संशोधित दरमान में इसके लिए प्रशुल्क प्रस्तावित किया है। पत्तन ने पुष्टि की है कि राजस्व अनुमान में इस प्रशुल्क मद के लिए राजस्व को पहले ही लिया गया है।
- (xvii). वीओसीपीटी ने पहले "अधिकतम दो टगों के अधीन" शब्द शामिल करते हुए पाइलटेंज शुल्क की परिभाषा में कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया था। वर्किंग दिशानिर्देशों का खंड 10.4 पाइलटेंज को होने वाली समेकित दर के लिए पाइलटेंज सह टोवेज शुल्क के रूप में परिभाषित करता है और पर्याप्त क्षमता की टगों/लांचों की अपेक्षित संख्या के साथ एक अंतर्मुखी तथा एक बहिर्मुखी आवागमन और 'पत्तन सुविधा' के लिए पोतों का स्थानांतरण शामिल होगा। इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, वीओसीपीटी ने मौजूदा दरमान में निर्धारित परिभाषा को बनाए रखा था।
- (xviii). पत्तन ने न्यूनतम स्थानांतरण प्रभार निर्धारित करते हुए अनुसूची 2.2.3 (i) और (ii) के अधीन नई टिप्पणियां प्रस्तावित की हैं। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम स्थानांतरण प्रभार न्यूनतम पाइलटेंज शुल्क के 25 प्रतिशत/50 प्रतिशत पर प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित टिप्पणियां पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित की गई हैं। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मौके बहुत कम हैं और वित्तीय दृष्टि से नगण्य हैं।
- (xix). इसके गैर-निष्पादन की वजह से बाह्य लंगरगाह/किसी अन्य बर्थों पर पोत के स्थानांतरण के लिए मौजूदा दरमान प्रभार निर्धारित करता है। टिप्पणी 9(ख) अनुसूची 2.2.1 में निर्धारित पाइलटेंज शुल्कों के 25 प्रतिशत की लेवी निर्धारित करती है यदि पोत को बर्थ 1 से 4 अथवा कोयला जेट्टी 1 तथा 2 एवं तेल जेट्टी के बीच स्थानांतरित किया जाता है।
- उक्त टिप्पणी में, पत्तन ने अब बर्थ सं. 7, 8, उत्तर-कार्गो बर्थ (एनसीबी) सं. 1 एवं 2 भी जोड़े हैं। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि चूंकि बर्थ 7, 8 और एनसीबी-1 तथा एनसीबी-2 में बर्थ किए गए/बर्थ किए जाने वाले पोतों के मामले में इसके गैर निष्पादन की वजह से बाह्य लंगरगाह/किसी अन्य बर्थ में पोतों के स्थानांतरण संभावना हो सकती है, इसलिए इस खंड को तदनुसार संशोधित किया गया है। पत्तन ने पुष्टि की है कि ऐसे मौके बहुत कम हैं और वित्तीय दृष्टि से नगण्य हैं। पत्तन द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के आधार पर, वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित मौजूदा टिप्पणी में संशोधन को अनुमोदित किया गया है।

(xx). अन्य पोटों के लिए अनुसूची सं. 2.4.2 बर्थ किराया प्रभार के अधीन क्र.सं. 3 पर निर्धारित अन्य क्राफ्टों के लिए तटीय प्रशुल्क में टाइपलेखन त्रुटि देखी गई थी। मौजूदा विदेशगामी दर में 27.7 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि लागू करते हुए यह रु 2.18/जीआरटी/घंटा की प्रस्तावित दर की बजाय रु 2.12 प्रति जीआरटी/घंटा होता है। पत्तन ने बताया है कि टाइपलेखन त्रुटि को सत्यापित और सही किया गया है। तथापि, संशोधित प्रस्तावित दरमान में शोधन किया गया दिखाई नहीं देता है। शोधित दर रु 2.18/जीआरटी/घंटा दरमान में निर्धारित की गई है। उसके अलावा, कुछ अंक-गणितीय त्रुटियां हैं जिन्हें संशोधित दरमान में शोधित किया गया है।

(xxi). (क). पत्तन ने बर्थ अभिग्रहण निर्धारित करने के लिए कार्गो वार आउटपुट प्रतिमानक और दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों की वसूली प्रस्तावित करते हुए अन्य पोटों के लिए अनुसूची 2.4.2. बर्थ किराया प्रभार के अधीन टिप्पणी 4 में नई शर्त का प्रस्ताव किया है।

टिप्पणी 4 के अधीन आउटपुट प्रतिमानक प्रस्तावित करने वाली तालिका के बाद, पत्तन ने यह टिप्पणी प्रस्तावित की है कि पत्तन के पास फील्ड परिस्थिति के अनुसार प्रतिमानकों में संशोधन करने का अधिकार होगा और इस संबंध में यातायात प्रबंधक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। चूंकि इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानकों का प्रशुल्क में सूचकांकन से संबंध होगा, इसलिए यह दिखाई देता है कि प्रशुल्क चक्र के चालू रहने के दौरान प्रतिमानों में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित टिप्पणी से प्रशुल्क के सूचकांकन से विरोध हो सकता है जिसका पूर्व-निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों से संबंध है। अतः पत्तन से अनुरोध है कि प्रस्तावित टिप्पणी की समीक्षा करे।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा खंड 7.2 द्वारा जारी किए गए महापत्तनों हेतु शुल्क बल्क के लिए नई बर्थिंग नीति के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से कार्यनिष्पादन प्रतिमानकों को बर्थों में उपलब्ध दिए गए अवसरचना के लिए प्रत्येक घटक के लिए अर्जित-योग्य लक्ष्य स्तरों पर पहुंचने के लिए है। इसके अंत में, लंगरगाह प्रभारों के साथ विभिन्न घटकों के लिए कार्यनिष्पादन प्रतिमानक सभी पत्तनों द्वारा प्रत्येक तिमाही में परिकलित किए जाएंगे। इसलिए प्रस्तावित टिप्पणी फील्ड परिस्थिति के अनुसार प्रतिमानकों को संशोधित करने के प्रावधान के साथ शामिल की गई है। शब्दावली "यातायात प्रबंधक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा" को वीओसीपीटी द्वारा संशोधित प्रस्तावित दरमान में हटा दिया गया है। वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के मद्देनजर और यह स्वीकार करते हुए कि किसी भी उपयोक्ता/उपयोक्ता एसोसिएशन ने प्रस्तावित टिप्पणी पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी, इस प्राधिकरण ने पत्तन द्वारा किए गए प्रस्ताव के साथ जाने का निर्णय लिया है सिवाय इन शब्दों को हटाने के कि पत्तन फील्ड परिस्थिति के अनुसार प्रतिमानों में संशोधन करे। यहां पर बताना प्रासंगिक है कि पत्तनों को पहले ये यह अधिकार प्राप्त है कि वे आउटपुट प्रतिमानकों में छूट दे सकें। यदि पत्तन निर्धारित आउटपुट को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है तो इस प्राधिकरण का ऊध्वमुखी अनुमोदन अपेक्षित होगा क्योंकि आउटपुट प्रतिमानकों को बर्थ किराया प्रभारों में दंडात्मक/रियायत से जोड़ा गया है। इस स्थिति के मद्देनजर, फील्ड परिस्थिति के अनुसार प्रतिमानक संशोधित करते हुए पत्तन की प्रस्तावित शर्त को हटाया गया है।

तूतीकोरिन स्टीवडोर्स एसोसिएशन (टीएसए) ने प्रस्तावित उत्पादकता प्रतिमानकों में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया था। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कार्गो पत्तन के लिए पत्तन ने पत्तन में उपलब्ध मौजूदा अवसरचना सुविधाओं को लेखा में लेने के बाद पिछले तीन वर्षों में प्रहस्तित वास्तविक टनभार से उत्पादकता को प्राप्त किया है। वीओसीपीटी ने कहा है कि शिप एजेंट्स एसोसिएशन ने अपने पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2015 द्वारा यह कहते हुए प्रतिमानकों पर पुनर्विचार करने के लिए पत्तन से अनुरोध किया था कि नए संशोधित प्रतिमानक बहुत अधिक हैं जिन्हें उनके द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। शिप एजेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधि जो उक्त कार्गो का प्रहस्तन करता है, के साथ चर्चा के बाद, पत्तन ने उनके अनुरोध के आधार पर कुछ कार्गो मर्चों के प्रतिमानक संशोधित किए हैं। पत्तन ने कहा है कि पत्तन उपयोक्ताओं के अनुरोध पर विचार करते हुए, पत्तन ने प्रत्येक कार्गो के लिए लगाए गए हुकों की संख्या से विभाजित करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रहस्तित कुल टनभार को लेते हुए प्रत्येक कार्गो के लिए तीन वर्षों के औसत के आधार पर प्रतिमानक संशोधित किए थे और न्यूनतम उक्त प्रतिदिन औसत टनभार का केवल 75 प्रतिशत है। पत्तन ने प्रभावी ढंग से कहा है कि आउटपुट प्रतिमानकों में और कमी करने के टीएसए के अनुरोध का औचित्य नहीं है।

इस मामले की कार्यवाही के दौरान, वीओसीपीटी ने कहा था कि प्रस्तावित उत्पादकता प्रतिमानकों में कुछ फाइन टयूनिंग अपेक्षित है। इस संबंध में, वीओसीपीटी से फाइन-टयूनिंग उत्पादकता प्रतिमानक और उत्पादकता प्रतिमानक भेजने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में, वीओसीपीटी ने बताया है कि जहां तक उत्पादकता प्रतिमानकों का संबंध है, उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श से मंत्रालय के निदेशों के अनुसार उत्पादकता प्रतिमानकों को अंतिम रूप देने की कार्रवाई की जा रही है और इसलिए इस प्राधिकरण से पत्तन द्वारा अंतिम रूप दिए जाने तक प्रस्ताव में निवेदन किए गए उत्पादकता प्रतिमानकों पर विचार किया जाए। इसलिए, पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित आउटपुट प्रतिमानक दरमान में निर्धारित किए गए हैं। यदि पत्तन ऐसा करने की परिकल्पना करता है तो वीओसीपीटी को संशोधित उत्पादकता प्रतिमानक अधिसूचित करने के लिए ट्रेड से विचार-विमर्श से प्रस्ताव के साथ इस प्राधिकरण का रुख करे।

(ग). पत्तन ने अतिरिक्त बर्थ किराया के 50 प्रतिशत का जुर्माना प्रस्तावित किया है यदि पोत की उत्पादकता प्रस्तावित आउटपुट प्रतिमानकों से कम रहती है। यदि पोत उत्पादकता अर्जित करता है जो आउटपुट प्रतिमानकों से 66.66 प्रतिशत कम है, पत्तन ने विनिर्दिष्ट घंटों से अधिक रुकने पर 75 प्रतिशत अतिरिक्त बर्थ किराया के जुर्माने का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने बर्थ किराया प्रभारों पर 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया है यदि अर्जित उत्पादकता निर्धारित आउटपुट प्रतिमानक प्रतिदिन से 125 प्रतिशत/150 प्रतिशत से अधिक रहती है।

टिप्पणी (4) के अधीन निर्धारित कार्गो-वार आउटपुट के अलावा, पत्तन ने बर्थ सं. 9 एवं बर्थ सं. 3 तथा 4 में प्रहस्तित कोयला पोटों के मामले में उत्पादकता प्रतिमानकों से उच्चतर अर्जित करने के लिए बर्थ किराया प्रभारों में रियायत और आउटपुट प्रतिमानक अर्जित नहीं करने के लिए जुर्माने से संबंधित अलग-अलग आउटपुट प्रतिमानक और प्रावधान भी प्रस्तावित किये हैं। पत्तन ने बर्थ किराये (घाट क्रेन तत्व अतिरिक्त) के 3 गुना और 5 गुना की दर से जुर्माने का प्रस्ताव किया है यदि प्रस्तावित आउटपुट प्रतिमानक अर्जित नहीं किए जाते हैं। इसी तरह, बर्थ किराया प्रभारों में 10 प्रतिशत/20 प्रतिशत की रियायत प्रस्तावित की गई है यदि प्रस्तावित आउटपुट प्रतिमानक अर्जित किए जाते हैं।

तूतीकोरिन स्टीवडोर्स एसोसिएशन (टीएसए) ने बताया है कि वीओसीपीटी के बर्थ सं. 3 और 4 तथा बर्थ सं. 9 में कोयले के लिए निर्धारित उत्पादकता मात्रा व्यावहारिक रूप से बर्थ में उतराई स्थान की उपलब्धता और बर्थ अभिग्रहण करने वाले पिछले पोत कार्गो की

निकासी पर निर्भर करता है जो बर्थ 3, 4 एवं 9 में कोयला पोतों की उतराई की मात्रा का हिंडर हो सकता है। वैसे, टीएसए ने सुझाव दिया है कि उत्पादकता प्रतिमानकों से कम उतराई करने के लिए प्रस्तावित जुर्माना 12000 मी.ट./दिन के उतराई प्रतिमानकों और 10,500 मी.ट. के उतराई प्रतिमानकों से कम के लिए परिकल्पित विराम अवधि को पार करने वाले पोत के लिए अतिरिक्त एकमुश्त बर्थ किराया अवश्य कम किया जाना चाहिए यह बर्थ किराया विराम का दो गुना तक अधिरोपित किया जा सकता है।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि बर्थ सं. 9 और बर्थ सं. 3 एवं 4 में कोयला प्रहस्तन पर बैचमार्क उत्पादकता मै0 बीसीजी की उसकी रिपोर्ट दिनांक 04-11-2015 (पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार बिना मोलभाव योग्य) में सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। पत्तन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जुर्माना/रियायत अधिरोपित करने के लिए बर्थ सं. 3, 4 एवं 9 पर उतराई प्रतिमानकों के संशोधन के लिए टीएसए के सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकता।

पत्तन ने यह भी कहा है कि बर्थिंग नीति, 2016 में शुष्क बल्क कार्गो के लिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित उत्पादकता प्रतिमानक मै0 बीसीजी द्वारा प्रस्तावित उत्पादकता प्रतिमानकों का अधिक्रमण करते हैं। तथापि, पत्तन ने प्रस्ताव में बताया है कि उत्पादकता प्रतिमानक परामर्शदाता की सिफारिशों पर आधारित हैं। पत्तन ने भविष्य आउटपुट से जुड़े जुर्माने/रियायत से संबंधित टिप्पणियों का भी प्रस्ताव किया है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य आउटपुट डिनोट करता है कि बर्थ सं. 9 पर अभियंत्रिकरण परिचालनों और बर्थ सं. 3 एवं 4 में एचएमसी की 2 सं. के इरेक्शन के बाद, भविष्य आउटपुट रूप में प्रस्तावित उच्चतर आउटपुट प्रतिमानक लागू होंगे।

पत्तन ने बताया है कि जुर्माना और रियायत योजना मै0 बीसीजी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 04-11-2015 (पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार बिना मोलभाव योग्य) में की गई अनुशंसाओं पर तैयार की गई थी। पत्तन ने यह भी कहा है कि अतिरिक्त बर्थ घंटों पर 3 गुना की दर से जुर्माने की सीमा भी एमओएस द्वारा जारी की गई बर्थिंग नीति, 2016 के अनुसार है।

वीओसीपीटी का ध्यान आकर्षित किया गया था कि जुर्माने की वसूली तथा रियायत प्रदान करने का शासित करने वाली प्रस्तावित शर्तें बर्थ सं. (9) और वीओसी 3 एवं 4 के लिए अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क में निर्धारित नहीं की गई हैं। इसलिए, वीओसीपीटी से यह जांच करने का विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि क्या प्रस्तावित शर्तों का निर्धारण करने से बर्थ सं. (9) तथा वीओसी 3 एवं 4 के सफल बोलीदाताओं के साथ विवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

इस संबंध में, पत्तन ने स्पष्ट किया है कि बर्थ सं. 9, वीओसी 3 एवं 4 में कोई पीपीपी परिचालन नहीं हैं, क्योंकि ये बर्थ वीओसी पत्तन द्वारा परिचालित किए जाते हैं। पत्तन ने बताया है कि लाइसेंस आधार पर दिए गए बर्थ सं. 9 में ही एचएमसी वर्तमान में तैनात किया गया है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना और रियायत प्रदान करना पोत परिचालकों पर होगा। पत्तन ने इस प्रकार पूर्ववर्ती दरमान में इसके द्वारा प्रस्तावित टिप्पणियों को जारी रखने का प्रस्ताव किया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सभी संबद्ध उपयोक्ता, क्रेन परिचालक इम्कोला क्रेन कम्पनी प्रा0 लि0 (आईसीसीपीएल) सहित सभी संबद्ध वीओटी परिचालकों से विषय प्रस्ताव पर परामर्श किया गया था। किसी भी उपयोक्ता, उपयोक्ता एसोसिएशन अथवा आईसीसीपीएल ने प्रस्तावित शर्तों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की थीं। ऐसी स्थिति में, और चूंकि वीओसीपीटी ने मामले की जांच करने के बाद दरमान में इन शर्तों का प्रस्ताव किया है और पत्तन ने यह भी बताया है कि प्रस्तावित शर्तें पोत परिचालक पर लागू हैं, वीओसीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित बर्थ सं. 9, 3 एवं 4 में प्रहस्तित कोयला पोतों के मामले में बर्थ किराया प्रभारों में जुर्माना और रियायत से संबंधित टिप्पणियां और शर्तें बर्थ सं. 3, 4 एवं 9 में प्रहस्तित कार्गो से इतर कार्गो के मामले में वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित रियायत/जुर्माना प्रावधानों के साथ अनुमोदित की गई हैं।

(घ). पत्तन से प्रस्तावित शर्तों की प्रत्येक शर्त के मद्देनजर प्रोद्भूत होने की संभावना वाली अतिरिक्त आय की गणना भेजने और यह भी दर्शाने का अनुरोध किया गया था कि इसे राजस्व अनुमानों में कहा लिया गया है। पत्तन ने बताया है कि चूंकि उच्चतर उत्पादकता के लिए कम उत्पादकता और प्रोत्साहन हेतु जुर्माने से संबंधित खंड, वित्तीय विवीक्षा अनुमान से परे है तथा यह नगण्य होगा। जैसाकि पहले बताया गया है, राजस्व अन्तर रु0 6649.77 लाख है और प्रस्तावित नई शर्तों से आय जिसके लिए आय का अनुमान नहीं लगाया गया है, उक्त राजस्व अन्तर से सबसम किया जाएगा।

(xxii). अनुसूची 2.4.2 के अधीन टिप्पणी 9 में मौजूदा दरमान यह टिप्पणी निर्धारित करता है कि एक दिवसीय बर्थ किराया प्रभार प्रभार्य है क्योंकि मांग की गई सेवाओं के रद्दीकरण के लिए न्यूनतम प्रभार है। इसमें बर्थिंग अनुसूची में संशोधन, बर्थिंग का रद्दीकरण, ई-बुकिंग के लिए प्रणाली में कंप्यूटर प्रविष्टि हेतु संशोधन आदि शामिल हैं।

वीओसीपीटी ने मौजूदा उक्त टिप्पणी को बनाए रखते हुए क्र.सं. 11 पर अनुसूची 2.4.2 के अधीन दो नई टिप्पणियां प्रस्तावित की हैं अर्थात् (i) यदि रद्दीकरण हेतु सूचना प्रार्थित सेवाओं के समय के 24 घंटे पहले प्राप्त होती है, कोई दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार नहीं होंगे; अन्यथा एक दिन की बर्थ लाइन पर इसे वसूल किया जाएगा और (ii) संशोधन के लिए दंड की राशि रु0 5000/- प्रति संशोधन है।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि उपयोक्ताओं ने पोत बुकिंग के रद्दीकरण के लिए प्रभारित एक दिवसीय दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार वापिस लेने का अनुरोध किया था क्योंकि यह एक्सोरबिटेंट है। इसलिए, अनुरोध पर विचार करने के लिए और बर्थिंग कार्यक्रम के संशोधन के लिए भी, यह उपर्युक्त दो नई टिप्पणियां शामिल करते हुए शर्त में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर राजस्व प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह संचयी नहीं है। चूंकि प्रस्तावित दो टिप्पणियां ट्रेड के अनुरोध पर आधारित बताई गई हैं, इसलिए इसे अनुमोदित किया गया है।

(xxiii). घाटशुल्क अनुसूची में, मौजूदा दरमान में कोयला तथा कोक के लिए निर्धारित प्रशुल्क तथा प्रस्तावित नाम और कोयला एवं कोक के अधीन कार्गो मदों के लिए प्रशुल्क संदर्भ के लिए नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

(क). मौजूदा दरमान में यथा निर्धारित।

दर रु0 में प्रति टन

क्र.सं.	विवरण	प्रभार की इकाई	जोन क	जोन ख
3.	कोयला एवं कोक		विदेशी	तटीय
			विदेशी	तटीय

(क). चारकोल बैगों/बल्क में	1 मी.ट.	28.00	16.80	12.00	7.20
(ख). स्टीमिंग (गैर-कोकिंग कोयला)	1 मी.ट.	27.00	16.20	16.20	9.70
(ग). स्टीमिंग (गैर-कोकिंग कोयला) और कोक से इतर कोयला बल्क में	1 मी.ट.	30.00	18.00	18.00	10.80
(घ). कोयला जेट्टी के माध्यम से प्रहस्तित कोयला तथा कोक (ताप कोयला से इतर)	1 मी.ट.	38.00	22.80	--	--

(ख). वीओसीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित

क्र.सं.	विवरण	रु० प्रति टन				
		प्रभार की इकाई	जोन क		जोन ख	
			विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
3	कोयला तथा कोक					
	(क). चारकोल बैगों/बल्क में	1 मी.ट.	35.76	21.45	15.32	9.19
	(ख). सीमाशुल्क दस्तावेज में किसी अन्य नाम से वर्णित और ताप बिजली संयंत्रों हेतु प्रयुक्त कोयला	1 मी.ट.	48.53	48.53	-	-
	(ग). उपर्युक्त 3(ख) से इतर सीमाशुल्क दस्तावेज में वर्णित किसी अन्य नाम से कोयला	1 मी.ट.	48.53	29.12	29.12	17.47
	(घ). कोयला जेट्टी के माध्यम से प्रहस्तित कोयला तथा कोक (ताप कोयला से इतर)	1 मी.ट.	48.53	29.12	-	-
	(ङ). ताप कोयला	1 मी.ट.	48.53	48.53		

यह देखा जा सकता है कि पत्तन ने तीन मदों के नाम संशोधित किए हैं। जब इसके कारण और आधार स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था तो पत्तन ने बताया था कि वर्तमान में कोयले के वर्गीकरण में कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन से बिजली संयंत्रों के लिए हैं और कौन से बिजली संयंत्रों से इतर के लिए हैं, जैसे सीमाशुल्क दस्तावेज केवल स्टीमिंग (गैर-कोकिंग) कोयला के रूप में वर्गीकृत करता है। ताप कोयला/अन्य कोयला के संबंध में सीमाशुल्क लेखांकन में कोई पृथक् विवरण नहीं है। इसलिए निर्वर्णन में भिन्नता की वजह से सतर्कता तथा रेजिडेंट ऑडिट द्वारा कम संग्रहण का मुद्दा देखा गया था। उपर्युक्त पर विचार करते हुए, कोयला एकल वर्गीकरण के अधीन लाया गया है। पत्तन ने बताया है कि प्रस्तावित दर कोयला जेट्टी में रु० 38/- प्रति टन की दर से प्रहस्तित कोयला तथा कोक के लिए मौजूदा घाटशुल्क दर में 27.7 प्रतिशत वृद्धि लागू करते हुए कोयले की सभी श्रेणियों में एकसमान रूप से प्रस्तावित की गई है। पत्तन ने पुष्टि की है कि उपर्युक्त संशोधन की वजह से राजस्व वृद्धि का प्रभाव राजस्व अनुमानों में उपयुक्ततः लिया गया है। वीओसीपीटी द्वारा किए गए निवेदनों पर विश्वास करते हुए, कोयला के नाम में संशोधन जोकि स्पष्ट लाने के लिए बताया गया है और वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें अनुमोदित की गई हैं।

(xxiv). पत्तन ने कुछ मदों के लिए मौजूदा दरमान में निर्धारित यथामूल्य घाटशुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है और घाटशुल्क दर इकाई आधार पर प्रस्तावित की है। मशीनरियों तथा मशीनरी पुर्जों के लिए रु० 150/- प्रति मी.ट की घाटशुल्क दर प्रस्तावित की गई है और शेष कार्गों के लिए, अन्यथा अविनिर्दिष्ट सामानों की मौजूदा घाटशुल्क दर में रु० 42 प्रति मी.ट. की दर से 27.70 प्रतिशत की वृद्धि पर विचार किया गया है और घाटशुल्क दर रु० 53.40 प्रति मी.ट. प्रस्तावित की गई है। यथामूल्य दर के स्थान पर पत्तन द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट घाटशुल्क दर अनुमोदित की गई है।

(xxv). पत्तन ने 1600 सीसी से कम की कार के प्रहस्तन के लिए रु० 500/- की दर से और 1600 सीसी से अधिक की कार के प्रहस्तन के लिए रु० 1000/- की दर से आरओआरओ पोतों के माध्यम से ऑटोमोबाइल के प्रहस्तन के मामले में अपने पत्र दिनांक 13 जून 2016 द्वारा नई घाटशुल्क मदों का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने बताया है कि प्रस्तावित प्रशुल्क 1600 सीसी से कम की कार के प्रहस्तन के लिए रु० 500/- और 1600 सीसी से अधिक की कार के प्रहस्तन के लिए रु० 1000/- की दर से आरओआरओ पोतों के माध्यम से ऑटोमोबाइल के प्रहस्तन के लिए दर निर्धारित करने हेतु चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के प्रस्ताव पर आधारित है। यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सीएचपीटी के दरमान में प्रस्तावित रु० 500 प्रति इकाई दोपहिया के लिए है चारपहिया के लिए नहीं। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीएचपीटी के दरमान में चारपहियों के लिए प्रस्तावित घाटशुल्क दरें निम्नवत् हैं:-

दर रु० में				
क्र.सं.	विवरण	लेवी की इकाई	विदेशी	तटीय
(i).	1400 सीसी तक के चारपहिया			
	(क). आयात	प्रत्येक	4,200	2,520
	(ख). निर्यात	प्रत्येक	2,200	1,320
(ii).	1400 सीसी से अधिक के चारपहिया	प्रत्येक	8,400	5,040
	-आयात और निर्यात			

चूंकि वीओसीपीटी का प्रस्ताव सीएचपीटी के दरमान में निर्धारित दर अंगीकृत करने के लिए है, इसलिए सीएचपीटी द्वारा प्रस्तावित और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चारपहियों के लिए उपर्युक्त दरें भी वीओसीपीटी के दरमान में निर्धारित की गई हैं। पत्तन ने यह टिप्पणी प्रस्तावित की है कि ट्रेलर के साथ लदे कंटेनरों के साथ वाहन के लिए, प्रशुल्क दोनों वाहन को कवर करते हुए समेकित दर पर संग्रहीत किया जाएगा और घाटशुल्क अनुसूची में अलग से निर्धारित दर पर अलग से निर्धारित किए गए हैं। प्रस्तावित टिप्पणी अनुमोदित की गई है।

- (xxvi). (क). वीओसीपीटी ने, प्रस्तावित दरमान में, यह टिप्पणी शामिल की है कि पत्तनों में आने वाले पोत जिसके लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रयोजनों के लिए आईजीएम और/अथवा ईजीएम दाखिल किए जाते हैं, 'कार्गो' के रूप में नहीं माना जा सकता और वे केवल सुविधा हैं और पत्तनों को ऐसे पोतों पर घाटशुल्क वसूल नहीं करना चाहिए। यह निर्धारण आयात सामान्य विनिहित (आईजीएम) अथवा निर्यात सामान्य विनिहित (ईजीएम) में कार्गो रूप में विनिहित पोत पर घाटशुल्क प्रभार संबंधी अनुसरण करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों को निदेश देते हुए एमओएस के एमओएस पत्र सं. पीडी-25021/7/2015-पीडी.1 के अनुसरण में वीपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को हमारे पत्र सं. टीएमपी/53/2002-विविध दिनांक 25 मार्च 2015 पर आधारित है। यह टिप्पणी संशोधित प्रस्तावित दरमान में शामिल नहीं की गई है। उक्त आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित इस संबंध में सामान्य टिप्पणी को संशोधित दरमान में शामिल किया गया है।
- (ख). इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएमपी/52/2014-सामान्य दिनांक 28 नवम्बर 2014 द्वारा सभी महापत्तन न्यासों द्वारा सामान्य अंगीकरण के लिए तटीय पोत की वरीयता बर्थिंग पर एमओएस द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए थे और पत्तन को उसके मौजूदा दरमान में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी गई थी। चूंकि प्रस्तावित दरमान में महापत्तन में तटीय पोतों की वरीयता बर्थिंग पर दिशानिर्देश शामिल नहीं किए गए थे, इसलिए वीओसीपीटी से इसे शामिल करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि पत्तन ने बताया है कि ये शर्तें शामिल की गई हैं, परन्तु इसे संशोधित प्रस्तावित दरमान में शामिल नहीं किया गया है। एमओएस द्वारा जारी किए गए और इस प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेश में अधिसूचित किए गए दिशानिर्देश संशोधित दरमान में शामिल किए गए हैं।
- (ग). यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पत्र सं. पीडी/14033/101/2015-पीडी.वी. दिनांक 3 फरवरी 2016 द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) संप्रेषण के अनुसरण में इस प्राधिकरण ने कार्गो तथा पोत संबंधित सेवाओं के लिए निम्नतर प्रभारों के निर्धारण एवं महापत्तन न्यासों तथा प्रचालन कर रहे बीओटी परिचालकों द्वारा नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभारों में विशेष छूट से संबंधित एक सामान्य अंगीकरण आदेश सं. टीएमपी/14/2016-विविध दिनांक 9 फरवरी 2016 पारित किया था। वीओसीपीटी ने कार्गो तथा पोत संबंधित प्रभारों एवं नियमित घंटों के बाद प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन प्रभारों में विशेष छूट के लिए निम्नतर प्रभारों का प्रस्ताव नहीं किया है। अतः वीओसीपीटी से प्रस्तावित दरमान में इसे शामिल करने का अनुरोध किया गया था। पत्तन ने अनुरोध किए जाने के बावजूद इसे शामिल नहीं किया है। उक्त सामान्य आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिसूचित सामान्य टिप्पणी संशोधित दरमान में शामिल की गई है।
- (xxvii). मौजूदा दरमान अध्याय 5, अनुसूची 5.03 के अधीन क्र.सं. 1 से 4 पर मोबाइल क्रेन/फोर्क लिफ्ट ट्रक/मार्शल दिमाग क्रेन किराये पर लेने के लिए पृथक प्रभार निर्धारित करता है। पत्तन ने यह उद्धरित करते हुए इन प्रशुल्क को हटाने का प्रस्ताव किया है कि पत्तन के पास ये उपस्कर उपलब्ध नहीं हैं। इन प्रशुल्क मदों को हटाने के लिए पत्तन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।
- (xxviii). वीओसीपीटी ने अनुसूची 5.20 निजी परिचालक द्वारा संस्थापित हारबर मोबाइल क्रेनों (एचएमसी) के उपयोग से संबंधित प्रभार में 27 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एचएमसी के लिए मौजूदा प्रशुल्क मानक आधार पर आदेश सं. टीएमपी/22/2007-टीपीटी दिनांक 30 दिसम्बर 2009 के अनुसार है जिसे उस समय के निर्धारित स्तर पर दरमान के पिछले सामान्य संशोधन में निर्धारित किया जाना जारी रखा गया था। प्रशुल्क नीति, 2015 में, खंड 9.1 से 9.3 पत्तन द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा वसूल किए गए प्रभारों के प्रशुल्क विनिमयन हेतु प्रावधान निर्धारित करता है। अधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा परिचालित एचएमसी के लिए सामान्य दरमान हेतु 27.7 प्रतिशत प्रशुल्क संशोधन लागू करते हुए वीओसीपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव उक्त दिशानिर्देश प्रावधान के अनुसार नहीं पाया गया था। ऐसी स्थिति में, वीओसीपीटी से मानक आधार पर अधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाई गई एचएमसी के लिए दर में संशोधन हेतु पृथक प्रस्ताव दाखिल करने का अनुरोध किया गया था। पत्तन सहमत था और कहा था कि समीक्षा के आधार पर और यदि आवश्यक हो प्रस्ताव अलग से दाखिल किया जाएगा। वीओसीपीटी द्वारा यथा सहमत, पत्तन को यह सलाह दी जाती है कि मामले की जांच करे और दिसम्बर 2009 आदेश में अनुसरित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए एचएमसी के लिए दर में संशोधन का प्रस्ताव दाखिल करे। तब तक, इसके संशोधित प्रस्तावित दरमान में वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरमान से हटाने की बजाय मौजूदा दरमान में 100 टन एचएमसी के लिए मौजूदा कार्यनिष्पादन संबंधित दर को निर्धारित रखा जाए।
- (xxix). (क). वीओसीपीटी ने धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार के लिए नया प्रशुल्क प्रस्तावित किया है। वर्किंग दिशानिर्देश, 2015 के खंड 5.7.1 के अनुसार, जब कभी किसी सेवा/कार्गो के लिए पत्तन विशेष के दरमान में विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध नहीं होता है तो संबद्ध महापत्तन न्यास किसी अन्य महापत्तन न्यास में प्रशुल्क तथा कार्यनिष्पादन मानकों को अंगीकृत करते हुए नए कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए दर प्रस्तावित कर सकता है। यदि किसी अन्य महापत्तन न्यास में दर उपलब्ध नहीं हो अथवा यदि उपलब्ध दर पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं हो तो पत्तन 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए सर्वोत्तम क्षमता के संदर्भ में अथवा दरित क्षमता अथवा सेवा/सुविधा/उपस्कर की तकनीकी विशेषता अथवा लागत जमा 16 प्रतिशत प्रतिलाभ सूत्र पर नए कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए प्रस्ताव दाखिल कर सकता है। वीओसीपीटी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि किस विकल्प के अधीन, धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार हेतु दर वर्किंग दिशानिर्देशों में निर्धारित विकल्पों में प्रस्तावित की गई है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि धूलपूर्ण कार्गो पर प्रदूषण अधिभार पृथक सेवा नहीं है। घाट क्षेत्र को साफ करने के लिए व्यय राशि वसूल करने के लिए और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) अपेक्षाओं का अनुपालन करने के प्रयासों के अंतर्गत, ऐसा प्रदूषण अधिभार धूलपूर्ण कार्गो पर रु 5/- प्रति टन की दर से प्रस्तावित किया गया है। पत्तन ने बताया है कि वर्तमान में, पर्यावरणीय मुद्दे पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इसलिए, पत्तन को यह देखने के लिए सभी उपाय करने होंगे कि प्रदूषण नियंत्रणधीन है और न्यूनतम स्तर पर है। इस दिशा में, प्रदूषण अधिभार धूलपूर्ण कार्गो के लिए रु 5/- प्रति टन की दर से नया प्रस्तावित किया गया है। इस नई मद से राजस्व राजस्व अनुमानों में लिया गया है। पत्तन द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के आधार पर और यह स्वीकार करते हुए कि इस नई प्रशुल्क मद के राजस्व को लेने के बाद भी, राजस्व अनुमान अनुमानित एआरआर के भीतर ही है, इसलिए धूलपूर्ण कार्गो पर प्रस्तावित प्रदूषण अधिभार अनुमोदित किया गया है।

- (ख). तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड पत्तन से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या प्रदूषण अधिभार कोयला जेट्टी 1 और 2 में प्रहस्तित कोयले पर लागू होगा। वीओसीपीटी ने स्पष्ट किया था कि यह लागू नहीं होगा। पहले पत्तन ने बताया था कि यदि कोयला जेट्टी 1 और 2 प्रदूषण सृजित करती है तो पत्तन को इन दो कोयला जेट्टियों के लिए भी प्रस्तावित लेवी लागू करनी होगी। इसलिए पत्तन से प्रस्तावित दरमान में शर्त में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित करने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात, वीओसीपीटी ने स्पष्ट किया है कि कोयला जेट्टी 1 एवं 2 में कोयला बन्द कन्वेयर प्रणाली में प्रहस्तित किया जाता है और इसलिए उक्त प्रदूषण अधिभार लागू नहीं होगा तथा इसलिए प्रस्तावित दरमान में संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (xxx). मै0 कोस्टल मेकेनाइज्ड सेल वेसल ऑनर्स एसोसिएशन (सीएमएसवी) जो जोन ख में परिचालन करता है, द्वारा कही गई यह बात सही नहीं है कि नौप्रस्थान पोत टीएमपी के न्यायाधिकार में नहीं आते हैं। यह बताना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण की संविधि महापत्तन न्यास अधिनियम के खंड 48 में सूचीबद्ध सेवाओं के लिए महापत्तन न्यासों द्वारा प्रदत्त पोत संबंधित तथा कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण के लिए है। नौप्रस्थान पोत के लिए प्रशुल्क पिछले तीन सामान्य संशोधन आदेश में एक दशक से अधिक समय से प्रचलन में है और इस प्राधिकरण को दिए गए अधिकार क्षेत्र में आता है।
- (xxxi). सीएचडी के संबंध में जैसाकि पहले बताया गया है 51.20 प्रतिशत वृद्धि वीओसीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित की गई है। रु0 25.10 की पेंशन निधि लेवी के डिस्पेंस करने के लिए वीओसीपीटी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 8.4 के अनुसार, महापत्तन उन्हें उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए ही वसूली करेंगे। लेबर की कल्पित बुकिंग और अन्य समान कल्पित प्रभारों की अनुमति नहीं दी गई है। वीओसीपीटी भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशुल्क नीति 2015 के उक्त प्रावधान का अनुपालन करे।
- (xxxii). टीएएनजीईडीसीओ ने अपने पत्र दिनांक 27 मई 2016 द्वारा इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वीओसीपीटी को इस प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना 1 अप्रैल 2016 के बाद की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत की पेंशन निधि लेवी संग्रहीत करने पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया जाए क्योंकि पिछले सामान्य संशोधन आदेश में कहा गया है कि 6.50 प्रतिशत की दर से पेंशन निधि लेवी 1 अप्रैल 2016 से लागू होनी समाप्त हो जाएगी। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 31 मार्च 2016 के बाद अपने दरमान की वैधता का विस्तार करने की मांग करते समय वीओसीपीटी ने पेंशन निधि लेवी की वैधता को इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरों को अधिसूचित किए जाने तक विस्तारित करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में, वीओसीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 11 मई 2016 द्वारा अनुरोध किया गया था कि उसके दरमान की वैधता के विस्तार की मांग करने के समय 31 मार्च 2016 के बाद की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत की पेंशन निधि लेवी के लिए विस्तार मांगने का औचित्य बताए। प्रत्युत्तर में, वीओसीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 12 मई 2016 द्वारा 31 मार्च 2016 के अनुसार पेंशन निधि खाते में रु0 171.56 करोड़ का घाटा दर्शाता विवरण भेजा था। वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित विवरण के अनुसार, 31 मार्च 2016 को पेंशननिधि का बीमांकन मूल्यांकन रु0 626.68 करोड़ बताया गया है जबकि तदनुसारी तारीख को वास्तविक पेंशन निधि शेषजमा रु0 455.12 करोड़ बताया गया है। इस प्रकार, वीओसीपीटी द्वारा प्रतिवेदित पेंशन निधि शेषजमा में कमी के मद्देनजर संशोधित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने तक अपने मौजूदा दरमान की वैधता का विस्तार करने की मांग करते समय 6.5 प्रतिशत की पेंशन निधि लेवी के विस्तार की मांग की थी। वीओसीपीटी द्वारा किए गए निवेदन के मद्देनजर, इस प्राधिकरण ने वीओसीपीटी के दरमानों की वैधता विस्तारित करते समय आदेश सं. टीएमपी/47/2012-वीओसीपीटी दिनांक 19 मई 2016 द्वारा 6.5 प्रतिशत की पेंशन निधि लेवी की वैधता भी विस्तारित की थी। इस बारे में उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है। वर्किंग दिशानिर्देश 2015 का उल्लेख करते हुए उनके मतों की जानकारी मांगने के बारे में टीएएनजीईडीसीओ द्वारा कही गई बात के संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह मामला मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित था और प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन पत्तन के किसी प्रस्ताव के संदर्भ में नहीं था। मौजूदा दरों की वैधता के विस्तार के लिए, परामर्श प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किसी भी महापत्तन न्यास/बीओटी परिचालक के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित किन्हीं आदेशों में नहीं किया गया है।
- (xxxiii). प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 4.1 के अनुसार, (i). पूर्व प्रशुल्क आदेशों में इस प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित अतिरिक्त अधिशेष जो असमायोजित रह गया था को महापत्तन न्यासों द्वारा किसी निधि में अंतरित किया जाएगा जैसी पत्तन न्यास की इच्छा होगी, और इसके अलावा (ii). इस नीति के अधीन निर्धारित नए दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक मौजूदा दरमानों के लागू होने की अवधि के दौरान महापत्तन न्यासों को प्रोदभूत होने वाला अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, मूल्यांकित किया जाना चाहिए और सामान्य आरक्षण में अंतरित किया जाना चाहिए तथा पत्तन अवसंरचना सुविधाओं के विकास, सृजन और/अथवा आधुनिकीकरण के लिए निधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि (i) के संबंध में वीओसीपीटी के मामले में कोई पूर्व अवधि असमायोजित अधिशेष नहीं है। उपर्युक्त (ii) के संबंध में, वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए अनुरोध किए जाने के बावजूद पत्तन ने स्वीकार्य लागत और 16 प्रतिशत प्रतिलाभ के बाद वास्तविक निवल अधिशेष/घाटा का मूल्यांकन नहीं किया है। पत्तन ने बस यही कहा है कि मौजूदा दरमान प्रस्तावित दरमान से 21.20 प्रतिशत कम है, इसलिए संशोधित दरों के संशोधन तक मौजूदा प्रशुल्क के विस्तार की वजह से अतिरिक्त अधिशेष का कोई प्रोदभूत नहीं होगा। पत्तनने अतिरिक्त अधिशेष/घाटा लागत स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए लागत विवरण नहीं भेजा है। पत्तन को यह सलाह दी जाती है कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए स्वीकार्य लागत और 16 प्रतिशत प्रतिलाभ के बाद निवल अधिशेष/घाटा का मूल्यांकन करे और अब अनुमोदित संशोधित दरें लागू होने तक और प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 4.1 के अनुसार अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, अंतरित नहीं करता और इस स्थिति के बारे में आदेश के लागू होने की तारीख से दो माह के भीतर इस प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।
- (xxxiv). प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 3.1 के अनुसार, महापत्तन न्यास औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, कंटेनर प्रहस्तन के मामले में औसत फेरे प्रति घंटा के रूप में कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए कार्यनिष्पादन मानक प्रतिबद्ध करेगा। पोत साइड सेवाओं के लिए, पत्तन पोतों के औसत वापिसी समय और पोतों के औसत पूर्व-बर्थिंग समय तथा किन्हीं अन्य पैरामीटर के रूप में कार्यनिष्पादन मानक निर्धारित करेगा जोकि पत्तन द्वारा प्रासंगिक पाया गया है। वीओसीपीटी ने कंटेनर प्रहस्तन सहित और पोत साइड सेवाओं के लिए औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट टनों में/दिन के रूप में कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए कार्यनिष्पादन मानक प्रतिबद्ध किया है, पत्तन ने पोतों के औसत वापिसी समय और पोतों के औसत पूर्व-बर्थिंग समय, बर्थ में

निष्क्रिय समय का प्रतिशत रूप में कार्यनिष्पादन मानक प्रस्तावित किए हैं। किन्हीं अन्य पैरामीटरों के अधीन, पत्तन ने कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर दक्षिण भारत गेटवे टर्मिनल प्रा0 लि0 (डीबीजीटीपीएल) द्वारा बर्थ सं. 8 में प्रहस्तित कोयला परंपरागत और कॉपर सेंद्रित, बर्थ सं. 3 एवं 4 में परंपरागत कोयला, बर्थ सं. 9 में परंपरागत कोयला प्रहस्तन और सीजे 1 एवं 2 में अभियंत्रिकृत कोयला के लिए सकल उत्पादकता टनों/दिन के रूप में भी कार्यनिष्पादन मानकों का प्रस्ताव किया है।

इस संबंध में, यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पत्तन द्वारा प्रतिबद्ध कार्यनिष्पादन मानक पत्तन परिसर के भीतर पत्तन द्वारा स्वयं के उपस्कर द्वारा किए गए परिचालनों के लिए सुविचारित किया जाना है और उसके उपस्कर के साथ पत्तन में सेवाएं प्रदान करने वाले बीओटी परिचालक पर लागू नहीं होंगे जिसके लिए प्रासंगिक आदेश में पृथक कार्यनिष्पादन मानक पहले ही निर्धारित किए गए हैं। बर्थ सं. 9 के संबंध में जोकि एचएमसी की तैनाती के लिए आईएमसीओएलए क्रेन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (आईसीसीपीएल) को लाइसेंस आधार पर दिया बताया गया है, आईसीसीपीएल का प्रशुल्क वीओसीपीटी में एचएमसी की तैनाती के लिए टीएमएपी द्वारा अनुमोदित पृथक प्रशुल्क द्वारा शसित किया जाएगा। इसलिए, बर्थ सं. 9 के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक यहां शामिल नहीं किए गए हैं।

इसके अलावा, वीओसीपीटी द्वारा बर्थ सं. 8 डीबीजीटीपीएल को कंटेनर प्रहस्तन के लिए बीओटी आधार पर दिया गया है। डीबीजीटीपीएल के लिए प्रशुल्क उक्त बर्थ हेतु कंटेनर टर्मिनल के लिए टीएमएपी द्वारा अनुमोदित पृथक प्रशुल्क द्वारा शसित किया जाएगा। इसलिए, बर्थ सं. 8 के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक भी पत्तन के दरमान के सामान्य संशोधन के लिए कार्यनिष्पादन मानकों का हिस्सा नहीं बन सकता।

इसके अलावा, पत्तन ने प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानकों में उल्लेख किया है कि कॉपर सेंद्रित डीबीजीटीपीएल द्वारा बर्थ सं. 8 में प्रहस्तित किया जाता है। यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बर्थ सं. 8 के लिए, पत्तन का प्रस्ताव कंटेनर प्रहस्तन के लिए था। इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अपक्रं प्रशुल्क कंटेनर प्रहस्तन के लिए है जैसाकि पत्तन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। परिचालक डीबीजीटीपीएल के नाम से अधिसूचित प्रशुल्क कंटेनर प्रहस्तन के लिए भी है। उक्त बर्थ में कंटेनर प्रहस्तन से इतर कार्गो के लिए डीबीजीटीपीएल द्वारा किए गए परिचालनों, यदि कोई हों, के लिए प्रशुल्क को इस प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त नहीं है।

उपर्युक्त संशोधन के अधीन, वीओसीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक जोकि प्रतिवेदित कार्यनिष्पादन मानकों से सीमांतक रूप से उच्चतर पाया गया है वर्ष 2015-16 में अर्जित किया गया है को पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित दरमान के साथ निर्धारित किया गया है।

(xxxv). प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.8 के अनुसार, दरमान को 1 जनवरी 2014 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में 100 प्रतिशत भिन्नता की सीमा तक मुद्रास्फीति में प्रत्येक वर्ष सूचकांकित किया जाएगा और समायोजित सूचकांकित दरमान प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.8 के साथ पठित प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 3.2 के अनुसार, डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत पर दरमान में वार्षिक सूचकांकन महापत्तन न्यासों द्वारा प्रतिबद्ध कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन है। यदि पत्तन विशेष कार्यनिष्पादन मानकों को पूरा नहीं करता है तो अगले वर्ष के दौरान सूचकांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कहना प्रासंगिक है कि वर्ष 2015-16 के लिए वर्तमान मामला सूचकांकन एआरआर और दरमान तैयार करने के प्रयोजन के लिए पहले ही सुविचारित किया जा चुका है। दरमान में अगला वार्षिक सूचकांकन वर्ष 2016-17 में कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा। ऐसी स्थिति में, दरमान में इस आशय का एक नोट शामिल किया गया है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा घोषित किए जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत पर स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन है।

वार्षिक सूचकांकन दरमान के साथ अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानकों को वीओसीपीटी द्वारा अर्जित किए जाने के अधीन 1 अप्रैल 2017 से होगा। यदि दरमान में निर्धारित कार्यनिष्पादन मानक अर्जित नहीं किए जाते हैं तो उस वर्ष विशेष के लिए दरमान में सूचकांकन नहीं होगा। प्रशुल्क नीति, 2015 विनिर्दिष्ट करती है कि दरमान में वार्षिक सूचकांकन कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन स्वचालित होगा। इसके लिए महापत्तन न्यासों को इस प्राधिकरण का रुख नहीं करना होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पत्तन को यह सलाह दी जाती है कि वह केलेंडर वर्ष के अंत के एक माह के भीतर पत्तन द्वारा प्रतिबद्ध स्तर पर इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानकों के सापेक्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए अर्जित कार्यनिष्पादन मानक संबंध उपयोक्ताओं एवं इस प्राधिकरण को घोषित करे। यदि इस प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानक पत्तन द्वारा अर्जित नहीं किए जाते हैं तो पत्तन इस प्राधिकरण द्वारा घोषित डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत पर इस दरमान में निर्धारित दरों को स्वतः ही सूचकांकित कर सकता है और सूचकांकित दरमान लागू कर सकता है जिसके बारे में वीओसीपीटी को संबंध उपयोक्ताओं तथा इस प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

(xxxvi). वीओसीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता आखिरी बार 31 अगस्त 2016 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, विस्तारित की गई थी। पत्तन ने अपने पत्र दिनांक 26 अगस्त 2016 द्वारा 31 अगस्त 2016 के बाद इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरें अधिसूचित किए जाने तक पेंशन निधि लेवी सहित मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार की मांग की थी। दरमान 10 अक्टूबर 2016 को अधिसूचित किया गया है जोकि दरमान की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा। ऐसी स्थिति में, 6.5 प्रतिशत की पेंशन निधि लेवी और सीएचडी के लिए पेंशन निधि लेवी सहित मौजूदा दरमानों को समाप्ति की तारीख से दरमान संशोधित किए जाने तक विस्तारित किया माना गया है जैसाकि पत्तन द्वारा मांगी की गई थी। पेंशन निधि लेवी की वैधता में विस्तार पिछले विस्तार आदेश के समय वीओसीपीटी द्वारा प्रतिवेदित घाटा स्थिति पर आधारित है, जैसाकि पहले बताया गया है।

(xxxvii). वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 3.8 के अनुसार, अधिसूचित दरमान भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 3 वर्षों के लिए वैध रहेगा। इसलिए, और चूंकि प्रशुल्क नीति, 2015 तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों में प्रतिवेदित वास्तविकताओं पर एआरआर के आधार पर प्रशुल्क के परिकलन की अपेक्षा करती है, इसलिए संशोधित दरमान की वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गई है।

(xxxviii). (क). प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 8.1 के अनुसार, दरमानों में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं; रियायतें तथा छूट निम्नतम स्तर हैं। वीओसीपीटी कम दरें वसूल करने और/अथवा उच्चतर रियायतें तथा छूट प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(ख). जैसाकि पहले बताया गया है, प्रशुल्क नीति 2015 के अनुसार, यह वीओसीपीटी को सुनिश्चित करना है कि दरमान में संशोधन के परिणामस्वरूप पत्तन को यातायात का नुकसान नहीं हो।

- (ग). यदि रिकार्ड में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो वीओसीपीटी भारत के राजपत्र में पारित आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर पर्याप्त औचित्य/कारण देते हुए निर्धारित प्रशुल्क की समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण का रुख कर सकता है।
- (घ). दरमानों को शासित करने वाली शर्तों में वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित औचित्य/स्पष्टीकरण के आधार पर अनुमोदन के लिए विचार कर सकता है। वीओसीपीटी भारत के राजपत्र में पारित आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर पर्याप्त औचित्य/कारण देते हुए निर्धारित प्रशुल्क की समीक्षा के लिए किन्हीं औचित्यपरक कारणों से इस प्राधिकरण का रुख कर सकता है।

15.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण वीओसीपीटी का संशोधित दरमान तथा कार्यनिष्पादन मानक अनुमोदित करता है जिसे अलग से अधिसूचित किया गया है। संशोधित दरमान तथा संशोधित दरमान को लागू करने पर शासित होने वाली शर्तें प्रभावी होने की तारीख वही रहेगी जोकि संशोधित दरमान तथा कार्यनिष्पादन मानक अधिसूचित करते हुए पृथक आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2016 में पहले से दर्शाई गई है और 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद प्रदत्त अनुमोदन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से विस्तारित नहीं किया जाता है।

15.2. वीओसीपीटी ने कंटेनर प्रहस्तन के मामले में औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, औसत फेरे प्रति घंटा के अनुसार कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए कार्यनिष्पादन मानक की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पोत साइड सेवाओं के लिए, पत्तन ने पोतों के औसत वापिसी समय तथा पोतों के औसत पूर्व-बर्थिंग समय के रूप में कार्यनिष्पादन मानक प्रतिबद्ध किए हैं।

15.3. प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.8 में यथा उपलब्ध करवाया गया दरमान का सूचकांकन प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 3.2 के साथ पढ़ा जाना है। यदि वीओसीपीटी कार्यनिष्पादन मानक पूर्ण नहीं करता है तो वीओसीपीटी अगले वर्ष के दौरान सूचकांकन के लिए योग्य नहीं है।

15.4. प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 7.1 के अनुसार, महापत्तन न्यास इस प्राधिकरण को कार्गो यातायात, जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, जलयानों का औसत वापिसी समय, औसत पूर्व-बर्थिंग प्रतीक्षा समय एवं इसके प्रत्येक बर्था के लिए वसूल किए गए प्रशुल्क पर वार्षिक रिपोर्टें भेजेगा। वार्षिक रिपोर्टें प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद 60 दिनों के भीतर जमा की जाएंगी। कोई अन्य सूचना जो इस प्राधिकरण अपेक्षा की जाएगी उसे भी समय-समय पर प्रेषित करना होगा।

15.5. वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 4 के अनुसार, यह प्राधिकरण महापत्तन न्यासों से उसे प्राप्त हुई सभी सूचना प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 7.1 के अधीन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन-III/4/असा./319/16(143)]

अनुबंध - I

प्रपत्र - 1

पत्तन परिचालनों के लिए वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन (कार्गो प्रहस्तन प्रमाण (सीएचडी) अतिरिक्त)				
रु० लाखों में				
क्र.सं.	विवरण	वाई 1 (2011-12)	वाई 2 (2012-13)	वाई 3 (2013-2014)
(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	9,081.42	9,618.80	10,479.36
(ii).	प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	5,221.51	5,729.93	6,816.73
(iii).	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)	4,565.21	5,545.57	5,740.22
	कुल व्यय 1 = (i)+(ii)+(iii)	18,868.14	20,894.30	23,036.31
(2).	घटाएं समायोजन:			

(i).	संपदा संबंधित व्यय			
	(क). परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	636.24	463.86	1,377.83
	(ख). आर्बिट्रेट प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	647.64	619.98	899.99
	(ग). आर्बिट्रेट एफएमई	334.39	384.23	428.09
	उपजोड़ 2 (i)=[(क)+(ख)+(ग)]	1,618.27	1,468.07	2,705.91
(ii).	ऋणों पर ब्याज	-	-	-
(iii).	एकमुस्त व्ययों, यदि कोई हो, का 4/5वां जैसे मजदूरी की बकाया राशियां, पेंशन/ग्रेजुटी की बकाया राशियां, एक्सग्रेसिया की बकाया राशियां आदि (प्रत्येक मद की सूची बनाए)			
	(क).	-	-	-
	(ख).	-	-	-
	(ग).	-	-	-
	उपजोड़ 2 (iii)=[(क)+(ख)+(ग)]	-	-	-
(iv).	पेंशन निधि में अंशदान का 4/5वां	1,300.97	640.00	1,720.00
(v).	परिचालन व्यय तथा मूल्यहास के जोड़ के 25 प्रतिशत से अधिक प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	1,804.84	2,008.71	2,837.17
(vi).	केपिटिव बर्ष के प्रशुल्क निर्धारण हेतु प्रासंगिक व्यय, यदि कोई हो, प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन शासित			
	(क). परिचालन व्यय	-	-	-
	(ख). मूल्यहास	58.54	58.83	76.05
	(ग). आर्बिट्रेट प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-	-
	(घ). आर्बिट्रेट एफएमई	-	-	-
	उपजोड़ 2 (vi) = [(क)+(ख)+(ग)+(घ)]	58.54	58.83	76.05
	2 का जोड़ = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	4,782.62	4,175.61	7,339.13
(3).	कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय (3 = 1-2)	14,085.52	16,718.69	15,697.19
(4).	क्र.सं. 3 के औसत व्यय = [वाई1 + वाई2 + वाई3] / 3			15,500.46
(5).	नियोजित पूंजी			
	(i). निवल अचल परिसंपत्तियां 31-03-2014 के अनुसार (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			88,644.92
	(ii). जोड़ें: प्रगतिधीन कार्य 31-03-2014 के अनुसार (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			9,980.39
	(iii). घटाएं: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31-03-2014 को संपदा गतिविधि से संबंधित अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य			650.69
	(iv). लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को बीओटी परिचालक को अंतरित अचल परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, का निवल मूल्य (VII बर्थ रु 2637.70 लाख + VIII बर्थ रु 2375.04 लाख+एनसीबी-1 1732.05)			6,744.79
	(v). घटाएं: प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन केपिटिव बर्षों, यदि कोई हों, के लिए सुविचारित किए जाने वाले लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य			-
	(vi). जोड़ें: वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.5 में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार कार्यगत पूंजी			
	(क). वस्तुसूची			257.19
	(ख). विविध देनदारियां			228.39
	(ग). रोकड़			1,534.78
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़			2,020.35
	(vii). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)(d)]			93,250.18
(6).	क्र.सं. 5(vii) पर 16 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ			14,920.03
(7).	31 मार्च 2014 को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) [(4)+ (6)]			30,420.49
(8).	वर्ष 2014-15 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 6% (7*1.06)			32,245.72
(9).	वर्ष 2015-16 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 3.82% (7*1.0382)			33,477.51
(10).	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)			33,477.51
	घटाएं: 31-3-2014 को एस्को खाते के अधीन उपलब्ध शेषजमा			5,637.03
	निवल एआरआर			27,840.48
(11).	अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित सूचकांकित दरमान पर राजस्व अनुमानन			27,840.87

अनुबंध - II

सीएचडी के अतिरिक्त पत्तन परिचालन के लिए वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित और टीएमपी द्वारा संशोधित प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन				
क्र.सं.	विवरण	वाई 1 (2011-12)	वाई 2 (2012-13)	वाई 3 (2013-2014)

(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	9,081.42	9,618.80	10,479.36
(ii).	प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	5,221.51	5,729.93	6,816.73
(iii).	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)	4,565.21	5,545.57	5,740.22
	कुल व्यय 1 = (i)+(ii)+(iii)	18,868.14	20,894.30	23,036.31
(2).	घटाएं समायोजन:			
(i).	संपदा संबंधित व्यय			
	(क). परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	636.24	463.86	1,377.83
	(ख). आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	647.64	619.98	899.99
	(ग). आबंटित एफएमई	334.39	384.23	428.09
	उपजोड़ 2 (i) = [(क)+(ख)+(ग)]	1,618.27	1,468.07	2,705.91
(ii).	ऋणों पर ब्याज	-	-	-
(iii).	एकमुश्त व्ययों, यदि कोई हो, का 4/5वां जैसे मजदूरी की बकाया राशियां, पेंशन/ग्रेजुटी की बकाया राशियां, एक्सग्रेशिया की बकाया राशियां आदि (प्रत्येक मद की सूची बनाएं)			
	(क).	-	-	-
	(ख).	-	-	-
	(ग).	-	-	-
	उपजोड़ 2 (iii) = [(क)+(ख)+(ग)]	-	-	-
(iv).	पेंशन निधि में अंशदान का 4/5वां	1,300.97	640.00	1,720.00
(v).	परिचालन व्यय तथा मूल्यहास के जोड़ के 25 प्रतिशत से अधिक प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	833.53	1,206.35	1,849.00
(vi).	केपिटिव बर्थ के प्रशुल्क निर्धारण हेतु प्रासंगिक व्यय, यदि कोई हो, प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन शासित			
	(क). परिचालन व्यय	-	-	-
	(ख). मूल्यहास	58.54	58.83	76.05
	(ग). आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-	-
	(घ). आबंटित एफएमई	-	-	-
	उपजोड़ 2 (vi) = [(क)+(ख)+(ग)+(घ)]	8.54	8.83	76.05
	2 का जोड़ = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	3,811.31	3,373.25	6,350.96
(3).	कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय (3 = 1-2)	15,056.83	17,521.06	16,685.35
(4).	क्र.सं. 3 के औसत व्यय = [वार्ड 1 + वार्ड 2 + वार्ड 3] / 3			16,421.08
(5).	नियोजित पूंजी			
	(i). निवल अचल परिसंपत्तियां 31-03-2014 के अनुसार (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)		88,644.92	
	(ii). जोड़ें: प्रगतिधीन कार्य 31-03-2014 के अनुसार (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)		9,980.39	
	(iii). घटाएं: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31-03-2014 को संपदा गतिविधि से संबंधित अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य		650.69	
	(iv). लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को बीओटी परिचालक को अंतरित अचल परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, का निवल मूल्य (VII बर्थ रु 2637.70 लाख + VIII बर्थ रु 2375.04 लाख+एनसीबी-1 1732.05)		6,744.79	
	(v). घटाएं: प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन केपिटिव बर्थों, यदि कोई हों, के लिए सुविचारित किए जाने वाले लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य			-
	(vi). जोड़ें: वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.5 में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार कार्यगत पूंजी			
	(क). वस्तुसूची			257.19
	(ख). विविध देनदारियां			228.39
	(ग). रोकड़			1,534.78
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़			2,020.35
	(vii). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)(d)]			93,250.18
(6).	क्र.सं. 5(vii) पर 16 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ			14,920.03
(7).	31 मार्च 2014 को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) [(4)+(6)]			31,341.11
(8).	वर्ष 2014-15 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 6% (7*1.06)			33,221.57
(9).	वर्ष 2015-16 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में			34,490.64

	सूचकांकन अर्थात् @ 3.82% (7*1.0382)	
(10).	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	34,490.64
(11).	अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित दरमान पर वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित राजस्व	27,840.87

अनुबंध - III

प्रपत्र-1 (सीएचडी)

कार्गो ग्रहस्तन प्रमाण (सीएचडी) के लिए वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन				
क्र.सं.	विवरण	वाई 1 (2011-12)	वाई 2 (2012-13)	रु० लाखों में वाई 3 (2013-2014)
(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	5,165.96	5,753.90	5,845.41
(ii).	प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	-	-	-
(iii).	वित्त और विविध व्यय (एफएमई) लेखों के अनुसार	1,999.90	1,353.06	1,119.98
(iv).	घटाएँ पेंशन निधि में अंशदान	354.00	294.98	-
(v).	108 एफ एंड एम व्यय	1,645.90	1,058.08	1,119.98
(vi).	जोड़ें: ओपनिंग में पेंशन निधि कमी	6,281.76	10,720.69	21,136.00
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)+(v)+(vi)	13,093.62	17,532.67	28,101.39
(2).	घटाएँ समायोजन:			
(i).	संपदा संबंधित व्यय			
	(क). परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	-	-	-
	(ख). आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-	-
	(ग). आबंटित एफएमई	-	-	-
	उपजोड़ 2 (i)=[(क)+(ख)+(ग)]	-	-	-
(ii).	ऋणों पर ब्याज	-	-	-
(iii).	एकमुश्त व्ययों, यदि कोई हो, का 4/5वां जैसे मजदूरी की बकाया राशियाँ, पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशियाँ, एक्सग्रेशिया की बकाया राशियाँ आदि (प्रत्येक मद की सूची बनाएँ)			
	(क). मजदूरी संशोधन बकाया राशियों का भुगतान	-	-	-
	(ख). पेंशन की बकाया राशियाँ/पेंशन का कम्प्यूटेशन	-	-	-
	(ग). ग्रेच्युटी की बकाया राशियाँ	-	-	-
	उपजोड़ 2 (iii)=[(क)+(ख)+(ग)]	-	-	-
(iv).	पेंशन निधि में अंशदान का 4/5वां	5,025.41	8,576.55	16,908.80
(v).	परिचालन व्यय तथा मूल्यहास के जोड़ के 25 प्रतिशत से अधिक प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	-	-	-
(vi).	केपिटिव बर्ष के प्रशुल्क निर्धारण हेतु प्रासंगिक व्यय, यदि कोई हो, प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन शासित			
	(क). परिचालन व्यय	-	-	-
	(ख). मूल्यहास	-	-	-
	(ग). आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-	-
	(घ). आबंटित एफएमई	-	-	-
	उपजोड़ 2 (vi) = [(क)+(ख)+(ग)+(घ)]	-	-	-
	2 का जोड़ = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	5,025.41	8,576.55	16,908.80
(3).	कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय (3 = 1-2)	8,068.21	8,956.12	11,192.59
(4).	क्र.सं. 3 के औसत व्यय = [वाई1 + वाई2 + वाई3] / 3			9,405.64
(5).	नियोजित पूंजी			
	(i). निवल अचल परिसंपत्तियाँ 31-03-2014 के अनुसार (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)		7.77	
	(ii). जोड़ें: प्रगतिधीन कार्य 31-03-2014 के अनुसार (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			-
	(iii). घटाएँ: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31-03-2014 को संपदा गतिविधि से संबंधित अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य			-
	(iv). लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को वीओटी परिचालक को अंतरित अचल परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, का निवल मूल्य			-
	(v). घटाएँ: प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन केपिटिव बर्षों, यदि कोई हों, के लिए सुविचारित किए जाने वाले लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य			-
	(vi). जोड़ें: वार्षिक दिशानिर्देशों के खंड 2.5 में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार कार्यगत पूंजी			
	(क). वस्तुसूची			-
	(ख). विविध देनदारियाँ			-
	(ग). रोकड़		580.38	

	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़	580.38
	(vii). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)(d)]	588.15
(6).	क्र.सं. 5(vii) पर 16 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	94.10
(7).	31 मार्च 2014 को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) [(4)+ (6)]	9,499.74
(8).	वर्ष 2014-15 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 6% (7*1.06)	10,069.73
(9).	वर्ष 2015-16 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 3.82% (8*1.0382)	10,454.39
(10).	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	10,454.39
(11).	अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित दरमान पर वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित राजस्व	10,454.39

अनुबंध - IV

कार्गो प्रहस्तन प्रमाण के लिए वीओसीपीटी द्वारा प्रेषित और टीएमपी द्वारा सुविचारित प्रशुल्क नीति 2015 के अधीन वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन				
रु० लाखों में				
क्र.सं.	विवरण	वाई 1 (2011-12)	वाई 2 (2012-13)	वाई 3 (2013-2014)
(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	5,165.96	5,753.90	5,845.41
(ii).	प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	-	-	-
(iii).	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई) लेखों के अनुसार	1,999.90	1,353.06	1,119.98
	कुल व्यय 1 = (i)+(ii)+(iii)	7,165.86	7,106.96	6,965.39
(2).	घटाएं समायोजन:			
(i).	संपदा संबंधित व्यय			
	(क). परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	-	-	-
	(ख). आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-	-
	(ग). आबंटित एफएमई	-	-	-
	उपजोड़ 2 (i) = [(क)+(ख)+(ग)]	-	-	-
(ii).	ऋणों पर ब्याज	-	-	-
(iii).	एकमुस्त व्ययों, यदि कोई हो, का 4/5वां जैसे मजदूरी की बकाया राशियां, पेंशन/ग्रेज्युटी की बकाया राशियां, एक्सप्रेमिया की बकाया राशियां आदि (प्रत्येक मद की सूची बनाएं)			
	(क). मजदूरी संशोधन बकाया राशियों का भुगतान	-	-	-
	(ख). पेंशन की बकाया राशियां/पेंशन का कम्प्यूटेशन	-	-	-
	(ग). ग्रेज्युटी की बकाया राशियां	-	-	-
	उपजोड़ 2 (iii) = [(क)+(ख)+(ग)]	-	-	-
(iv).	पेंशन निधि में अंशदान का 4/5वां	283.20	235.98	-
(v).	परिचालन व्यय तथा मूल्यहास के जोड़ के 25 प्रतिशत से अधिक प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्यय	-	-	-
(vi).	केपिटव बर्ध के प्रशुल्क निर्धारण हेतु प्रासंगिक व्यय, यदि कोई हो, प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन शासित			
	(क). परिचालन व्यय	-	-	-
	(ख). मूल्यहास	-	-	-
	(ग). आबंटित प्रबंधन तथा प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-	-
	(घ). आबंटित एफएमई	-	-	-
	उपजोड़ 2 (vi) = [(क)+(ख)+(ग)+(घ)]	-	-	-
	2 का जोड़ = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	283.20	235.98	-
(3).	कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय (3 = 1-2)	6,882.66	6,870.98	6,965.39
(4).	क्र.सं. 3 के औसत व्यय = [वाई1 + वाई2 + वाई3] / 3			6,906.34
(5).	नियोजित पूंजी			
	(i). निवल अचल परिसंपत्तियां 31-03-2014 के अनुसार (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			7.77
	(ii). जोड़े: प्रगतिधीन कार्य 31-03-2014 के अनुसार (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			-
	(iii). घटाएं: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार 31-03-2014 को संपदा गतिविधि से संबंधित अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य			-
	(iv). लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को बीओटी परिचालक को अंतरित अचल परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, का निवल मूल्य			-

	(v). घटाएं: प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 2.10 के अधीन केपटिव बर्थों, यदि कोई हों, के लिए सुविचारित किए जाने वाले लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 31 मार्च 2014 को अचल परिसंपत्तियों का निवल मूल्य	-
	(vi). जोड़ें: वार्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.5 में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार कार्यगत पूंजी	
	(क). वस्तुसूची	-
	(ख). विविध देनदारियां	-
	(ग). रोकड़	580.38
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़	580.38
	(vii). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)(d)]	588.15
(6).	क्र.सं. 5(vii) पर 16 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	94.10
(7).	31 मार्च 2014 को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) [(4)+ (6)]	7,000.45
(8).	वर्ष 2014-15 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 6% (7*1.06)	7,420.47
(9).	वर्ष 2015-16 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन अर्थात् @ 3.82% (8*1.0382)	7,703.93
(10).	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	7,703.93
(11).	वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित और टीएएमपी द्वारा सुविचारित राजस्व (टिप्पणी देखें)	10,454.39
	टिप्पणी: 51.20 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि पर वीओसीपीटी द्वारा अनुमानित राजस्व ₹0 10,454.39 लाख है। प्राधिकरण द्वारा विचार करते हुए इसपर विचार किया गया है कि राजस्व कमी समग्र पतन के लिए है। समग्र पतन के लिए समग्र एआरआर ₹0 42,195.57 लाख (अर्थात् ₹0 34,490.64 लाख पतन के लिए + ₹0 7,703.93 लाख सीएचडी से)। वीओसीपीटी द्वारा मूल्यांकित पतन परिचालन से राजस्व अनुमान ₹0 14,353.70 लाख छोड़ते हुए ₹0 27,840.84 लाख है। 51.20 प्रतिशत पर सीएचडी के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क पर राजस्व ₹0 10,454.39 लाख है जोकि समग्र पतन के लिए अधिकतम सूचकांकित के भीतर है।	

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Mumbai, the 21st November, 2016

NOTIFICATION

No. TAMP/29/2016-VOCPT .—This Authority, in exercise of the powers conferred on it under Sections 48, 49 & 50 of the Major Port Trusts Act, 1963, had disposed of the proposal received from the V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) for general revision of its Scale of Rates, in the Meeting of this Authority held on 17 September 2016. However, considering the time involved for notifying (Speaking) Order along with the revised Scale of Rates, this Authority decided to notify only the revised Scale of Rates immediately. Accordingly, the Scale of Rates approved on 17 September 2016 was notified in the Gazette of India on 10 October 2016 vide Gazette No.370. It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies the reasoned Speaking Order connected with disposal of the proposal of the VOCPT for general revision of its Scale of Rates as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/29/2016-VOCPT

V.O. Chidambaranar Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 17th day of September 2016)

This case relates to the proposal dated 7 May 2016 received from V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR).

2.1. The existing SOR of VOCPT was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/47/2012-VOCPT dated 04 August 2014 which was notified in the Gazette of India on 19 August 2014 with Gazette no.243. The validity of the existing SOR of the VOCPT prescribed in the said Order was till 31 March 2016.

2.2. This Authority passed an Order dated 19 May 2016 extending the validity of existing SOR of VOCPT including the Pension Fund Levy prescribed in the existing SOR till 31 August 2016 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier for the reasons stated in the Order. While extending the validity of the SOR, it was stated that the treatment of additional surplus, if any, accruing to the VOCPT for the period beyond 1 April 2016 will be governed by the New Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015.

3.1. The VOCPT under cover of its letter dated 07 May 2016 has submitted its proposal for General Revision of its Scale of Rates following Tariff Policy, 2015 along with draft SoR and Proposed Performance Standards.

3.2. The VOCPT has made the following submissions in its proposal for general revision of its SOR:

- (i). The Average revenue Requirement (ARR) is separately assessed for port and CHD.
- (ii). The VOCPT has furnished detailed computation of Annual Revenue Requirement (ARR) under Form 1 and Revenue estimation at the proposed rate in Form 3.
- (a). A summary position of ARR computation furnished by VOCPT for Port (excluding CHD) is tabulated below:

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Description	Y1 (2011-12)	Y1 (2012-13)	Y2 2013-2014)
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	9,081.42	9,618.80	10,479.36
(ii).	Management & general Overheads	5,221.51	5,729.93	6,816.73
(iii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	4,565.21	5,545.57	5,740.22
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)+(iii)	18,868.14	20,894.30	23,036.31
(2).	Less Adjustments:			
(i).	Estate related expenses			
	(a). Operating expenses (including depreciation)	636.24	463.86	1,377.83
	(b). Allocated Management & Administrative Overheads	647.64	619.98	899.99
	(c). Allocated FME	334.39	384.23	428.09
	Subtotal 2 (i)=[(a)+(b)+(c)]	1,618.27	1,468.07	2,705.91
(ii).	Interest on loans	-	-	-
(iii).	4/5th of One time expenses, if any like arrears of wages, arrears of pension / gratuity, arrears of exgratia payment, etc. (list out each of the items)			
	(a).	-	-	-
	(b).	-	-	-
	(c).	-	-	-
	Subtotal 2 (iii) = [(a)+(b)+(c)]	-	-	-
(iv).	4/5th of the Contribution to the Pension Fund	1,300.97	640.00	1,720.00
(v).	Management and General overheads over & above 25% of the aggregate of the operating expenditure and depreciation	1,804.84	2,008.71	2,837.17
(vi).	Expenses relevant for tariff fixation of Captive Berth, if any governed under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.			
	(a). Operating Expenses	-	-	-
	(b). Depreciation	58.54	58.83	76.05

	(c). Allocated Management and Administrative Overheads	-	-	-
	(d). Allocated FME	-	-	-
	Subtotal 2 (vi) = [(a)+(b)+(c)+(d)]	58.54	58.83	76.05
	Total of 2 = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	4,782.62	4,175.61	7,339.13
(3).	Total Expenditure after Total Adjustments (3 = 1-2)	14,085.52	16,718.69	15,697.19
(4).	Average Expenses of SI. No. 3 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3			15,500.46
(5).	Capital Employed			
	(i). Net Fixed Assets as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)			88,644.92
	(ii). Add: Work in Progress as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)			9,980.39
	(iii). Less: Net value of Fixed assets related to Estate activity as on 31.03.2014 as per Audited Annual Accounts.			650.69
	(iv). Less: Net value of fixed assets, if any, transferred to BOT operator as on 31 March 2014 as per Audited Accounts. (VII Berth `2637.70 Lakhs + VIII Berth `2375.04 Lakhs+ NCB-1 1732.05)			6,744.79
	(v). Less: Net value of fixed assets as on 31 March 2014 as per Audited Accounts relevant to be considered for captive berths, if any, under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.			-
	(vi). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.5. of the Working Guidelines			
	(a). Inventory			257.19
	(b). Sundry Debtors			228.39
	(c). Cash			1,534.78
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)			2,020.35
	(vii). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)(d)]			93,250.18
(6).	Return on Capital Employed 16% on SI. No. 5(vii)			14,920.03
(7).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2014 [(4)+ (6)]			30,420.49
(8).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 i.e. @ 6% (7*1.06)			32,245.72
(9).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2015-16 i.e. @ 3.82% (7*1.0382)			33,477.51
(10).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)			33,477.51
	Less: Balance available under Escrow A/c as on 31.3.2014			5,637.03
	Net ARR			27,840.48
(11).	Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at SI No. 10 above			27,840.87

- (b). A summary position of ARR computation furnished by VOCPT for CHD is tabulated below:
(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Description	Y1 (2011-12)	Y1 (2012-13)	Y2 (2013-2014)
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	5,165.96	5,753.90	5,845.41
(ii).	Management & general Overheads	-	-	-
(iii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME) as per Accounts	1,999.90	1,353.06	1,119.98
(iv).	Less: Contribution to Pension Fund	354.00	294.98	-
(v).	Balance F & M Expenditure	1,645.90	1,058.08	1,119.98
(vi).	Add: Pension Fund shortfall in the opening	6,281.76	10,720.69	21,136.00
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)+(v)+(vi)	13,093.62	17,532.67	28,101.39
(2).	Less Adjustments:			
(i).	Estate related expenses			
(a).	Operating expenses (including depreciation)	-	-	-

	(b). Allocated Management & Administrative Overheads	-	-	-
	(c). Allocated FME	-	-	-
	Subtotal 2 (i)=[(a)+(b)+(c)]	-	-	-
(ii).	Interest on loans	-	-	-
(iii).	4/5th of One time expenses, if any like arrears of wages, arrears of pension / gratuity, arrears of exgratia payment, etc. (list out each of the items)			
	(A). Payment of Wage revision arrears	-		
	(B). Arrears of Pension/Commutation of Pension	-		
	(C). Arrears of Gratuity	-		-
	Subtotal 2 (iii) = [(a)+(b)+(c)]	-	-	-
(iv).	4/5th of the Contribution to the Pension Fund	5,025.41	8,576.55	16,908.80
(v).	Management and General overheads over & above 25% of the aggregate of the operating expenditure and depreciation	-	-	-
(vi).	Expenses relevant for tariff fixation of Captive Berth, if any governed under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.			
	(a). Operating Expenses	-	-	-
	(b). Depreciation	-	-	-
	(c). Allocated Management and Administrative Overheads	-	-	-
	(d). Allocated FME	-	-	-
	Subtotal 2 (vi) = [(a)+(b)+(c)+(d)]	-	-	-
	Total of 2 = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	5,025.41	8,576.55	16,908.80
(3).	Total Expenditure after Total Adjustments (3 = 1-2)	8,068.21	8,956.12	11,192.59
(3 a)	Total	8,068.21	8,956.12	11,192.59
(4).	Average Expenses of SI. No. 3 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3		9,405.64	
(5).	Capital Employed			
	(i). Net Fixed Assets as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)		7.77	
	(ii). Add: Work in Progress as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)		-	
	(iii). Less: Net value of Fixed assets related to Estate activity as on 31.03.2014 as per Audited Annual Accounts.		-	
	(iv). Less: Net value of fixed assets, if any, transferred to BOT operator as on 31 March 2014 as per Audited Accounts.		-	
	(v). Less: Net value of fixed assets as on 31 March 2014 as per Audited Accounts relevant to be considered for captive berths, if any, under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.		-	
	(vi). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.5. of the Working Guidelines			
	(a). Inventory		-	
	(b). Sundry Debtors		-	
	(c). Cash		580.38	
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)		580.38	
	(vii). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)(d)]		588.15	
(6).	Return on Capital Employed 16% on SI. No. 5(vii)		94.10	
(7).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2014 [(4)+ (6)]		9,499.74	
(8).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 i.e. @ 6% (7*1.06)		10,069.73	
(9).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2015-16 i.e. @ 3.82% (8*1.0382)		10,454.39	
(10).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)		10,454.39	
(11).	Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at SI. No.10 above		10,454.39	

- (iii). As far as Port is concerned, due to higher Capital Employed and resultant increased ROCE, the Annual Revenue Requirement is much more than the earnings earned for the traffic handled in 2014-15 excluding the PPP traffic.
- (iv). (a). It is proposed to utilise the balance in the Escrow Account maintained by the VOCPT and the future accruals in the Escrow Account as deemed fit by the Board of Trustees of the VOCPT as per clause 2.11 of the working guidelines. An amount of ₹56.37 Crores is available in 2013-14, and hence is adjusted against the gross revenue requirement and net revenue requirement of ₹278.40 crores is considered.
- (b). Thus, in short, the ARR is arrived after deducting the balance in escrow fund as on 31 March 2014 and after applying relevant escalations for the years 2014-15 and 2015-16.
- (v). In respect of CHD, there is no surplus funds available to meet the huge shortfall in Pension and Gratuity Fund with respect to actuarial valuation. As a result, the clause 2.11 of the working guidelines providing for dispensing with Pension Fund Levy will result in heavy financial burden to CHD to meet the heavy shortfall in Pension and Gratuity Fund. There is no Escrow fund available in CHD, utilizing the same to meet the shortfall is not possible in CHD (which is to be self-sufficient as per Memorandum of Settlement dated 27.7.2011). Therefore, the shortfall in actuarial valuation is considered as expenditure in the total expenditure and hence, 1/5th of opening shortfall of each year is considered as expenditure to ensure continuous contribution to meet the shortfall. In short 1/5th of the opening shortfall is proposed for recovery. The treatment may please be considered by the Authority.
- (vi). To meet the estimated ARR of ₹27,840.48 lakhs from port operations and ₹ 10,454.39 lakhs from CHD the tariff revision proposed by VOCPT is follows:
- (a). Uniform hike of 27.70% is proposed by VOCPT in all tariff items for vessel related charges, cargo related charges and miscellaneous charges.
- (b). Existing Pension Fund levy of 6.5% is dispensed with.
- (c). The port has stated that after dispensing the Pension Fund levy, the net increase is 21.20% only.
- (d). As regards CHD, the VOCPT has proposed uniform increase of 51.20% for in all the tariff items.
- (e). The existing Pension Fund levy for CHD @ ₹ 25.10/- tonne is dispensed with.
- (f). The port has stated that after dispensing of pension fund levy the net increase in CHD is 2% for cargoes other than coal and salt and 13% for coal at coal jetty.
- (vii). (a). As per Clause 2.5 of the Tariff Policy, 2015, the traffic to be considered would be overall traffic estimated exclusive for the port for the year 2014-15. The port has stated that actual traffic handled is 324.14 lakh tonnes for 2014-15. The tonnage relating to PPP operations viz., VII Berth Container Terminal, VIII Berth Container Terminal and cargo handled by M/s.NLC Tamil Nadu Power Limited (NTPL) and the earnings from Pension Fund Levy and Dredging Levy in respect of the above PPP operators during the year 2014-15 are excluded.
- (b). The tariff of ₹ 38/- per M.T. for Thermal Coal is applied uniformly for all categories of Coal including Steaming (Non-coking) coal to avoid the problems in applying rate for Thermal Coal as it is felt that there was no necessary in differentiating the coal.
- (viii). (a). The VOCPT has in Form 3 furnished revenue estimation at the proposed tariff for the actual traffic of 2014-15.
- (b). The computation of ARR and revenue estimation attached to the proposal are certified by the practicing Chartered Accountant, as required by the Tariff Policy & Working Guidelines.

- (ix). The VOCPT has forwarded draft proposed Scale of Rates.
- (x). The Performance Standards proposed by VOCPT in Form - 6 are as follows:

Sl. No.	Performance Parameters	Proposed performance standards
(1).	Cargo Related Services	
(a)	Average Ship Berth day Output (in tonnes) in respect of Major Cargo groups	
1	Cashew Nuts In Bags	1,125
2	Caustic Soda Lye	3,750
3	Cement	1,500
4	Clinkers	5,250
5	Copper Concentrate	6,750
6	DAP	4,500
7	Diesel Oil	6,000
8	Furnace Oil IOC	7,500
9	Furnace Oil SPIC	2,250
10	Garnet Sand Bulk	6,000
11	General Cargo	1,875
12	Granite Stone	1,500
13	Gypsum In Bulk	9,000
14	Coal at III/IV Berth	9,000
15	Coal at IX Berth	18,000
16	Ilmenite	8,000
17	Iron And Steel Materials	3,600
18	Iron Ore	9,750
19	Lime Stones	7,500
20	Liquid Ammonia	3,750
21	Logs	3,450
22	Lpg	5,000
23	Machinaries	900
24	Maize	3,000
25	MOP	6,750
26	Naptha IOC	7,500
27	Naptha SPIC	3,000
28	Oil Cake/Copra	1,875
29	Palm Oil	3,000
30	Peas (Yellow)	5,250
31	Petroleum Coke	7,500
32	Phosphoric Acid	2,625
33	Rock Phosphate	7,500
34	Salt In Bags	1,875
35	Salt In Bulk	5,250
36	Stone Aggregate	2,400
37	Stone Dust	2,475
38	Stone Rough	3,900
39	Sugar In Bag	1,875
40	Sugar (Raw)	5,250
41	Sulphur	6,000
42	Sulphuric Acid	3,000
43	Coal at NCBI	18,750
44	Coal at Coal Jetty I&II	11,250
45	Urea	4,500
46	Vcm	2,250
47	Wheat	4,875
(b)	Average moves per hour (in TEUs) in respect of Containers	21
(2)	Vessel Related Services	
(a)	Average Turnaround Time of Vessels (in days)	3.70
(b)	Average Pre-Berthing Time of Vessels (in days)	1.50
(3)	Any other parameters found relevant by the Port	-

- (xi). As far as changes in the conditionalities are concerned, the VOCPT has stated the following regarding modification / insertion / deletion in the proposed SOR:

- (a). The existing separate entry for port dues for sailing vessel is proposed to be deleted.
- (b). In the definition of pilotage fee, words are added to state that pilotage fee covers maximum of two tugs. Tugs required more than two nos. will be charged separately.
- (c). A new Note 4 under schedule 2.4.2 is inserted prescribing the cargo wise output norms and performance standard. The port has proposed penalty and rebate in berth hire charges in respect of Coal vessels handled at Berth No.IX & VOC II & IV and for the remaining cargos except coal handed at Berth No.III & IV and Berth No.IX.
- (d). At present no minimum charges for the lower slab GRT is available in respect of shifting charges as in the cases of Pilotage and Berth hire charges. Hence a note is proposed to be incorporated under the schedule of Shifting charges that 25% of the minimum charges of Pilotage schedule for shifting berths in SBW/NBW and 50% of the minimum charges of Pilotage for shifting between SBW to NBW and vice versa. At present the charges is very meager in cases of lower level GRT vessels shifted.
- (e). A new note is inserted under berth hire schedule stating that if intimation for cancellation is received in advance before 24 hours of the time of services requested, there will be no penal berth hire charges; otherwise one day's berth hire is proposed to be levied.
- (f). The penalty for amendment in berthing schedule is proposed at a flat rate of ₹5,000/- per amendment. The port has stated that the proposed rate is in place of one day berth hire charges leviable for amendment in the berthing schedule.
- (g). The port has proposed to discontinue with advalorem wharfage prescribed in the existing SOR for a few items and has proposed wharfage rate on unit basis. ₹ 150/- per MT is proposed for Machineries and Machinery Parts and for the remaining cargoes, the existing wharfage rate of goods otherwise not specified at ₹ 42.00 per MT plus proposed increase totaling ₹ 53.40 per MT. [The SOR proposes ₹ 53.63 per MT and not ₹ 53.40 per MT stated by VOCPT].
- (h). Pollution cess on dusty cargoes discharged at the rate of ₹ 5/- per MT is proposed.

4.1. The VOCPT has confirmed that it has hosted draft SOR and proposed Performance Standards in its website as on 06 May 2016 as required by Clause 5.2 of the Tariff Policy, 2015 for comments of the Stakeholders.

4.2. The VOCPT was vide our letter dated 17 May 2015 requested to confirm that it has communicated about the same to all the relevant stakeholder / users and also intimate this Authority when action is completed. The VOCPT has confirmed this vide its letter dated 17 June 2016. The VOCPT has also furnished a copy of Board Resolution passed in the Board Meeting according approval for the proposal.

5.1. It is relevant to state here that in the meantime, Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.8/(15)2015-TAMP dated 11 May 2016 has decided to temporarily keep the earlier direction issued by the MOS vide its letter no.8/(15)2015-TAMP dated 17 September 2015 in abeyance till further orders and restore the policy direction issued by the (then) MSRTH vide its letter no.PR- 14019/29/2001-PG dated 1st/3rd January 2005 and 9 March 2005. The MOS has directed this Authority to appropriately prescribe the coastal cargo/ container/ vessel related charges levied at all Major Port Trusts and private operators authorized under Section 42(3) of the Major Port Trusts Act, 1963 immediately.

5.2. In view of the above direction issued by the MOS, this Authority passed an Order No.TAMP/4/2004-Genl dated 19 May 2016 keeping the Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 5 October 2015 passed by this Authority based on the direction issued by the MOS vide its letter no.8(15)2015-TAMP dated 17 September 2015 temporarily in abeyance till further orders from the MOS. Consequently, the Order no.TAMP/4/2004-Genl. dated 7 January 2005 and the amendment to the said Order dated 15 March 2005 based on the policy direction issued by the (then) MSRTH dated 1 January 2005 are restored as directed by the MOS.

5.3. The above direction from the MOS would have impact on the coastal vessel rates proposed by the VOCPT. Therefore, the VOCPT was requested vide our letter dated 20 June 2016 to review its proposal dated 7 May 2016 for general revision of its Scale of Rates based on the Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 19 May 2016 passed by this Authority and file a revised proposal. The VOCPT vide its email dated 2 July 2016 has revised draft SOR duly taking into consideration the amendment to coastal concession policy notified by this Authority vide Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 19 May 2016. The VOCPT has, however, retained the indexed ceiling ARR at ₹ 27,840.48 lakhs and the revenue estimates in Form-3 at ₹ 27,840.87 as estimated in its original proposal dated 7 May 2016.

5.4. The VOCPT vide its e-mail dated 2 July 2016 has forwarded its email to all Stakeholders/ users wherein it is stated that in pursuance of the Order of this Authority dated 19 May 2016, the draft Scale of Rates has been modified suitably proposing fixed rates for coastal vessels as per the practice prevailing prior to 1 November 2015 and the modified SOR is hosted on its website on 28 June 2016.

6. A copy each of comments received from the concerned users / user organisations on the subject proposal were forwarded to VOCPT as feedback information. The VOCPT vide its letter dated 15 June 2016 has furnished its reply.

7.1. The VOCPT has, subsequently, vide its letter No.FIN-OFFCT-SOR-REVIS-VI-15/D1450 dated 13 June 2016 proposed to handle automobiles through RoRo vessels & PCTC (Pure car & Truck carrier) considering the tariff available in Cochin Port at per unit basis. The tariff proposed by VOCPT is as follows:

- (i). The wharfage rate of ₹ 500/- for handling car below 1600 CC and ₹ 1000/- for handling car above 1600 CC is proposed.
- (ii). For vehicle with laden containers with trailer, the tariff is proposed to be collected at composite rate covering both vehicle and container separately collecting the rate of container as per prevailing Scale of Rates.

7.2. The port has confirmed that the wharfage rate newly proposed for automobiles and containers loaded in tractor handling through RoRo vessel is also incorporated in the modified proposed SOR hosted on its website. The port has requested all stakeholders / users to view the amendments made in the draft proposed SOR.

8. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, it was observed that there are certain information gaps / deficiency in the proposal of VOCPT. The VOCPT was, therefore, vide our letter dated 13 July 2016 requested to furnish requisite information/ revised working/ proposal by 20 July 2016. The VOCPT has subsequent to the joint hearing furnished additional information/ clarification vide its letter dated 9 August 2016 which is brought out in subsequent paragraph.

9.1. A joint hearing in this case was held on 11 July 2016 at the VOCPT premises. The VOCPT made a brief presentation of its proposal. At the joint hearing, the VOCPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions.

9.2. As agreed at the joint hearing, the VOCPT was requested vide our letter dated 19 July 2016 with subsequent reminder dated 25 July 2016 to take action on the following points:

- (i). Furnish reply to the clarifications/ information sought by us vide our letter dated 13 July 2016.
- (ii). Furnish comments on the written submissions made by DCW Limited and Tamilnadu Generation and Distribution Corporation Limited (TANGEDCO).
- (iii). The TANGEDCO has sought clarification from the port whether, Pollution cess will apply to coal handled at coal jetty I and II. The VOCPT has clarified that it will not apply. However, if coal jetty I and II create pollution, port wants to apply the proposed levy to these two coal jetties. In this backdrop, as agreed at the joint hearing, the port was to propose suitable modification in the conditionality in the proposed SOR.
- (iv). At the joint hearing, the VOCPT has stated that some fine tuning is required in the proposed productivity norms. The VOCPT was to furnish fine-tuned productivity norms and send the productivity norms as desired by the port by 18 July 2016 and also update it on its web site and intimate the users/ user associations.
- (v). At the joint hearing, the VOCPT has stated that a few expenses captured under the head Management and General Administration Overheads (MGAO) are relevant for all the activities of the port. As desired by the port, VOCPT was allowed to relook at the MGAO excluded in the estimate of ARR and respond by 18 July 2016.

10.1. With reference to the first point of action decided at the joint hearing, the VOCPT vide its letter dated 9 August 2016 has furnished its response to the additional information / clarification sought vide our letter dated 13 July 2016. A summary of the additional information / clarification sought by us and reply furnished by the port are tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarifications sought by us	Reply furnished by VOCPT																									
1.	General																										
(i).	Administrative Report for the year 2014-15 to be furnished as the Audited Annual Accounts for 2014-15 do not contain the traffic figures.	As required, a copy of Administration Report for the year 2014-15 along with commodity wise statement for the year 2014-15 is furnished since the Administration Report does not have detailed break up of cargo handled.																									
(ii).	The VOCPT vide its email dated 02 July 2016 has intimated about hosting of revised proposed Scale of Rates (SOR) on its website on 28 June 2016 and intimating the position to the stakeholders about the same. The port has, however, not furnished the revised proposed SOR. The port to furnish the same.	The revised draft SoR which has been uploaded in the Port website on 28.6.2016 incorporating the required modification with respect to the clarifications raised by the Authority is furnished.																									
2.	Annual Revenue Requirement (ARR) (FORM NO.1) (Port)																										
(i).	Estate Related Expenses (Sl.No.2(i)(b) & (c): The VOCPT has excluded `647.64 lakhs, ₹619.98 lakhs & ₹899.99 lakhs in the years 2011-12, 2012-13 & 2013-14 respectively towards allocated Management & administrative overheads for estate related activity and ₹334.39 lakhs, ₹384.23 lakhs and ₹428.09 lakhs are excluded towards allocated FME for estate activity. Note 2 and 3 under Form-1 require the port to furnish a working reconciling the amount reported in the Audited Annual Accounts and the figures considered in the cost statement. The VOCPT has not furnished requisite reconciliation working. VOCPT to provide the same.	Since the allocated Management and General Overheads and Finance & Miscellaneous Expenditure relating to Estate Activity is not available in the Audited Annual Accounts, the figures are derived from the Cost Statement of the relevant year and hence the figures of Operating Expenditure including depreciation relating to Estate Activity has been derived from Schedule-13 to Revenue Account of respective Audited Annual Accounts.																									
(ii).	<u>4/5th of one time expenses, if any like arrears of wages, arrears of pension/ gratuity, arrears of ex-gratia payment, etc.(Sl.No. 2 (iii) of Form-I):</u> The port has shown nil figures towards the above items. The port to confirm there is no one time expenses like arrears of wages, arrears of pension/ gratuity, arrears of ex-gratia payment reported in the Annual Accounts for the years 2011-12 to 2013-14.	There was wage revision due in 2012-13 and 2013-14. Hence, liability towards the same was created and included in the Salaries & Wages portion of the respective year. Hence, no one time payment was made at the time of settlement of WRC in 2013-14 and hence the Port has not shown any figures towards 4/5 th of one time expenses, if any like arrears of wages, arrears of pension/ gratuity, arrears of ex-gratia payment, etc. (Sl.No. 2 (iii) of Form-I) of the Proposal submitted to TAMP.																									
(iii).	<u>4/5th of the One time Contribution to the Pension Fund (Sl.No. 2 (iv) of Form-I):</u> As per clause 2.2 (iii) of Working Guidelines,2015, the port has excluded ₹1300.97 Lakhs, `640 Lakhs & ₹1720 Lakhs in the years 2011-12, 2012-13 & 2013-14 respectively as 4/5 th of contribution to the pension fund. These figures could not be correlated with the figures reported in the Annual Accounts as the Annual Accounts report contribution to pension fund and gratuity fund together. Note 2 and 3 under Form-3 require the port to furnish a working reconciling the amount reported in the Audited Annual Accounts and the figures considered in the cost statement. The VOCPT to furnish the same.	The statement of reconciliation is furnished below:- (₹ In Lakhs) <table><tr><th>S.No.</th><th>Description</th><th>2011-12</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th></tr><tr><td>1</td><td>Contribution to Pension Fund & Gratuity Fund as per Annual Accounts</td><td>2000.00</td><td>2000.00</td><td>2500.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Less: Gratuity Fund</td><td>374.00</td><td>1200.00</td><td>350.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Balance</td><td>1626.00</td><td>800.00</td><td>2150.00</td></tr><tr><td>4</td><td>4/5th considered on Sl.No.3</td><td>1300.97</td><td>640.00</td><td>1720.00</td></tr></table>	S.No.	Description	2011-12	2012-13	2013-14	1	Contribution to Pension Fund & Gratuity Fund as per Annual Accounts	2000.00	2000.00	2500.00	2	Less: Gratuity Fund	374.00	1200.00	350.00	3	Balance	1626.00	800.00	2150.00	4	4/5 th considered on Sl.No.3	1300.97	640.00	1720.00
S.No.	Description	2011-12	2012-13	2013-14																							
1	Contribution to Pension Fund & Gratuity Fund as per Annual Accounts	2000.00	2000.00	2500.00																							
2	Less: Gratuity Fund	374.00	1200.00	350.00																							
3	Balance	1626.00	800.00	2150.00																							
4	4/5 th considered on Sl.No.3	1300.97	640.00	1720.00																							
(iv).	<u>Expenses relevant for tariff fixation of Captive Berth, if any governed under clause 2.10 of the Tariff Policy, 2015(Sl.No. 2 (vi) of Form-I):</u> The VOCPT has excluded depreciation of ₹58.54 lakhs, ₹58.83 lakhs and ₹76.05 lakhs in the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively towards captive berth. However, the port has not shown any exclusion of	Since the Port does not incur any direct Operating Expenditure and Finance & Miscellaneous expenditure items relating to captive berths operated by BOT Operators except depreciation relating to respective berths, the port has not shown any exclusion of operating expenses, allocated Management & Administrative Overhead (MAO) and allocated Finance & Management Expenses (FME)																									

	operating expenses, allocated Management & Administrative Overhead (MAO) and allocated Finance & Management Expenses (FME) towards captive berth. The reasons therefor, may be explained. The port may also indicate the captive berth for which this exclusion is done by the VOCPT.	towards captive berths. The captive berths considered are VII Berth Container Terminal operated by M/s. PSA SICAL, VIII Berth Container Terminal operated by M/s. DBGT and North Cargo Berth-I by M/s. NTPL.
(v).	Capital Employed (Sl.No. 5 (iii) & (iv) of Form-I):	
	(a). As per Clause 2.4 of Working Guidelines 2015 for computation of capital employed, the port has to exclude net value of fixed asset related to estate activity and net fixed assets transferred to BOT operators as on 31 March 2014 as per Audited Annual Accounts. The VOCPT has excluded ₹650.69 lakhs towards net value of fixed asset related to estate activity and ₹6744.79 lakhs (i.e. VII berth ₹2637.70 lakhs + VIII berth ₹2375.04 lakhs + NCB-1 1732.05) towards net value of fixed asset transferred to BOT operators as on 31 March 2014 as per Audited Annual Accounts. As regards ₹1732.05 lakhs excluded by VOCPT towards NCB-1, it is relevant to state that during the fixation of upfront tariff for this berth, it was made to understand by the port that the NCB-1 was constructed by the VOCPT on deposit terms as per the sanction of the MOS vide letter no PD-11015/5/2006-TPT dated 22 October 2009. Further, the capital cost considered for tariff fixation for the project was based on the actual capex incurred by NLC Tamil Nadu Power Ltd (NTPL). In view of the above position, please review exclusion of ₹1732.05 lakhs towards NCB-1.	The exclusion of ₹1,732.05 lakhs towards the net value of fixed assets relating to NCB-I pertains to expenditure for common usage regarding road and electricity around the berth area developed by the Port for the operation of NCB-I and not relating to Berth. Hence the exclusion of the same is in order and eligible to be considered for Annual Revenue Requirement.
	(b). The port has excluded depreciation related to captive berths from the total operating expenses. However, the VOCPT has not shown any deduction towards corresponding net fixed assets related to captive berth at Sl.No.5 (v). The VOCPT to examine and make suitable correction in Form-I.	Depreciation excluded in S.No.2(vi)(b) is towards BOT berths, since no separate row was available for the same stated under captive. In Net Block separate row under Sl.No.5(iv) was available so deduction is shown against the same. Hence correction in Form-I not required.
(vi).	(a). It is seen that from the ceiling indexed Annual Revenue Requirement (ARR) estimated at ₹33,477.51 lakhs, the VOCPT has shown adjustment (reduction) of ₹5,637.03 lakhs being the Escrow Account balance as on 31.3.2014 and has arrived at the adjusted ceiling ARR of ₹27,840.48 lakhs which matches with the revenue estimated at the draft proposed SOR. Clause 4.2 of the Tariff Policy, 2015 and Clause 2.11 of Working Guidelines state that balance in the Escrow accounts maintained by the Major Port Trust can be utilized for the purpose as decided by the Board of Trustees of the concerned Major port trusts. Thus, the Tariff Policy, 2015 and Working Guidelines do not require the Major Port Trusts to adjust the Escrow Accounts balance against the ARR. The ARR is the ceiling level and ports have the flexibility to draw the proposed SOR within the ceiling indexed ARR. The VOCPT to explain the reason for adjustment of Escrow Account balance from the ARR. It may be relevant to state here that none of the other Major Port Trusts who have filed the proposal under Tariff Policy, 2015 have done such an adjustment.	Since a provision is in Clause 2.11 of Working Guidelines that the balance in the Escrow accounts maintained by the Major Port Trust can be utilized for the purpose as decided by the Board of Trustees of the concerned Major port trusts, the Port shown deduction of ₹56.38 crores from the indexed ARR as provided in the Tariff Regulations, 2015.
	(b). The nature and purpose for which the Escrow Account is maintained to be explained.	The Escrow Fund is maintained to meet the expenditure for the development of Port infrastructure and established and maintained as Part of Tariff Guidelines, 2005.
3.	Working relating Management & General	

	Overheads (FORM-2) :	
	The operating expenditure (including depreciation but excluding operating expenditure related to estate) arrived by the port at Sl.No.2 does not exclude the allocated Management and General Overheads of Estate Activity as reflected in Sl.No.2(i) (b) of Form-1. The VOCPT to examine and make necessary correction in Form -2 and submit revised Form-2.	Since as per the Form-2, Operating Expenditure (including depreciation but excluding operating expenditure relating to Estate) (As per Audited Annual Accounts) has to be arrived vide Sl.No.2, only the operating expenditure as per audited annual accounts has been deducted and allocated Management & General Overheads has not been excluded, since it was not stated to exclude.
4.	<u>Computation of Working Capital as per norms (FORM -4):</u> There is an addition of ₹2963.24 lakhs in excel working considered by the VOCPT for estimating cash expenses at one month. The port to furnish detailed working of cash expenses considered by it.	The amount of ₹2,963.24 lakhs consist of Pension Payments for 2013-14. As the same is an outflow, proportionate Pension payments p.m. is included in working capital under general revenue.
5.	<u>Revenue estimation (Form -3):</u>	
(i).	It is seen that the port, while estimating revenue at proposed SOR, has considered the revenue earned during the year 2014-15 and increased it by the proposed tariff hike of 27.7% to arrive at estimated revenue at the proposed Scale of Rates. As per the format prescribed for estimating the revenue, the VOCPT is required to estimate revenue for each tariff items viz. cargo, vessels and miscellaneous services at the proposed rate for the actual traffic handled by the port in the year 2014-15.	To obtain the Annual Revenue Requirement of the Port as per Form-1, the traffic throughput of 210.68 lakh tonnes is the tonnage handled net of tonnage from PPP Operations. The relating cargo handling, port Dock related services and miscellaneous services are distinctively worked out and furnished in Form III submission to the authority. Actual earnings of 2014-15 is used as a base and proposed rate of increase on the existing SoR is computed.
(ii).	Further, the revenue of 2014-15 considered by VOCPT in Form 3 do not match with the revenue reported in the Audited Annual Accounts. e.g. For port dues, earning considered by VOCPT for the year 2014-15 is ₹2,553.95 lakhs which do not match with port dues of ₹2835.88 lakhs reported in the Audited Annual Accounts for the year 2014-15.	The dredging levy component of ₹281.94 lakhs is included in the revenue of Port Dues for the year 2014-15, as shown in Annual Accounts 2014-15 (Scheduled 7). The same is not relevant now since dispensed with from 1.10.2014. Hence in the current proposal, the said amount was excluded in the earnings and balance figure ₹2,553.95 lakhs is considered.
(iii).	The VOCPT, therefore, to furnish modified revenue estimate (Form- 3), as brought out in (a) above with detailed working in support of the revenue estimates. While estimating the revenue at the proposed tariff for the actual traffic of 2014-15, VOCPT is also requested to furnish the following:	Please refer the reply to point (ii) above. Considering the submissions, the Port's computation may be considered.
	(a). Confirm that the total GRT vessel considered in the revenue estimates for vessel related charges matches with the actual total GRT of the vessel handled by the port for the year 2014-15. In case of mismatch, if any, the VOCPT to reconcile the difference. (b). Confirm that volume of cargo considered in the revenue estimates matches with the actual cargo handled and reported in the Administrative Report. In case of variation, the difference is to be reconciled. (c). The exchange rate considered for revenue estimates may please be indicated. (d). While estimating revenue from coastal vessel, the VOCPT to ensure that it is in line with recent Order No. TAMP/4/2004-Genl. of the Authority dated 19 May 2016 passed by the Authority.	It is confirmed that the total GRT vessel considered in the revenue estimates for vessel related charges matches with the actual total GRT of the vessel handled by the port for the year 2014-15 since the actual earnings of the 2014-15 excluding the dredging levy and pension fund levy is considered as a base to arrive at the rate of increase to compute the ARR. It is confirmed that volume of cargo considered in the revenue estimates matches with the actual cargo handled and reported in the Administrative Report as the tonnage considered in Form-3 is net of tonnage handled through PPP Operator viz., VII Berth and VIII Berth Container Terminal and NTPL operations at NCB I. The actual earnings made in 2014-15 is considered in the figures. Yes. The revenue for coastal vessel is estimated in line with recent Order No. TAMP/4/2004-Genl. of the Authority dated 19 May 2016 passed by this

		Authority. As income is based on actual for the year 2014-15, the coastal earnings are captured with respect to TAMP order No 4/2004- General dated 19.5.2016.
6.	<u>Scale of Rates:</u>	
(i).	Clause 2.12. of the revised Working Guidelines stipulates that if a new condition is introduced or if existing condition is modified due to operational contingency, the port may prescribe such modification with reasons thereof and capture the financial / revenue impact in the ARR. The basis adopted for the tariff proposed for new items is to be furnished and its financial effect to be captured in the revenue estimations in Form - 3. The VOCPT has proposed the following new tariff items / conditions and deletion of the following tariff items / conditionalities from the existing SOR in the proposed SOR:	Factual
	<p>(a). <u>Chapter –II , Schedule 2.1 Port Dues:</u></p> <p>The VOCPT has proposed deletion of existing port dues separately prescribed for Sailing Vessels at Sl. No.2. In this regards, following may be furnished:</p> <p>(i). Furnish the reason for deletion of separate port dues in respect of Sailing Vessels. It is seen that in other schedules, the separate tariff for sailing vessel is proposed to be continued by the port.</p> <p>(ii). The basis for levy of port dues for this category of vessels may be explained and the percentage increase from the existing tariff also to be indicated. Please confirm the increase for this category of vessel will be 27.70% as per the proposal of the port for other items.</p> <p>(iii). Please show that the impact of the proposed modification has been considered by the port in the revenue estimation.</p>	<p>The deletion of existing port dues separately prescribed for Sailing Vessels at Sl. No.2 of Chapter – II, Schedule 2.1 Port Dues is due to typographical error. The proposed tariff for the same is to be retained and the same is included in the revised draft SoR furnished.</p> <p>The Authority may consider the increase for this category of vessel by 27.70% as per the proposal of the port for other items.</p> <p>The revenue estimation already submitted by the Port includes the impact also in Form-3 vide Sl.No.1 Port Dues and only it was left out in draft Scale of Rates.</p>
	<p>(b). <u>Schedule 2.2.1 – Schedule of Pilotage Fees Note (1).</u></p> <p>In the existing note (1) defining pilotage fee the words, “subject to a maximum of Two tugs” is added and a sentence is added to state that Tugs required more than the prescribed maximum number of two shall be levied at the rates prescribed at sl.no.1 of Schedule 2.3 (Tug Hire Fees). Clause 10.4 of the Working Guidelines, 2015 defines pilotage as Pilotage-cum-towage fee to be composite rate and shall include one inward and one outward movement with required number of tugs/launches of adequate capacity and shifting/s of vessels for ‘Port convenience.’ The VOCPT to clarify as to how the modified definition proposed by the VOCPT fits in line with the definition prescribed in the Working Guidelines which is uniformly prescribed in the SOR of all Major Port Trusts.</p>	The proposed levy of additional Tug over and above Two Tugs is deleted.
	<p>(c). <u>Schedule 2.2.3 – Shifting Charges, Clause (I) & (II)</u></p> <p>The port has proposed a new note under schedule 2.2.3 stating that the shifting fee prescribed in schedule 2.2.3 (I) is subject to a minimum charge of ₹4385.54 per ship</p>	The minimum charges prescribed for specified slabs in scheduled 2.2.1. 25% or 50% of pilotage fees minimum charges at 25%/50% of pilotage fees is

	in case of coastal vessel and US\$ 168.18 for foreign going vessel. Likewise, the port has proposed minimum shifting charges under schedule 2.2.3 (II). The basis of prescription of the minimum charges may be explained.	adopted proportionately as minimum charges is proposed in scheduled 2.2.3.(I) and (II).
	<p>(d). <u>General Notes relating to Schedule 2.2.1, 2.2.2 and 2.2.3.</u></p> <p>Under General Notes relating to Schedule 2.2.1, 2.2.2 and 2.2.3. under Clause 9 (b) (ii), the port has added the berth no. VII, VIII, north-cargo berth No. I & II. The reasons for addition of the berth no. VII, VIII, north-cargo berth No. I & II in the existing clause may be explained. Confirm that revenue impact of the proposed modification, if any, which may generate additional revenue to the port is captured in the revenue estimates.</p>	As the possibility of shifting of vessels to outer anchorage/any other berth is there on account of its non performance provision is made in respect of vessels berthed / to be berthed at from other berths VII, VIII and NCB-I & NCB-II this clause is modified accordingly. The instances are very rare and is negligible in financial terms.
	<p>(e). <u>Schedule 2.3 – Tug Hire Fees, Sl. No.1</u></p> <p>The addition of words “and also hire of each additional tug over and above the maximum of two tugs for pilotage operation” specified in Note 1 under schedule 2.3 to be re-examined in the light of our query at 6 (ii) (b) above. Similarly, the modification proposed in Note 1 under schedule 2.3 may also be relooked and modified in the light of our query at 6 (ii) (b) above.</p>	The addition of words “and also hire of each additional tug over and above the maximum of two tugs for pilotage operation” may be deleted with respect to reply vide sl.no.6 (b).
	<p>(f). <u>Schedule No. 2.4.2 Berth Hire Charges for other Vessels –</u></p> <p>The Rupee denomination indicated in Schedule 2.4.2 under foreign going vessels at Sl.No.1 to 3 appears to be typographical error. This may be corrected. Further, the coastal tariff for other crafts applying proposed increase of 27.7% comes to ₹2.12 per GRT/hour instead of proposed rate of ₹2.18 /GRT/hour. The port to relook at the proposed tariff rates for all items to ensure there is no typographical error.</p>	The typographical error is corrected indicating the tariff of Sl.No.1 to 3 in Rupee Denomination in the draft SoR enclosed vide Sl.No.1. The typographical error in other areas are verified and corrections incorporated.
	<p>(g). <u>Notes under Schedule No.2.4.2 Berth Hire Charges for other Vessels:</u></p> <p>(i). The port has proposed a note after note 4 stating that port reserve the right to revise the norms as per the field condition and that decision of Traffic Manager in this regard shall be final and binding. Since the performance standards (to be) notified by the Authority will have linkage to indexation in tariff, the proposed note to revise the norms during the currency of the tariff cycle may run in conflict with indexation of tariff which has linkage to pre-determined performance standards. Therefore, the proposed note to be reviewed.</p> <p>(ii). The port has also proposed notes relating to penalty for non achievement of the prescribed output norms and rebate in berth hire charges for achieving higher than the norms prescribed in respect of Coal vessels handled at Berth No. IX & VOC II & IV and for remaining cargos except coal handed at Berth No. III & IV and Berth No. IX. In this regard the following points may be clarified:</p> <p>(a). The note (A) prescribing that till the commencement of mechanised handling through conveyor for evacuation of coal at berth No. IX and deployment of 2 HMCs at Berth nos. III and IV is</p>	<p>As per the New Berthing Policy for Dry Bulk for Major Ports issued by the Ministry of Shipping vide Clause 7.2. Performance norms in a phased manner to reach the target levels achievable for each commodity given infrastructure available at berths. To this end, performance norms for different commodities alongwith anchorage charges will have to be computed every quarter by all Ports. Further, Point No. 8 of Berthing Policy for dry bulk cargo for Major Ports is furnished. The words “decision of the Traffic Manager --- final and binding is deleted”.</p> <p>The 3 x and 5 x times penalty on berth hire for every extra hour during the stay at berth is calculated based on the recommendations of M/s BCG in their report dated 04.11.2015 (non-negotiable as instructed by Ministry of Shipping). The recommendations of the consultant is furnished. However, the extent of penalty remains at 3 times on the extra berth hours as per the new Berthing Policy, 2016 which will remain in force until modified.</p>

<p>incomplete. A complete note with the reasons for the proposed note may be furnished.</p> <p>(b). Also, explain the reasons and basis for proposing the benchmark productivity of 24000 MT / day and 21000 MT/day for coal handling at Berth No. IV, 12000 MT/day /10,500 MT/day for coal handling at berth No. III and IV for proposing penalty for the above level of productivity as they do not match with the cargo output norms proposed by VOCPT.</p> <p>(c). Likewise, the reasons and basis for proposing productivity level of 25,500 T/day 27000 T/day for coal at Berth No. IX and productivity level of 13,500 T/day / 15,000 T/day for coal handled at berth No. III/IV for proposing rebate if productivity above the prescribed level is achieved may be explained as they do not match with cargo output norms proposed by VOCPT.</p> <p>(d). Also, explain the reasons and basis for proposing penalty at 3 times and 5 times, the berth hire (excluding wharf crane element) and rebate of 10% / 20% in berth hire charges.</p> <p>(e). The reasons, basis and logic of proposing Future Output in the notes may also be explained.</p> <p>(f). The port has proposed separate conditions for levy of penalty / rebate after commencement of mechanised operations of coal handling.</p> <p>(i). The basis of each of the parameters considered in the proposed note may be explained in detail.</p> <p>(ii). The proposed conditions governing levy of penalty and grant of rebate have not been prescribed in the reference tariff approved for the berth no.(IX) and VOC III & IV. Therefore, the VOCPT may carefully examine whether prescription of the proposed conditions would give rise to disputes with the successful bidders of berth no.(IX) and VOC III & IV.</p> <p>(g). The port to furnish the working of additional income likely to accrue in view of the each of the proposed conditions and also show where it is captured in the revenue estimates.</p>	<p>The benchmark productivity on Coal handling at berth No.IX and berth III & IV is prepared based on the recommendations of M/s.BCG in their report dated 04.11.2015 (non-negotiable as instructed by Ministry of Shipping). The recommendations of the consultant are enclosed for reference. But at present, the new productivity norms proposed by the port as per the recommendations of Ministry of Shipping on revised productivity norms for Dry bulk cargoes in the Berthing Policy, 2016 supersedes the productivity norms proposed by M/s BCG. The recommendations of the consultant are enclosed is furnished.</p> <p>The benchmark productivity on Coal handling at berth No.IX and berth III & IV is prepared based on the recommendations of M/s. BCG in their report dated 04.11.2015 (non-negotiable as instructed by Ministry of Shipping). The recommendations of the consultant are enclosed for reference. But at present, the new productivity norms proposed by the port as per the recommendations of Ministry of Shipping on revised productivity norms for Dry bulk cargoes in the Berthing Policy, 2016 supersedes the productivity norms proposed by M/s. BCG. The recommendations of the consultant are enclosed for reference.</p> <p>The penalty and rebate scheme was formulated and recommended by M/s. BCG in their report dated 04.11.2015 (non-negotiable as instructed by Ministry of Shipping). The recommendations of the consultant are enclosed for reference.</p> <p>The future output denotes that after implementation of mechanization proposed at IX Berth the benchmark output enhanced from 24,000 M.T to 28,000 M.T. and so on.</p> <p>This basis stands withdrawn now based on the Berthing Policy, 2016. The penalties and incentive are based on the Penalty and incentive given in the Berthing Policy by the Ministry.</p> <p>There are no PPP operations in Berth No. IX, VOC III & IV, as these berths are operated by VOC Port. Only in IX berth on license basis HMC is deployed at present. The penalty and grant of rebate are to be on vessel operators.</p>
--	---

		As clause relates to penalty for lesser productivity and incentive for higher productivity the financial implication is beyond estimation and the same will be negligible considering Government norms to improve productivity.
	<p>(h). <u>Schedule No. 2.4.2 – Note Sl. No. 11</u></p> <p>(i). The port has proposed two new notes under schedule 2.4.2 at Sl. No. 11 (i) & (ii). The reasons for insertion of proposed notes may be explained.</p> <p>(ii). The basis for proposing ₹5,000/- per amendment may also be explained.</p> <p>(iii). The existing note (9) as well as proposed note no.(11) proposes one day berth hire charges for cancellation of services including amendment to berthing schedule. The proposal of port states that `5000 per amendment is proposed as a flat rate instead of existing provisions. However, by retaining the existing note (9) and proposing new note 11(ii), there will be duplication in levy for the same service. The port to examine and propose necessary modification. Confirm the revenue impact of the same is considered in the revenue estimates in Form 3.</p>	The Users requested to withdraw one day penal berth hire charges levied for cancellation of vessel booking after numbering of vessels and amendment request in the berthing programme considering that the same is exorbitant. Hence, to consider the request and also for amendment of berthing programme, it is proposed to relax the conditionality incorporating the two new Notes. The revenue impact on this issue could not be predicted as it is not a recurring one.
	<p>(i). <u>Chapter 3, Schedule 3.1, Sl. No. 3(b), (c):</u></p> <p>(i). The port has inserted two items under schedule 3.1 at Sl. No. viz. 3(b) Coal by whatever name described in Customs documents and used for thermal power plants and 3 (c) Coal by whatever name described in Customs Document other than sl.no.3 (b). The VOCPT to elaborately explain the reasons and basis for inclusion of the each of the above new tariff items / in the proposed SOR. Also, confirm whether the impact of each of the above tariff items is captured in revenue estimates in Form – 3.</p> <p>(ii). The existing SOR prescribes separate wharfage rate for steaming (non-cooking coal) under Chapter-II, Schedule 3.1. at Sl. No. 3(b). The reason for deletion of this item may be explained. The wharfage rate leviable as per the modified SOR for this cargo may also be clarified.</p>	<p>At present there is no clarity in the classifications of coal as to which are meant for power plants and which are meant for other than power plants, as Customs document classify as Steaming (non-coking) coal only.</p> <p>There is no separate description in the Customs documentation as Thermal coal/other coal. Hence the issue of short collection has been observed by Vigilance and Resident Audit observation, due to difference in interpretation. Considering the above, the Coal is brought under single classification. The impact of revenue increase due to the above is suitably captured in the revenue estimates in Form-3.</p> <p>Please refer the reply to point No.(i) above.</p>
	<p>(j). <u>Chapter 3, Schedule 3.1, Sl. No. 23:</u></p> <p>The existing SOR prescribes separate wharfage rate for “Goods not otherwise specified” in Schedule 3.1. at Sl. No. 23. The port has proposed deletion of this tariff item. The reason for deletion of this item may be explained. The port may also clarify what will be the wharfage rate for residual cargo category, if a particular cargo does not fit in the cargo items prescribed in the Schedule.</p>	The rate for “Goods not otherwise specified” in Schedule 3.1. has not been deleted. The tariff is available under Sl.No.16 of Chapter 3, Schedule 3.1
	<p>(k) <u>Chapter 3, Schedule 3.1, Wharfage Charges Sl. No. 24 to 25:</u></p> <p>Automobiles through RORO vessels (Roll on Roll off) PCTC (Pure car & Truck Carrier)</p> <p>The port has proposed new wharfage items vide its letter no. FIN-OFFCT-SOR-REVIS-VI-15/D1450 dated</p>	The tariff is proposed based on the Chennai Port Trust’s proposal to fix the rate for handling automobile through RO RO vessels at ₹500/- for handling car below 1600 CC and ₹1000/- for handling car above 1600 CC. It is in advertantly mentioned that

	<p>13 June 2016 in respect of handling of automobile through RORO vessels at ₹500/- for handling car below 1600 CC and ₹1000/- for handling car above 1600 CC. The VOCPT has stated that it is based on the tariff available for the same facility in Cochin Port (COPT). In this context it is to state that rate approved for COPT recently for RORO is as follows:</p> <table border="1"> <tr> <td>Motor Vehicles except Motorcycles</td><td>Coastal</td><td>Foreign</td></tr> <tr> <td>By RO-RO System</td><td>1080.00</td><td>1800.00</td></tr> <tr> <td>Other than by RO-RO System</td><td>2160.00</td><td>3600.00</td></tr> </table> <p>The rates proposed by the VOCPT do not match with the rates prescribed in the SOR of COPT. The VOCPT may, therefore, indicate the correct position of whose rate the port has adopted. The port may in this context refer clause 5.7.1 of the Working Guidelines which deals with tariff fixation for new cargo / service / facility and propose tariff in compliance with the said clause.</p>	Motor Vehicles except Motorcycles	Coastal	Foreign	By RO-RO System	1080.00	1800.00	Other than by RO-RO System	2160.00	3600.00	<p>the rate proposed is based on the rate available in Cochin Port Trusts. The Authority is requested to consider for the approval of the rate proposed.</p>
Motor Vehicles except Motorcycles	Coastal	Foreign									
By RO-RO System	1080.00	1800.00									
Other than by RO-RO System	2160.00	3600.00									
	<p>(m). <u>Chapter 5, Schedule 5.03 Sl. No. 1 to 4</u></p> <p>The existing SOR prescribes separate charges for hire of Mobile Cranes / Fork Lift Truck /Marshall Demag Crane at Sl. No. 1 to 4. The port has proposed deletion of these tariff items. The reason for deletion of these items may be explained.</p>	<p>As the said Mobile Cranes / Fork Lift Truck /Marshall Demag Crane at Sl. No. 1 to 4 are already survey reported a long back and not available with the Port the tariff for the said items are to be deleted.</p>									
	<p>(n) <u>Chapter 5, Schedule 5.03 Note:</u></p> <p>The existing SOR prescribes a note stating that the rate in Column 5 shall be applicable for coastal cargo and containers eligible for concessional tariff, for ship shore transfer, transfer from / to quay and to / from storage yard .The port has proposed deletion of this note. The reason for deletion of this note may be explained. This note may be continued as it flows from coastal concession policy of the Ministry of Shipping.</p>	<p>The Note has not been included inadvertently in the proposed draft SoR submitted to the Authority. The same has been incorporated in the draft SoR enclosed vide Sl.No.1.</p>									
(ii).	<p>It is seen from the Form 3 furnished by the port that the VOCPT has not estimated revenue at the proposed Scale of Rates for the following few items:</p> <ol style="list-style-type: none"> Schedule 2.2.2 - Miscellaneous Pilotage Fee Schedule 2.3 – Tug Hire Fees Schedule 4.1, 4.2 &4.3 – Container related Charges Schedule 5.01 – Weightment Charges for Zone A & B Schedule 5.5 – Charges for use of Ports Pipeline to Transport Ship Stores / Bunker Oil to Ship. Schedule 5.6 – Charges for use in connection with Shipping Operation. Schedule 5.9 – Charges for higher of Dry Dock to owners of sailing vessel and to other Govt. Department for Dry Docking their Vessel. Schedule 5.10 – Hire charges for hire of tools and plants to Govt. Dept. Schedule 5.11 – Cooper License Fee Schedule 5.12 – Charges for issue of photo permits Schedule 5.13 – Charges for issue of temporary passes. 	<p>As the earnings from Sl.No.(a) to (q) in the query raised is meager amount and hence the same is clubbed under basic vessel related income and the revenue estimation has been calculated . Hence, the Authority is requested to consider the same for admission.</p>									

	<p>(l). Schedule 5.14 – Charges for taking photographs / shooting films</p> <p>(m). Schedule 5.15.1 & 5.15.2 – Fees for salvage of goods / services of driver.</p> <p>(n). Schedule 5.17 – Passenger Toll</p> <p>(o). Schedule 5.18 – Issue of Duplicate Bill Copy etc.</p> <p>(p). Schedule 5.19 – Charges for wooden logs to sailing vessels.</p> <p>(q). Schedule 6.1(4) – CHD – for Container Stuffing / De-stuffing Operation.</p> <p>(r). Wharfage of ₹500 for handling below 1600 cc and ₹1000 for handling car above 1600cc.</p> <p>(s). For vehicle with laden containers with trailers the tariff will be collected at composite rate covering both vehicle and container separately collecting the rate of container as per prevailing SOR.</p> <p>The VOCPT is requested to estimate the revenue at proposed rates for the above items also. Alternatively, the VOCPT may leave reasonable amount of ARR uncovered to take care of tariff of the above of few items for which revenue is not estimated.</p>	<p>Since this is new cargo item expected in future the impact of financial implication could not be quantified.</p>
(iii).	<p><u>Schedule 5.20 Charges for use of Harbour Mobile Cranes (HMC) installed by the private operator.</u></p> <p>The VOCPT has proposed 27.7% increase in the proposed schedule. In this context it is relevant to state that the existing tariff for HMC approved by the Authority is as per Order No.TAMP/22/2007-TPT dated 30 December 2009 on normative basis which was continued to be prescribed in the last general revision of SOR.</p> <p>In the Tariff Policy 2015, clause 9.1. to 9.3. prescribes the provision for tariff regulation of charges levied by service provider authorized by the port. The proposal filed by the VOCPT applying 27.7% tariff revision for general SOR to HMC operated by authorized service provider is not found to be in line with the said guidelines provision. That being so, VOCPT may file a separate proposal for revision in the rate for HMC provided by the authorized service provider on normative basis.</p>	<p>Agreed to. Based on review and if required proposal will be dealt in separately.</p>
(iv).	<p><u>Pollution cess on Dusty Cargoes discharged at the rate of ₹5/- per MT.</u></p> <p>The VOCPT has proposed a new tariff for pollution cess on Dusty Cargoes. The VOCPT has not furnished any basis for the tariff items proposed pollution cess. As per clause 5.7.1 of the Working Guidelines, 2015, whenever a specific tariff for a service/ cargo is not available in the SOR, of that particular port, the concerned Major Port Trust can propose rate for new cargo/ equipment/ service adopting the tariff and performance standards, if any, fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any other Major Port Trust. If there is no rate available in any other Major Port Trust or if the rate available is not representative enough of the proposed new cargo/ service/ facility, then the port may file the proposal for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service with reference to optimal capacity assessed following the principles of 2008 guidelines or based on</p>	<p>The pollution cess on dusty cargoes is not a separate service. In order to recover the amount spent towards cleaning of wharf area and efforts to comply with Environment Management System (EMS) requirements, such pollution cess is proposed at the rate of ₹5/- per M. Ton dusty cargoes. Also, the amount to be collected is adjusted in the revenue requirement. Hence the Authority is requested to approve the tariff for pollution cess on dusty cargoes.</p>

	<p>rated capacity or technical specification of service/facility/ equipment. If determination of tariff based on the above prescribed options is not possible, then the Major Port Trusts after giving sufficient reasons may propose rates based on cost plus 16% return formula. In this context, the VOCPT is requested to clarify under which option the rate for pollution cess on dusty cargo is proposed amongst the options prescribed in the Working Guidelines? In case the port has adopted the rate from the rate prescribed at other Major Port Trust for similar items, then please indicate the reference of such adopted rate. If the port has proposed rate based on cost + 16%, furnish the detailed working for the proposed rate.</p>	
7.	<u>Annual Revenue Requirement (ARR) (FORM No.1)</u>	
	<u>Cargo Handling Division (CHD):</u>	
(i).	<p><u>Adjustment of Pension Fund Shortfall:</u></p> <p>(a). The VOCPT has added 1/5th of the opening shortfall in Pension Fund to the tune of ₹6,281.76 Lakhs, ₹10,720.69 Lakhs & ₹21,136.00 Lakhs for the years 2011-12, 2012-13 & 2013-14 respectively while estimating the ARR of CHD. The approach adopted by the VOCPT does not fall in line with the provisions prescribed in the Tariff Policy 2015 and Working Guidelines and hence justify the reasons for deviation from the Tariff Policy 2015 and Working Guidelines in this regard.</p> <p>(b). Furnish the basis and detailed working of the above figures considered in the ARR computation.</p>	<p>In respect of CHD, there is no surplus funds available to meet the huge shortfall in Pension and Gratuity Fund with respect to actuarial valuation. As a result, the clause 2.11 of the working guidelines providing for dispensing with Pension Fund Levy will result in heavy financial burden to CHD to meet the heavy shortfall in Pension and Gratuity Fund. As there is no Escrow fund available in CHD, utilizing the same to meet the shortfall is not possible in CHD (which is to be self sufficient as per Memorandum of Settlement dated 27.7.2011) it is proposed to cover 1/5th of the opening shortfall of each year under reference as expenditure.</p> <p>The pension Fund shortfall as on 01.4.2011 at ₹6281.76 lakhs and as on 1.4.2012 at ₹10,720.69 is available in the TAMP orders dated 11.10.2011 vide point No.10.1.(viii) and order dated 04.8.2014 vide point NO.5.1 (xiv) (e) respectively. The balance as on 01.4.2013 is furnished.</p>
(ii).	<p><u>4/5th of the One time expenses, if any, like arrears of wages, arrears of pension / gratuity / arrears of ex-gratia payment etc.(Sl.No. 2(iii) of Form-I):</u></p> <p>The VOCPT has considered nil amount towards onetime expenses like arrears of wages, arrears of pension / gratuity / arrears of ex-gratia payment etc. The Annual Audited Accounts for the year 2013-14, however, reports that ₹10,90,62,275 and ₹11,65,857 towards WRC arrears and ACP arrears respectively for the year 2013-14. The VOCPT is requested to clarify the reasons for not considering 4/5th of such one time expenses in the ARR. While capturing, this computation the VOCPT to take into consideration note 2 (ii) under Form -I prescribed along with the Working Guidelines.</p>	<p>The payment of wage revision arrears and pension arrears pertain to impact of revision for 2013-14 only shown distinctively in the Accounts as ₹10,90,62,275 towards WRC arrears and ₹11,65,857 towards ACP arrears pertain to the period of 2013-14 only. Therefore, the question of 4/5th of one time expenses deferred for future does not arise as previous expenditure is not included in the above figures.</p>
(iii).	<p><u>Contribution to the Pension Fund (Sl.No. 2(iv) of Form-I):</u></p> <p>The Annual Audited Accounts reports contribution to Pension Fund of ₹354 lakhs, ₹294.98 lakhs & ₹ Nil for the year 2011-12, 2012-13 & 2013-14 respectively. 4/5th of this comes to ₹283.2 lakhs, ₹235.98 lakhs & Nil. As against this, the VOCPT has considered ₹5,025.41</p>	<p>Under Form-1 vide Sl.No.1 (vi) instead of considering Pension Contribution, the Pension Fund shortfall at the beginning of the relevant year is considered and hence on the same lines under Sl.No.2 (iv) also the 4/5th of Pension Fund shortfall at the beginning is considered</p>

	lakhs, ₹8,576.55 lakhs and ₹16,908.80 lakhs for the years 2011-12, 2012-13 & 2013-14 respectively. This does not match with the 4/5 th of the contribution to pension fund reported in the Audited Annual Accounts for each of the years. The VOCPT to compute and consider the figures based on the figures reported in the Audited Annual Accounts of 2013-14.	for adjustment.
(iv).	<u>Revenue Estimation -CHD (Form -3):</u> Indicate the actual cargo traffic handled by CHD. Confirm that the traffic of 2014-15 considered in Form 3 is the actual traffic handled by CHD. In case of any variation, please reconcile giving reasons for variation.	It is confirmed that the actual cargo traffic handled by CHD in 2014-15 is 158.80 lakh tonnes and the same is considered in Form-3 also.
(v).	<u>Scale of Rates - Section 6.1- Levy of Charges for obtaining services of cargo handling workers from Cargo Handling Division</u> The port has proposed to increase the CHD levy by 51.20%. Justify the proposed increase of 51.20% in existing levy for supply of labour from CHD for cargo handling operations as against 27.75% increase proposed for port operations. The VOCPT is requested to explore the possibility of moderating the increase proposed in CHD tariff items which are higher than the general increase proposed in the port operations at 27.70%.	The proposed increase of 51.20% in respect of CHD is arrived to obtain the annual revenue requirement of ₹104.54 crores as per required annual requirement as per Form-1(CHD) considered the traffic throughput of 158.80 lakh tonnes in 2014-15 whereas the proposed increase of 27.70% is with respect to the revenue requirement of Port viz., ₹278.41 crores as per Form-1 (Port) considering the traffic throughput of 210.68 lakhs tonnes net of PPP tonnage (113.46 lakh tonnes) from 324.14 lakhs tonnes. Hence the percentage of increase is arrived based on different figures in respect of Port and CHD. CHD is to function as a separate self sufficient unit as per merger settlement condition.
8.	The Authority has passed the following common adoption order for all Major Port Trusts. Apart from that, the Major Port Trusts were also requested to include suitable note in the SOR vide our letters brought out at Sl. No. (c) and (d) : (a). Order No. TAMP/52/2014-Genl. dated 28 November, 2014 relating to the guidelines on priority berthing of coastal vessels at Major Port. (b). Order No. TAMP/14/2016-Misc dated 9 February 2016 relating to prescription of lower charges for cargo & vessels related services as well as special discount in port charges for the services rendered after regular hours by the Major Port Trusts and BOT Operators operating thereat in pursuance of MOS letter No. PD/14033/101/2015-PD.V dated 3 February 2016. (c). Letter No. TAMP/35/2013-Misc. dated 7 August 2014 directing all Major Port Trusts to prescribe a suitable note in their respective SOR regarding applicability of wharfage rates for Defence Stores in such a way that there is no ambiguity in the mind of users on the application of the prescribed rates. (d). Letter No. PD-25021/7/2015-PD.1 dated 16 April 2015 of MOS directing to all Major Port Trusts to follow the TAMP letter No. TAMP/53/2002-Misc dated 25 March 2015 regarding wharfage charges on vessel manifested as cargo in the Import General Manifest (IGM) or Export General Manifest (EGM).	The provisions covered under all the common orders are considered in the submission of General Revision proposal and the financial implications involved are also taken care of.

	<p>(e). Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 10 June 2016 clarification regarding levy of concessional charges for costal cargo/ container.</p> <p>It is, however, seen that the port has not included the provisions prescribed in the above common adoption Orders / communication in the proposed SOR. The port is requested to incorporate the same in the draft proposed SOR. The impact, if any, on the revenue estimates may be captured in Form-3.</p>	
9.	<p><u>Adjustment of Additional surplus:</u></p> <p>As per clause 4.1 of the Tariff Policy, 2015, (a) additional surplus assessed by TAMP in earlier tariff Orders which remain unadjusted has to be transferred by Major Port Trusts to any fund as desired by the Port Trust. (b) Additional surplus, if any, accruing to the Major Port Trusts during the period of application of existing Scale of Rates till the effective date of implementation of the new Scale of Rates fixed under this policy should be assessed and transferred to the General Reserve and use the funds for the purpose of development, creation and/ or modernization of the port infrastructure facilities. As regard (a) above, it is seen that there is no past period unadjusted surplus in the case of VOCPT. As regard (b) above, the VOCPT is requested to assess the additional surplus, as required under clause 4.1 of the said Tariff Policy and furnish the same for information.</p>	As regards (b), as the existing SoR is lesser by 21.20% over proposed SoR, there shall not be any accrual of additional surplus due to extension of existing tariff till revision of revised rates.
10.	<u>Performance Standards</u>	
(i).	The VOCPT has proposed performance standards in Form-6. The VOCPT is requested to explain the basis of the proposed Performance Standards.	In view of new berthing Policy this is withdrawn.
(ii).	Clause 3.2. of the Tariff Policy 2015 stipulates that the indexation of SOR as provided in Clause 2.8 will be subject to achievement of Performance Standards committed by Major Port Trusts. If a particular port does not fulfil the Performance Standard, no indexation would be allowed during the next year. The VOCPT may, therefore, incorporate a suitable clause in the SOR on indexation in line with the provision stipulated in clause 3.2.	Yes. The relevant clause is suitably incorporated in the draft SoR is furnished

10.2. While furnishing additional information / clarification, the VOCPT has also slightly revised draft SOR duly taking into consideration the additional information / clarification sought by us. Some of the main modifications made by the VOCPT in the proposed draft SOR dated 9 August 2016 are given below:

- (i). The port has proposed port dues for sailing vessels which port stated was inadvertently deleted in the earlier proposed SOR.
- (ii). The port has retained the existing definition of pilotage fee.
- (iii). The port has stated that it proposes admission of an average expenditure of ₹19.21 crores towards share of port security, welfare and medical relating to cargo handling services and port and dock facility in addition to 25% cap of operating expenditure already proposed by the port in a proposal towards Management and General Overheads. The details of said expenditure are as under:

Sl. No.	Description	2011-12	2012-13	2013-14
1	Port Security	646.48	806.28	1087.24
2	Labour Welfare & Medical Expe.	1174.87	981.60	1066.64

3	Total	1821.35	1787.88	2153.88
Average Expenditure		1921.03		

(iv). Performance Standards:

The port has proposed modified Performance Standards as given below:

Sr. No.	Performance Parameters		Performance Achieved 2015-16	Proposed Performance Standards (2016-17)
1	Cargo related Services			
(a)	Av. Ship berth day Output (in tonnes)			
(i).	Container		21,018	21,500
(ii).	Break bulk		2,113	2,120
(iii).	Dry bulk – Mec		13,187	13,500
(iv).	Dry bulk – Con		10,331	10,400
(v).	Liquid bulk		3,829	3,830
	Overall		10,239	10,500
(b)	Av. Moves per hour (in TEUs) in respect of Container		21	21
2	Vessels Related Services			
(a)	Av. TRT of vessels (in days) (port + Non-port A/c)			
(i).	Container		1.35	1.30
(ii).	Break bulk		5.33	5.30
(iii).	Dry bulk – Mec		5.13	5.10
(iv).	Dry bulk – Con		6.48	6.40
(v).	Liquid bulk		2.96	2.90
	Overall		3.73	3.30
(b)	Av. PBD of vessels (in days) (port + Non-port A/c)			
(i).	Container		0.28	0.25
(ii).	Break bulk		2.21	2.20
(iii).	Dry bulk – Mec		1.41	1.40
(iv).	Dry bulk – Con		3.00	2.90
(v).	Liquid bulk		0.98	0.90
	Overall		1.41	1.40
3	Any Other parameters found relevant by the Port			
(i).	Gross Productivity (gross / MT/ day)	Coal –Mechanized at CJI & CJII	12,030	12,630
(ii).		Coal-Conventional at IX Berth.	23,305	24,470
(iii).		Coal-Conventional at III & IV Berth	10,551	11,606
(iv).	Evacuation Yard throughput (MT per Sq.m)	Coal Conventional	15.35	16.00
(v).	Short term Agreement with DBGT (MMT/YR)	Copper Concentrate handled at VIII berth	0.18	0.30
4	% of idle time at berth			
(i).	Container		0.00	0.00
(ii).	Break bulk		32.35	31.40
(iii).	Dry bulk – Mec		13.34	12.95
(iv).	Dry bulk – Con		27.16	26.35
(v).	Liquid bulk		23.14	22.45
	Overall		20.84	20.21

10.3. Subsequently, the VOCPT vide its email dated 26 August 2016 has clarified that in the proposed SOR the wharfage rate for Coal by whatever name prescribed in Customs Document and used for Thermal Power Plants for coastal in Zone-A may be read as ₹48.53/tonne instead of ₹29.12/tonne and the VOCPT had also requested to incorporate proposed levy of pollution cess on dusty cargo as under which though proposed in the proposal was not incorporated in the proposed SOR:

“Schedule 3.5 : Cess for Pollution Mitigation Measures.

Cess for Pollution mitigating measures shall be levied at ₹5/- per M.T in respect of dusty cargoes discharged at the Port (Excluding cargo handled through closed conveyors).”

11.1. With reference to the second point of action decided at the joint hearing brought out above, the VOCPT has furnished its comments on the comments made by users / user organisations vide its letter dated 9 August 2016.

11.2. With reference to the third point of action decided at the joint hearing brought out above, the VOCPT has clarified regarding application of Pollution cess to coal handled at Coal Jetty-I and II that as the coal is being handled in coal jetty-I and II in the closed conveyor system the said pollution cess will not apply and hence suitable modification in the proposed SOR also does not arise.

11.3. With reference to the fourth point of action decided at the joint hearing brought out above, the VOCPT has stated that as far as the productivity norms are concerned, action is being taken to finalise the productivity norms as per Ministry's directions in consultation with users/ user associations and hence the productivity norms already submitted and uploaded in the port website may be considered by this Authority till finalisation.

11.4. With reference to the fifth point of action decided at the joint hearing brought out above, the proposal of the VOCPT has already been brought out.

The VOCPT has requested that the amount of ₹1,921.03 lakhs may be appropriately included. Though after considering the above expenditure under Management & General Administration overheads, the revised rate of increase comes to 36.69%, the port has requested to consider and approve a ceiling increase of 27.70% only as proposed earlier vide its letter dated 7 May 2016. The Port has stated that the same is being placed in the ensuring Board Meeting.

12.1. As stated earlier, this Authority has based on the request made by the VOCPT passed an Order dated 19 May 2016 extending the validity of existing SOR of VOCPT including the Pension Fund Levy prescribed in the existing SOR till 31 August 2016 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

12.2. In this regard, the TANGEDCO vide its letter no.CE/Coal/SE/E2/A4/F.TAMP/ D.18/2016 dated 27 May 2016 has requested this Authority to intervene in the matter and to instruct the VOCPT not to insist on collecting Pension Fund Levy @ 6.5% from 1 April, 2016 as VOCPT has no authority to collect Pension Fund Levy based on the proposal for extension without approval of this Authority. Further, TANGEDCO has requested to obtain their views on the proposal for extension of Pension Fund Levy by VOCPT before passing any Order on the proposal.

13. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

14. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following points emerges:

- (i). The Scale of Rates (SOR) of VOCPT was last revised by this Authority in August 2014. The validity of the SOR of VOCPT approved by this Authority vide its Order dated 4 August 2014 is till 31 March, 2016. In the said Order, based on the estimated cost position, this Authority decided to maintain status quo in the then existing SOR of VOCPT and the special rate for dredging was discontinued. Pension Fund Levy of 6.5% was approved by this Authority which was to cease to apply from 1 April 2016. As regards, levy for deployment of labour from Cargo Handling Division (CHD), an increase of 167%, 223% and 207% was approved for other main pool cargo, coal at coal jetty II and salt respectively. The Pension Fund Levy for CHD was approved at 25.10 per tonne.

The VOCPT has filed its proposal for general revision of its SOR under the Tariff Policy 2015 on 7 May 2016.

As brought out in earlier paragraphs bringing out the factual position, the draft proposed SOR filed by VOCPT vide its letter dated 7 May 2016 took into consideration the earlier direction of the Ministry of Shipping (MOS) dated 17 September 2015 based on which this Authority had passed Order No.TAMP/4/2004-Genl dated 5 October 2015. As per the said Order, the VOCPT had, against the rate for coastal vessel, proposed a note stating that the rate for coastal vessel will be collected in Indian rupees upto 60% (of the rate juxtaposed) for foreign going vessel calculated by taking into account the exchange rate fluctuation. Subsequently, the MOS vide its letter dated 11 May 2016, directed this Authority to keep its earlier direction dated 17 September 2015 in abeyance and reinstated the MOS direction of 1st/ 3rd January 2005 and 9 March 2005. In pursuance of the said direction of the MOS, this Authority passed an Order dated 19 May 2016 to keep its Order dated 5 October 2015 also in abeyance. On being pointed out, the VOCPT has vide its letter dated 2 July 2016 furnished revised proposed SOR proposing specific rate for coastal vessel in line with the Order dated 19 May 2016 and modified Performance Standards.

As brought out in earlier paragraphs, VOCPT was requested vide our letter dated 13 July 2016 to furnish information/ clarification with reference to its proposal by 20 July 2016. After regular follow up, the port has furnished the requisite information / clarification along with revised draft SOR and modified Performance Standards vide its letter dated 9 August 2016. The information / clarification furnished by VOCPT vide its letter dated 9 August 2016 alongwith revised proposed SOR and submissions made by the port during the processing of the case are considered in this analysis. This case could be taken up for finalization only after receipt of information/ clarification from the port.

- (ii). (a). Clause 2.1 of the Tariff Policy 2015 requires each Major Port Trust to assess the Annual Revenue Requirement (ARR) which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final Audited Accounts of the three years 2011-12 (Y1), 2012-13 (Y2) and 2013-14 (Y3) subject to certain exclusions as prescribed the Clause 2.2. of the Tariff Policy 2015 and the Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on Capital Employed including capital work-in-progress obtaining as on 31st March 2014, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant.
- (b). The VOCPT has assessed the Annual Revenue Requirement (ARR) based on Audited Annual Accounts for three years i.e. 2011-12 (Y1), 2012-13 (Y2) and 2013-14 (Y3) duly certified by a practicing Chartered Accountant. The VOCPT has excluded the expenses not admissible in ARR computation for arriving at the Average annual expenses for the year 2011-12, 2012-13 and 2013-14. The following adjustments done by VOCPT in line with provisions prescribed in Clause 2.2. of Tariff Policy 2015 and Clause 2.2. of Working Guidelines are brought out for specific mention along with a few modification required to be done in the computation of the ARR for the reasons explained:
 - (i). As per Clause 2.2. (ii) of the Tariff Policy, 2015 and Working Guidelines interest on loan is to be excluded. The VOCPT has also not considered any amount towards interest on loan. On perusing the Annual Accounts for each of the three years, it is seen that interest on loan is nil. Hence the treatment given by the VOCPT is found to be in order.
 - (ii). (a). As per Clause 2.2(iii) of Tariff Policy 2015 and the Working Guidelines, 1/5 of one-time expenses like arrears of wages, pension/ gratuity, ex-gratia payments arising out of wage revision etc. are to be included in the Annual Revenue Requirement (ARR). Likewise, 1/5th of the Contribution to Pension Fund are to be included for the calculation of ARR. This means 4/5th of the above mentioned expenses are to be excluded in the ARR computation.
 - (b). The port has shown nil figures towards the one time expenses like arrears of wages, arrears of pension/ gratuity, arrears of ex-gratia payment. The port has confirmed there is no one time payment on the above accounts. The position is relied upon.
 - (c). The port has excluded ₹1,300.97 lakhs, ₹640 lakhs and ₹1,720 lakhs in the years 2011-12, 2012-13 & 2013-14 respectively as 4/5th of contribution to the pension fund. The port has reconciled the figures with the figures reported in the Annual Accounts of each of the years 2011-12 to 2013-14. It is seen from the reconciliation statement furnished by the port that the figures reported in the Annual Accounts of the port is towards Contribution to Pension Fund and Gratuity Fund. The port has given break up for both these contribution to the funds and considered 4/5 of the contribution to pension fund for exclusion as required as per clause 2.2 (iii) of Tariff Policy, 2015.
 - (iii). As per Clause 2.2. (iv) of Tariff Policy 2015 and Clause 2.2. (iv) of the Working Guidelines, Management and General Administration Overheads (MGAO) subject to a cap of 25% of aggregate of the operating expenditure and depreciation is only to be considered in the ARR calculation.

The MGAO reported in the Audited Annual Accounts is ₹5,221.51 lakhs, ₹5,729.93 lakhs and ₹6,816.73 lakhs for years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively.

In Form 2, to arrive at the admissible MGAO, the VOCPT has considered sum of operating expense and management and general overhead at ₹14,302.93 lakhs, ₹15,348.73 lakhs and ₹17,296.09 lakhs for years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively. From that after excluding the operating expense of estate, the VOCPT has finally assessed 25% on ₹13,669.69 lakhs, ₹14,884.87 lakhs and ₹15,918.26 lakhs for the 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively to arrive at the MGAO cap of ₹3,416.67 lakhs, ₹3,721.22 lakhs and ₹3,979.57 lakhs. Since MGAO reported as per Audited Annual Accounts is in excess of the prescribed cap of 25%, the VOCPT has considered ₹1,804.84 lakhs, ₹2,008.71 lakhs and ₹2,837.17 lakhs for years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively as exclusion from total expenses while assessing the ARR.

The port during the proceeding of the case has clarified that some of the expenses like CISF expenses, inspection related expenses, IT related expenses are captured under MGAO and hence the computation of MGAO in excess of 25% cap will be re-examined. Subsequently, the port has furnished the sum of port security and labour welfare expense and medical expense reported under the MGAO which is reported to be related to cargo handling services and port and dock facility to the tune of ₹1,821.35 lakhs, ₹1,787.88 lakhs and ₹2,153.88 lakhs. The VOCPT has requested this Authority to take cognisance of this while arriving at 25% cap of the operating expense for MGAO. In view of clarification furnished by the VOCPT, the above expenses which are reported to be related to cargo and vessel related activity are excluded from the MGAO and added to the operating expenditure in Form 2. This exercise is done only for the purpose of arriving the admissible cap of MGAO in view of submissions made by VOCPT that the two heads of expenses related to cargo and vessel related activity are captured in MGAO. It is relevant to state that similar adjustment was also made by the NMPT which was admitted by this Authority while revising the SOR of the NMPT.

Subject to above analysis, the cap on MGAO at 25% of the Operating Expenses works out to ₹2,566.63 lakhs, ₹2,735.71 lakhs and ₹2,813.85 lakhs for the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively. Since MGA reported as per Audited Annual Accounts is in excess of the prescribed cap of 25%, the excess of the prescribed cap level i.e. ₹8,33.53 lakhs, ₹1,206.35 lakhs and ₹1,849.00 lakhs for years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively is excluded from the total expenses for each of the year for computation of ARR.

- (iv). As per Clause 2.2(v) of the Working Guidelines notified by this Authority, all expenses relevant for captive berths are to be excluded from the computation of ARR. The VOCPT has excluded depreciation of ₹58.54 lakhs, ₹58.83 lakhs and ₹76.05 lakhs in the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively towards captive berths. However, the port has not shown any exclusion of operating expenses, allocated Management & Administrative Overhead (MAO) and allocated Finance & Management Expenses (FME) towards captive berth. The VOCPT has clarified that the port does not incur any direct Operating Expenditure and Finance & Miscellaneous expenditure items relating to captive berths operated by BOT Operators except depreciation relating to respective berths. Hence, the port has not shown any exclusion of operating expenses, allocated Management & Administrative Overhead (MAO) and allocated Finance & Management Expenses (FME) towards captive berths. The above clarification furnished by the VOCPT is relied upon.
- (iii). Following the provisions prescribed in clause 2.3. of the Tariff Policy 2015 and clause 2.3. of the working guidelines, the quantum of average expenses for the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 is arrived at ₹16,421.08 lakhs as against ₹15,500.46 lakhs estimated by the VOCPT.
- (iv). As per Clause 2.4 of Working Guidelines 2015 for computation of capital employed, the port has to exclude net value of fixed asset related to estate activity and net fixed assets transferred to BOT operators as on 31 March 2014 as per Audited Annual Accounts. The VOCPT has arrived at the capital employed figure based on the Audited Annual Accounts as on 31 March 2014 at ₹93,250.18 lakhs, which comprises of ₹88,644.92 lakhs towards Net fixed assets +

₹9,980.39 lakhs towards value of work-in-progress + ₹2,020.35 lakhs towards working capital - ₹650.69 lakhs towards net fixed assets related to Estate Activity - ₹6,744.79 lakhs towards net value of fixed asset transferred to BOT operators in respect of Beth No.VII, VIII and captive berth North Cargo Berth (NCB)-1. As regard, ₹1,732.05 lakhs excluded by VOCPT towards NCB-1, it is relevant to state that during the fixation of upfront tariff for this berth, it was made to understand by the port that the NCB-1 was constructed by the VOCPT on deposit terms as per the sanction of the MOS vide letter no.PD-11015/5/2006-TPT dated 22 October 2009. When requested to review exclusion of this item, the VOCPT has clarified that the exclusion is towards the net value of fixed assets relating to NCB-I pertaining to expenditure for common usage regarding road and electricity around the berth area developed by the Port for the operation of NCB-I and not relating to Berth. The port has confirmed that exclusion of the same is in order. Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances. The VOCPT has computed working capital as per norm prescribed in clause 2.5. of working guidelines at ₹2,020.35 lakhs. The capital employed as furnished by the VOCPT is relied upon and considered.

- (v). The total capital employed arrived by VOCPT is ₹93,250.18 lakhs. The Returns on Capital Employed at 16% is ₹14,920.03 lakhs which is considered in the ARR computation.
- (vi). The ARR estimated by VOCPT is the average of the expenditure for the three financial years 2011-12 to 2013-14 at ₹15,500.46 lakhs plus 16% ROCE at ₹14,920.03 lakhs aggregating to ₹30,420.09 lakhs as on 31 March 2014. Further, the VOCPT as per Clause 2.7. of Working Guidelines has indexed the said ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 and 2015-16 at 6% and 3.82% respectively and arrived at ceiling indexed ARR forwarding SOR at ₹33,477.41 lakhs for the year 2015-16.

From the ceiling indexed Annual Revenue Requirement (ARR) at ₹33,477.51 lakhs, the VOCPT has shown adjustment (reduction) of ₹5,637.03 lakhs being the Escrow Account balance as on 31.3.2014 and has arrived at the adjusted ceiling ARR of ₹27,840.48 lakhs and matched with the revenue estimated at the draft proposed SOR at ₹27,840.48 lakhs.

Clause 4.2 of the Tariff Policy, 2015 and Clause 2.11 of Working Guidelines state that balance in the Escrow accounts maintained by the Major Port Trust can be utilized for the purpose as decided by the Board of Trustees of the concerned Major port trusts. Thus, the Tariff Policy, 2015 and Working Guidelines do not require the Major Port Trusts to adjust the Escrow Accounts balance against the ARR. The ARR is the ceiling level and ports have the flexibility to draw the proposed SOR within the ceiling indexed ARR. When pointed out this position, the VOCPT has clarified that since Clause 2.11 of Working Guidelines provides that the balance in the Escrow accounts maintained by the Major Port Trust can be utilized for the purpose as decided by the Board of Trustees of the concerned Major port trusts, the Port has shown deduction of ₹5,637.03 lakhs from the indexed ARR.

It is relevant to state that in none of the other Major Port Trusts viz. New Mangalore Port Trust (NMPT), Cochin Port Trust (COPT), Visakhapatnam Port Trust (VPT), Kandla Port Trust (KPT), Mumbai Port Trust (MBPT) who filed the proposal under Tariff Policy, 2015 have proposed such an adjustment. The Tariff Policy, 2015 do not require the Major Port Trusts to adjust the Escrow Accounts balance against the ARR. The ARR is the ceiling level and ports have the flexibility to draw the proposed SOR within the ceiling indexed ARR. Hence this adjustment of considering the Escrow Account Balance as reduction from the ARR is not being shown in the revised ARR computation prepared by us. By not showing this adjustment in the ARR does not refrain the port to do so as they have the flexibility under Tariff Policy, 2015 to utilise the funds in Escrow Balance as decided by the Port Trust Board.

- (vii). Subject to above modification, the ARR calculation furnished by the VOCPT vide its letter dated 7 May 2016, which is duly certified by Chartered Accountant is relied upon. A summary of the ceiling indexed ARR furnished by the VOCPT and as considered by this Authority subject to modification explained in the above analysis is given below:

(Amount ₹ in lakhs)			
Sr. No.	Particulars	As estimated by the VOCPT	As considered by this Authority
1.	Average Expenses for the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14	15,500.46	16421.08
2.	Capital employed including net fixed asset, capital work-in- progress as on 31.03.2014 and working capital as per norms	93,250.18	93,250.18
3.	Return on capital employed @ 16%	14,920.03	14,920.03
4.	ARR as on 31 March 2014 (4=1+3)	30,420.49	31,341.11

5.	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 (6%)	32,245.72	33,221.58
6.	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2015-16 (3.82%)	33,477.51	34,490.64
7.	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)	33,477.51	34,490.64
8.	Revenue estimated by VOCPT at the proposed Scale of Rates	27,840.48	27,840.48

- (viii). As per Clause 2.6. of Tariff Policy 2015, the Major Port Trusts have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the Scale of Rates within the ceiling of indexed ARR, duly certified by a practicing Chartered Accountant. The port has proposed uniform hike of 27.70% in all tariff items for vessel related charges, cargo related charges and miscellaneous charges. Pension Fund levy of 6.5% is dispensed with. After dispensing the Pension Fund levy, the net increase is 21.20% only.

It is seen that the port, while estimating revenue at proposed SOR, has considered the revenue earned during the year 2014-15 and increased it by the proposed tariff hike of 27.7% to arrive at estimated revenue at the proposed Scale of Rates. The port has proposed uniform wharfage rate for coal cargo by whatever name described in the Customs Document. Further, port has proposed new pollution cess on dusty cargo at ₹5/tonne. The port has also proposed few modification in the existing conditions and has also proposed new conditionalities which are discussed in the subsequent paragraphs.

As per the format prescribed for estimating the revenue, the VOCPT is required to estimate revenue for each tariff items viz. cargo, vessels and miscellaneous services at the proposed rate for the actual traffic handled by the port in the year 2014-15. Despite request to furnish detailed working of revenue estimation indicating each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding traffic handled in 2014-15 as required as per Clause 2.9. of the Working Guidelines, the VOCPT has maintained its stand that actual earnings of 2014-15 is used as a base and proposed increase applied thereon to arrive at the revenue estimates at the proposed tariff on the existing SOR is computed. The port has confirmed that the total GRT vessel considered in the revenue estimates for vessel related charges matches with the actual total GRT of the vessel handled by the port for the year 2014-15. The port has also confirmed that volume of cargo considered in the revenue estimates matches with the actual cargo handled and reported in the year 2014-15 net of tonnage handled through PPP Operator viz., VII Berth and VIII Berth Container Terminal and NCB I. As regards new tariff item proposed at ₹5 per tonne towards pollution cess on dusty cargo, the VOCPT has captured revenue estimate of ₹542.72 lakhs in the revenue estimates.

The earlier paragraphs tabulating the information sought from the port lists out a few tariff items for which revenue at the proposed Scale of Rates is not found to be estimated. The VOCPT was requested to estimate the revenue at proposed rates for the above items also. Alternatively, the VOCPT may leave reasonable amount of ARR uncovered to take care of tariff of the above of few items for which revenue is not estimated. The port has clarified that for those items listed therein, revenue is meager and hence it is clubbed under basic vessel related income and the revenue estimation has been calculated. For the new tariff item viz. wharfage rate for handling car and vehicles, the port has stated that since this is new cargo item expected in future, the impact of financial implication could not be quantified.

Based on the above clarification furnished by the port and recognising that the revenue estimates is duly certified by the practicing Chartered Accountant, the revenue estimated by the VOCPT is relied upon.

The port has also furnished copy of the Board resolution of VOCPT approving the proposed Scale of Rates and Performance Standards.

- (ix). The computation of ARR as furnished by the VOCPT is attached as **Annex - I**. Subject to the above analysis, the modified ceiling indexed ARR works out to ₹34,490.64 lakhs as against ₹33,477.51 lakhs estimated by the VOCPT. The computation of modified ARR is attached as **Annex - II**. The revenue estimated by the VOCPT at the proposed SOR is ₹27,840.87 lakhs. As brought out in the subsequent paragraphs, the VOCPT has stated that for a few tariff items / conditionalities, the revenue cannot be quantified. Considering the revenue gap between the ceiling indexed ARR for the port as whole as assessed in the subsequent paragraph, and revenue estimate at proposed tariff, the income arising on account of few new tariff items/ conditionalities and modification in the existing conditionalities for which income is not estimated would get subsumed in the revenue gap of ₹3,899.31 lakhs as estimated in the analysis given in the subsequent paragraph for the port as a whole.

- (x). The port has stated that CHD is to function as a separate self-sufficient unit as per merger settlement condition. The VOCPT has furnished separate computation of ARR for its CHD in prescribed Form-1. The VOCPT has assessed the Annual Revenue Requirement (ARR) based on figures for CHD reported in the Audited Annual Accounts for three years i.e. 2011-12 (Y1), 2012-13 (Y2) and 2013-14 (Y3) duly certified by a practicing Chartered Accountant. The ARR estimated by the VOCPT for CHD and modifications done thereon are discussed hereunder:
- (a). For arriving at the average expenditure based on Audited Annual Accounts for three years i.e. 2011-12 (Y1), 2012-13 (Y2) and 2013-14 (Y3), the VOCPT has taken the operating expenditure reported in the Annual Accounts of the VOCPT for each of these years, which is considered.
- (b). As regards, the Finance and Miscellaneous Expenditure (FME), the port has taken the FME reported in the Annual Accounts of the VOCPT for each of three years and has excluded the Contribution to Pension fund for CHD reported in the Annual Accounts of the VOCPT reported at ₹354.00 lakhs, ₹294.98 and ₹nil in the years 2011-12 to 2013-14 respectively therefrom and has considered the balance FME i.e. ₹1645.90 lakhs, ₹1058.08 lakhs and ₹1119.98 lakhs. The VOCPT has then added opening shortfall in the Pension Fund to the tune of ₹6,281.76 lakhs, ₹10,720.69 lakhs and ₹21,136.00 lakhs in each of the above years.

The port has assessed total expenditure before adjustments at ₹13,093.62 lakhs, ₹17,532.67 lakhs and ₹28,101.39 lakhs respectively. All the adjustments prescribed in the Tariff Policy, 2015 is considered as nil by VOCPT except for one adjustment. The port has excluded 4/5 of the opening shortfall in the Pension Fund from the total expenditure at ₹5,025.41 lakhs ₹8,576.55 lakhs and ₹16,908.80 lakhs for the years 2011-12 to 2013-14 respectively. The port has stated that the pension Fund shortfall as on 01.4.2011 at ₹6281.76 lakhs and as on 1.4.2012 at ₹10,720.69 is available in the Orders dated 11.10.2011 approved by this Authority vide para No.10.1.(viii) and Order dated 04.8.2014 vide para No.5.1.(xiv) (e) respectively. The basis for ₹21,136.00 lakhs remains unexplained.

In other words, the VOCPT has added 1/5th of the opening shortfall in Pension Fund for the years 2011-12, 2012-13 & 2013-14 respectively while estimating the ARR of CHD. The port has stated that in respect of CHD, there is no surplus funds available to meet the huge shortfall in Pension and Gratuity Fund with respect to actuarial valuation. Clause 2.11 of the working guidelines providing for dispensing with Pension Fund Levy. This will result in heavy financial burden to CHD to meet the heavy shortfall in Pension and Gratuity Fund. The port has argued, as there is no Escrow fund available in CHD, utilizing the same to meet the shortfall is not possible in CHD (which is to be self-sufficient as per Memorandum of Settlement dated 27.7.2011), the port has proposed to cover 1/5th of the opening shortfall of each year under reference as expenditure.

The approach adopted by the VOCPT of arriving at the ARR by adding 1/5th of the shortfall in the opening balance in the Pension Fund is not in line with the provisions prescribed in the Tariff Policy, 2015 and Working Guidelines. In none of the other Major Port Trusts whose tariff is fixed following Tariff Policy, 2015 including Kandla Port Trust, New Mangalore Port Trust where there is separate CHD, such adjustment of opening shortfall in the Pension Fund is done while approving the tariff for CHD. Moreover, it is relevant to state that the approach adopted by VOCPT of considering opening shortfall assessed in the two Orders referred by VOCPT dated 11 October 2011 and 4 August 2014 is not correct as in the said Orders, based on the shortfall assessed, this Authority has approved pension fund levy for CHD at ₹9/tonne and in the Order dated 11 October 2011 and ₹25.10/ tonne in the Order dated 4 August 2014. Since the approach adopted by the VOCPT of considering 1/5th of the opening shortfall in the Pension Fund in the years 2011-12 to 2013-14 in the Pension Fund is not in line with the provision in the Tariff Policy in 2015, there is no extra ordinary situation warranting deviation from the Tariff Policy, 2015 only in the case of the VOCPT. Hence this adjustment done by the VOCPT in the ARR computation of CHD is not considered.

Thus, in the cost statement prepared by us, FME as reported in the Annual Accounts is considered. The VOCPT has not reported any adjustment as regards interest on loan, captive berth, estate and Management and General Overhead which is accepted. The adjustment of 4/5th of the Contribution to Pension Fund is done based on the figures reported in the Annual

Accounts for each of the years which comes to ₹283.20 lakhs, ₹235.98 and ₹nil in the years 2011-12 to 2013-14 respectively. This adjustment is in line with the prescription in the Tariff Policy 2015.

- (c). The VOCPT has not considered any amount towards one time expenses like arrears of wages, arrears of pension / gratuity / arrears of ex-gratia payment etc. The Annual Audited Accounts for the year 2013-14, however, reports that ₹10,90,62,275 and ₹11,65,857 towards Wage revision arrears and ACP arrears respectively for the year 2013-14. On being pointed out, the VOCPT has clarified that this impact pertains to the 2013-14 only and is shown distinctively in the Accounts. The port has confirmed that no adjustment is required on this account. This position is relied upon as the figures are duly certified by a practicing Chartered Accountant.
- (xi). Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances. The port has not considered Inventory and Sundry Debtors for CHD. The cash balances estimated by VOCPT are seen to be computed as per norms prescribed in clause 2.5. of Working Guidelines. The working capital estimated by VOCPT at ₹580.38 lakhs is taken into account.
- (xii). The total capital employed arrived by VOCPT is ₹588.15 lakhs. The Returns on Capital Employed at 16% is ₹94.10 lakhs which is considered in the ARR computation.
- (xiii). The ARR estimated by VOCPT is the average of the expenditure for the three financial years 2011-12 to 2013-14 at ₹9,405.64 lakhs plus 16% ROCE at ₹94.10 lakhs aggregating to ₹9,499.74 lakhs as on 31 March 2014. Further, the VOCPT as per Clause 2.7. of Working Guidelines has indexed the said ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 and 2015-16 at 6% and 3.82% respectively and arrived at ceiling indexed ARR forwarding SOR at ₹10,454.39 lakhs for the year 2015-16.
- (xiv). The computation of ARR for CHD as furnished by the VOCPT is attached as **Annex - III**. Subject to above analysis, the ceiling indexed ARR estimated by VOCPT is modified. The computation of modified ARR is attached as **Annex - IV**. Subject to above modification, the average expenditure for the three years 2011-12 to 2013-14 works out to ₹6,906.34 lakhs plus 16% ROCE as estimated by VOCPT aggregating to ₹7,703.93 lakhs. Except for the modification explained the above analysis, the ARR calculation furnished by the VOCPT vide its letter dated 7 May 2016, which is duly certified by Chartered Accountant is relied upon. A summary of the ceiling indexed ARR furnished by the VOCPT for CHD and as considered by this Authority subject to modification explained in the above analysis is given below:

(Amount ₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	As estimated by the VOCPT	As considered by this Authority
1.	Average Expenses for the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14	9,405.64	6,906.34
2.	Capital employed including net fixed asset, capital work-in- progress as on 31.03.2014 and working capital as per norms	588.15	588.15
3.	Return on capital employed @ 16%	94.10	94.10
4.	ARR as on 31 March 2014 (4=1+3)	9,499.74	7,000.45
5.	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 (6%)	10,069.73	7,420.47
6.	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2015-16 (3.82%)	10,454.39	7,703.93
7.	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)	10,454.39	7,703.93
8.	Revenue estimated by VOCPT and by TAMP within the ceiling indexed ARR	10,454.39	10,454.39

- (xv). The port has proposed to increase the CHD levy by 51.20% to meet the estimated ARR of ₹10,454.39 lakhs.

The existing Pension Fund levy of ₹25.10/ tonne in CHD has been dispensed with as per Working Guidelines of Tariff Policy, 2015. The port has reported that after dispensing of pension fund levy the net increase in CHD is 2% for cargoes other than coal and salt and 13% for coal at coal jetty.

The port has confirmed that the actual cargo traffic handled by CHD in 2014-15 at 158.80 lakh tonnes and the same is considered in revenue estimates. The revenue estimated by the VOCPT at the proposed increase of 51.20% is ₹10454.39 lakhs. The ceiling ARR and revenue estimated by the VOCPT at the

proposed tariff are duly certified by the Chartered Accountant which is relied upon. However, in view of the above analysis the modified ARR works out to ₹7,703.93 lakhs.

As stated earlier, the port has assessed the ARR and proposed tariff separately for port operations and for CHD. In other general revision proposals like the NMPT, KPT, MBPT, the ports had assessed ARR for the port as a whole including CHD while seeking revision under Tariff Policy, 2015 though in their cases also, the Accounts of CHD is maintained separately.

If the position for the port as a whole is analysed, the total modified ceiling indexed ARR for port operations plus CHD works out to ₹42,194.57 lakhs i.e. ₹34,490.64 lakhs assessed for port operations and ₹7,703.93 lakhs for CHD. As stated earlier, the revenue estimate from port operations at the proposed tariff increase of 27.7% in port operations is ₹27,840.87 lakhs. Balance ARR is ₹14,353.70 lakhs i.e. (₹42,194.57 lakhs - ₹27,840.87 lakhs) which has been left uncovered. The revenue estimated by the VOCPT at the proposed increase of 51.20% for CHD is ₹10,454.39 lakhs. Considering the revenue gap of ₹14,353.70 lakhs, tariff increase of 51.20% proposed by the VOCPT is allowed as proposed by the port. This will still leave a revenue gap of ₹3,899.31 lakhs. The income arising on account of few new tariff items/ conditionalities and modification in the existing conditionalities for which income is not estimated would get subsumed in the revenue gap of ₹3,899.31 lakhs.

As per clause 2.11 of the Working Guidelines issued by this Authority, Pension Fund levy, if any, approved by this Authority is to be dispensed with. Hence the proposal of VOCPT to dispense with the existing Pension Fund levy for CHD is accepted.

- (xvi). In the original proposed SOR, the VOCPT had proposed deletion of existing port dues separately prescribed for Sailing Vessels at Sl. No.2. On being pointed out, the port has clarified that the said deletion was typographical error and has proposed tariff for the same in the revised SOR applying 27.7% tariff increase as proposed for other items. The port has confirmed that revenue estimation already captures revenue for this tariff item.
- (xvii). The VOCPT had earlier proposed some modification in the definition of pilotage fee by inserting the words, "subject to a maximum of Two tugs" Clause 10.4 of the Working Guidelines, 2015 defines pilotage as Pilotage-cum-towage fee to be composite rate and shall include one inward and one outward movement with required number of tugs/launches of adequate capacity and shifting/s of vessels for 'Port convenience.' On pointing this out, the VOCPT has retained the definition prescribed in the existing SOR.
- (xviii). The port has proposed new notes under schedule 2.2.3 (i) and (ii) prescribing minimum shifting charges. The port has clarified that the minimum shifting charges are proposed at 25% / 50% of the minimum pilotage fee. The proposed notes is approved as proposed by the port. The port has clarified that instances are very rare and negligible in financial terms.
- (xix). The existing SOR prescribes charges for shifting of a vessel to outer anchorage/ any other berths on account of its non performance. Note 9 (b) prescribes levy of 25% of the pilotage fees prescribed in Schedule 2.2.1 in case a vessel is shifted to berths I to VI or between Coal Jetty I and II and Oil Jetty.

The port has now, in the said note, added the berth nos.VII, VIII, North-Cargo Berth (NCB) Nos.I & II as well. The port has clarified that as there could be possibility of shifting of vessels to outer anchorage/any other berth on account of its non performance in respect of vessels berthed / to be berthed at berths VII, VIII and NCB-I & NCB-II, this clause is modified accordingly. The port has confirmed that the instances are very rare and negligible in financial terms. Based on the clarification furnished by the port, the modification to the existing note proposed by the VOCPT is approved.

- (xx). There was typographical error observed in the coastal tariff for other crafts prescribed at Sl.No.3 under Schedule No.2.4.2 Berth Hire Charges for other Vessels. Applying proposed increase of 27.7% to the existing foreign going rate, comes to ₹2.12 per GRT/hour instead of proposed rate of ₹2.18/GRT/hour. The port has stated that typographical error is verified and corrected. However, correction does not seem to have been done in the revised proposed SOR. The corrected rate ₹2.18 /GRT/hour is prescribed in the SOR. Apart from that, there are some arithmetical error which are corrected in the revised SOR.
- (xxi). (a). The port has proposed a new conditionality at note 4 under Schedule No.2.4.2 Berth Hire Charges for other Vessels proposing cargo wise output norms for determining berth occupancy and levy of penal berth hire charges.

Subsequent to the table proposing output norms under note 4, the port has proposed a note stating that port reserve the right to revise the norms as per the field condition and that decision of Traffic Manager in this regard shall be final and binding. Since the performance standards notified by this Authority will have linkage to indexation in tariff, it appeared that the proposed note to revise the norms during the currency of the tariff cycle may run in conflict with indexation of tariff which has linkage to pre-determined performance standards. The port was, therefore, requested to review the proposed note.

The port has clarified that as per the New Berthing Policy for Dry Bulk for Major Ports issued by the Ministry of Shipping vide Clause 7.2., Performance norms in a phased manner is to reach the target levels achievable for each commodity for the given infrastructure available at berths. To this end, performance norms for different commodities alongwith anchorage charges will have to be computed every quarter by all Ports. Hence, the proposed note is inserted with provision to revise the norms as per the field condition. The words "decision of the Traffic Manager --- final and binding" is deleted by the VOCPT in the revised proposed SOR. In view of the clarification furnished by the VOCPT and also recognising that none of the users/ user associations have made any adverse remark to the proposed note, this Authority decides to go by the proposal by the port except for deleting of the words that port to revise the norms as per the field condition. It is relevant to state here that the ports already have the flexibility to relax the output norms. In case the port proposes to revise the prescribed output, upwards approval of this Authority will be required as the output norms are linked to penal/ rebate in berth hire charges. In view of the position, the proposed condition of the port revising the norms as per the field condition is deleted.

The Tuticorin Stevedores Association (TSA) has suggested some modification in the proposed productivity norms. The port has clarified that for each cargo Port has derived the productivity from the actuals tonnage handled in the last three years after taking into the account the existing infrastructure facilities available in the Port. The VOCPT has stated that Ship Agents Association vide their letter dated 18 December 2015 had requested the Port to revisit the norms stating that the newly revised norms are very high which may not be achieved by them. After discussion with the representatives of the Ship Agent's Association and with the representative, who handled the above said cargoes, the Port has revised the norms for a few cargo items based on their request. The port has stated that considering the Port users request, the port had revised the norms based on the three years average for each cargo by taking the total tonnage handled during the past 3 years in the divided by the number of hooks engaged for each cargo and the minimum is only 75% of said per day average tonnage. The port has emphatically stated that the request of the TSA to further reduce the output norms is not justifiable.

During the processing of the case, the VOCPT had stated that some fine tuning is required in the proposed productivity norms. In this regard, the VOCPT was requested to furnish fine-tuned productivity norms and send the productivity norms. In this regard, the VOCPT has stated that as far as the productivity norms are concerned, action is being taken to finalise the productivity norms as per Ministry's directions in consultation with users/ user associations and hence has requested this Authority to consider the productivity norms submitted in the proposal till finalization by the port. Hence, the output norms as proposed by the port is prescribed in the SOR. If port envisages to do so, the VOCPT may approach this Authority with a proposal in consultation with the trade to notify the modified productivity norms.

- (c). The port has proposed penalty of 50% of additional berth hire if productivity of vessel is less than the proposed output norms. If vessel achieves productivity which is 66.66% less than the output norms, port has proposed penalty of 75% additional Berth hire for stay exceeding stipulated hours. The port has proposed discount of 10% and 20% on Berth hire charges if productivity achieved is 125%/ 150% more than the prescribed output norms per day.

Apart from cargo-wise output prescribed under note (4), the port has also proposed separately output norms and provisions relating to penalty for non achievement of the output norms and rebate in berth hire charges for achieving higher than the productivity norms in respect of Coal vessels handled at Berth No. IX & Berth nos. III and IV. The port proposed penalty at 3 times and 5 times the berth hire (excluding wharf crane element) if the proposed output norms are not

achieved. Likewise, rebate of 10% / 20% in berth hire charges are proposed if the proposed output norms are achieved.

The Tuticorin Stevedores Association (TSA) has stated that productivity quantum fixed for coal at berth nos.III and IV of VOCPT and Berth No.IX will practically depend on the availability of discharge space at Berth and evacuation of previous vessel cargoes occupying the Berth that may hinder the quantum of discharge of coal vessels at III, IV and IX Berths. As such, TSA has suggested that the proposed penalty for discharging less than the productivity norms must be reduced to extra one time Berth hire for vessel exceeding the stay period calculated for the discharges norms of 12000 MT/ day and for less than the discharge norms of 10,500 MT it can be imposed at 2 times of Berth hire stay.

The port has clarified that the benchmark productivity on Coal handling at berth No.IX and berth III & IV is proposed based on the recommendations of M/s.BCG in their report dated 04.11.2015 (non-negotiable as instructed by Ministry of Shipping). The port has emphatically stated that the suggestion of TSA for revision of discharge norms at Berth III, IV & IX for imposing of penalty / rebate may not be considered.

The port has further stated that the revised productivity norms issued by the Ministry of Shipping for Dry bulk cargoes in the Berthing Policy, 2016 supersedes the productivity norms proposed by M/s BCG. The port has, however, stated that in the proposal, the proposed the productivity norms are based on the recommendations of the consultant. The port has also proposed notes relating to penalty / rebate linked to Future Output. The port has clarified that the future output denotes that after implementation of mechanization operations at IX Berth and erection of 2 nos. of HMC at berth nos.III and IV, the higher output norms proposed as future output will apply.

The port has stated that the penalty and rebate scheme was formulated and recommended by M/s.BCG in their report dated 04.11.2015 (non-negotiable as instructed by Ministry of Shipping). The port has also stated that the extent of penalty at 3 times on the extra berth hours is also there in the new Berthing Policy, 2016 issued by the MOS.

It was pointed out to the VOCPT that the proposed conditions governing levy of penalty and grant of rebate have not been prescribed in the reference tariff approved for the berth no.(IX) and VOC III & IV. The VOCPT was, therefore, specifically requested to examine whether prescription of the proposed conditions would give rise to disputes with the successful bidders of berth no.(IX) and VOC III & IV.

In this regard, the port has clarified that there are no PPP operations in Berth No. IX, VOC III & IV, as these berths are operated by VOC Port. The port has stated that only in berth no.IX given on license basis, HMC is deployed at present. The port has clarified that penalty and grant of rebate are to be on vessel operators. The port has thus proposed to continue with the notes proposed by it in the earlier SOR. It is relevant to state that all the concerned users, all the concerned BOT operators including the crane operator Imcola Crane Company Pvt. Ltd (ICCPL) were consulted on the subject proposal. None of the users, user associations or ICCPL have made any adverse remarks on the proposed conditions. That being so, and since the VOCPT after examining the matter has proposed these conditions in the SOR and the port has also stated that the proposed conditions are applicable on vessel operator, the notes and conditions relating to penalty and rebate in berth hire charges in respect of coal vessels handled at berth nos.IX, III and IV as proposed by VOCPT are approved along with rebate/ penal provisions proposed by VOCPT in respect of cargo other than cargo handled at Berth nos.III, IV and IX.

- (d). The port was requested to furnish the working of additional income likely to accrue in view of the each of the proposed conditions and also show where it is captured in the revenue estimates. The port has stated that as clause relates to penalty for lesser productivity and incentive for higher productivity, the financial implication is beyond estimation and the same will be negligible. As stated earlier, there is revenue gap ₹6,649.77 lakhs and income from the proposed new conditionalities for which income is not estimated would get subsumed from the said revenue gap.

- (xxii). The existing SOR at Note 9 under schedule 2.4.2 prescribes a note stating that one day Berth Hire Charges is chargeable as the minimum charges for cancellation of services requisitioned. This will include amendment to Berthing Schedule, cancellation of Berthing, amendment to Computer entry in the system for E-booking etc.

The VOCPT whilst retaining the existing said note has proposed two new notes under schedule 2.4.2 at Sl. No.11 viz. (i) If the intimation for cancellation is received in advance before 24 hours of the time of services requested, there will be no penal berth hire charges; otherwise the same at one day's berth line is to be levied and (ii). The amount of penalty for amendment is at ₹5,000/- per amendment.

The port has clarified that the users had requested to withdraw one day penal berth hire charges levied for cancellation of vessel booking as the same is exorbitant. Hence, to consider the request and also for amendment of berthing programme, it is proposed to relax the conditionality by incorporating the above mentioned two new Notes. The port has clarified that revenue impact on this issue could not be predicted as it is not a recurring one. Since the proposed two notes are reported to be based on the request of trade, the same is approved.

- (xxiii). In the wharfage schedule, the tariff prescribed for coal and coke in the existing SOR and the proposed nomenclature and tariff for cargo items under coal and coke is tabulated below for ease of reference:

(a). As prescribed in the existing SOR.

Sl. No.	Particulars	Unit of Charge	Rate in ₹per tonne			
			Zone A		Zone B	
3.	COAL & COKE		Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
	(a). Charcoal in bags/bulk.	1 M.T.	28.00	16.80	12.00	7.20
	(b). Steaming (Non-coking Coal)	1 M.T.	27.00	16.20	16.20	9.70
	(c). Coal other than Steaming (Non-coking Coal) and coke in bulk	1 M.T.	30.00	18.00	18.00	10.80
	(d). Coal and Coke handled through Coal Jetty (other than thermal coal).	1 M.T.	38.00	22.80	--	--

(b). As proposed by the VOCPT

Sl. No.	Particulars	Unit of Charge	₹ per tonne			
			Zone A		Zone B	
			Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
3	COAL & COKE					
	(a). Charcoal in bags/bulk.	1 M.T.	35.76	21.45	15.32	9.19
	(b). Coal by whatever name described in Customs Document and used for Thermal Power Plants	1 M.T.	48.53	48.53	-	-
	(c). Coal by whatever name described in Customs Document other than sl.no.3 (b) above.	1 M.T.	48.53	29.12	29.12	17.47
	(d). Coal and Coke handled through Coal Jetty (other than thermal coal).	1 M.T.	48.53	29.12	-	-
	(e). Thermal Coal	1 M.T.	48.53	48.53		

It can be seen that the port has modified the nomenclature of the three items. When requested to elaborately explain the reasons and basis therefor, the port has stated that at present there is no clarity in the classifications of coal as to which are meant for power plants and which are meant for other than power plants, as Customs document classify as Steaming (non-coking) coal only. There is no separate description in the Customs documentation as regard Thermal coal/other coal. Hence the issue of short collection has been observed by Vigilance and Resident Audit observation, due to difference in interpretation. Considering the above, the Coal is brought under single classification. The port has stated that the rate proposed are uniform across all the categories of coal applying 27.7% increase over the existing wharfage rate for coal and coke handled at coal jetty at ₹38/- tonne. The port has confirmed that the impact of revenue increase due to the above modification is suitably captured in the revenue estimates. Relying on the submissions made by the VOCPT, the modification in the nomenclature of coal which is reportedly to bring in clarity and the rates proposed by VOCPT are approved.

- (xxiv). The port has proposed to discontinue advalorem wharfage prescribed in the existing SOR for a few items and has proposed wharfage rate on unit basis. Wharfage rate of ₹150/- per MT is proposed for Machineries and Machinery Parts and for the remaining cargoes, 27.70% increase over the existing wharfage rate of goods otherwise not specified at ₹42.00 per MT is considered and wharfage rate proposed is ₹53.40 per MT. The specific wharfage rate proposed by port in place of advalorem rate is approved.
- (xxv). The port has proposed new wharfage items vide its letter dated 13 June 2016 in respect of handling of automobile through RORO vessels at ₹500/- for handling car below 1600 CC and ₹1000/- for handling car above 1600 CC. The port has stated that the tariff proposed is based on the proposal of Chennai Port Trust (CHPT) to fix the rate for handling automobile through RO RO vessels at ₹500/- for handling car below 1600 CC and ₹1000/- for handling car above 1600 CC. It is relevant here to state that ₹500 per unit proposed in the SOR of CHPT is for two wheelers and not for four wheelers. The wharfage rates proposed for four wheelers in the SOR of CHPT approved by this Authority are as follows:

Sl. No.	Particulars	Unit of levy	Rate in ₹	
			Foreign	Coastal
(i).	Four wheelers of upto 1400 cc			
	(a). Import	Each	4,200	2,520
	(b). Export	Each	2,200	1,320
(ii).	Four wheelers of above 1400 cc -Import & Export	Each	8,400	5,040

Since the proposal of the VOCPT is to adopt the rate prescribed in the SOR of CHPT, the above rates for four wheelers proposed by the CHPT and approved by this Authority are prescribed in the SOR of the VOCPT also. The port has proposed a note that for vehicle with laden containers with trailer, the tariff will be collected at a composite rate covering both vehicle as prescribed and container separately at the rate prescribed separately in the wharfage Schedule. The proposed note is approved.

- (xxvi). (a). The VOCPT has, in the proposed SOR, inserted a note that Vessels which call at Ports, for which IGMs and/or EGMs are filed for the purposes of Customs Act, 1962, cannot be treated as 'cargo', and they are conveyance only, and, the Ports should not charge wharfage on such vessels. This prescription is based on our letter No.TAMP/53/2002-Misc dated 25 March 2015 to all the Major Port Trusts including VPT in pursuance of the MOS letter No.PD-25021/7/2015-PD.1 dated 16 April 2015 of MOS directing to all Major Port Trusts to follow regarding wharfage charges on vessel manifested as cargo in the Import General Manifest (IGM) or Export General Manifest (EGM). This note is not incorporated in revised proposed SOR. The general note in this regard notified by this Authority in the said Order is incorporated in the revised SOR.
- (b). This Authority has, vide Order No.TAMP/52/2014-Genl. dated 28 November 2014, notified the Guidelines issued by the MOS on priority berthing of coastal vessel for common adoption by all Major Port Trusts and has advised the port to suitably amend their existing SOR. Since the proposed SOR did not incorporate the guidelines on priority berthing of coastal vessels at Major Port, the VOCPT was requested to incorporate the same. Though the port has stated that these conditions are incorporated, the same are not incorporated in revised proposed SOR. The guidelines issued by the MOS and notified by this Authority in the said Order are incorporated in the revised SOR.
- (c). It is relevant to state that in pursuance of Ministry of Shipping (MOS) communication vide letter No. PD/14033/101/2015-PD.V dated 3 February 2016 this Authority has passed a common adoption Order No.TAMP/14/2016-Misc dated 9 February 2016 relating to prescription of lower charges for cargo & vessels related services as well as special discount in port charges for the services rendered after regular hours by the Major Port Trusts and BOT Operators operating. The VOCPT has not proposed lower charges for cargo & vessels related services as well as special discount in port charges for the services rendered after regular hours. The VOCPT was, therefore, requested to incorporate the same in the proposed SOR. The port has not incorporated the same despite request. The general note in this regard notified by this Authority in the said common Order is incorporated in the revised SOR.
- (xxvii). The existing SOR prescribes separate charges for hire of Mobile Cranes / Fork Lift Truck /Marshall Demag Crane at Sl. No. 1 to 4 under Chapter 5, Schedule 5.03. The port has proposed deletion of these

tariff citing that these equipment are not available with the Port. The proposal of the port for deletion of these tariff items are accepted.

- (xxviii). The VOCPT has proposed 27.7% increase in the schedule 5.20 - Charges pertaining to use of Harbour Mobile Cranes (HMC) installed by the private operator. In this context, it is relevant to state that the existing tariff for HMC approved by this Authority is as per Order No.TAMP/22/2007-TPT dated 30 December 2009 on normative basis which was continued to be prescribed in the last general revision of SOR at the then prescribed level.

In the Tariff Policy 2015, clause 9.1. to 9.3. prescribes provision for tariff regulation of charges levied by service provider authorized by the port. The proposal filed by the VOCPT applying 27.7% tariff revision for general SOR to HMC operated by authorized service provider was not found to be in line with the said guidelines provision. That being so, VOCPT was requested to file a separate proposal for revision in the rate for HMC provided by the authorized service provider on normative basis. The port has agreed and stated that that based on review and if required proposal will be filed separately. As agreed by the VOCPT, the port is advised to examine the matter and file a proposal, if necessary, for revision in the rate for HMC following the principles followed in the December 2009 Order. Till such time, the existing performance linked rate for 100T HMC is continued to be prescribed in the existing SOR instead of deletion from the SOR proposed by the VOCPT in its revised proposed SOR.

- (xxix). (a). The VOCPT has proposed a new tariff for pollution cess on Dusty Cargoes. As per clause 5.7.1 of the Working Guidelines, 2015, whenever a specific tariff for a service/ cargo is not available in the SOR, of that particular port, the concerned Major Port Trust can propose rate for new cargo/ equipment/ service adopting the tariff and performance standards, in any other Major Port Trust. If there is no rate available in any other Major Port Trust or if the rate available is not representative enough, then the port may file the proposal for new cargo/ equipment/ service with reference to optimal capacity following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service/ facility/ equipment or on cost plus 16% return formula. The VOCPT was requested to clarify under which option, the rate for pollution cess on dusty cargo is proposed amongst the options prescribed in the Working Guidelines.

The port has clarified that the pollution cess on dusty cargoes is not a separate service. In order to recover the amount spent towards cleaning of wharf area and efforts to comply with Environment Management System (EMS) requirements, such pollution cess is proposed at the rate of ₹5/- per tonne on dusty cargoes. The port has stated that presently, lot of emphasis is laid on environmental issue. Hence, port has to take all measures to see that pollution is under control and at the minimum level. In this direction, pollution cess is newly proposed at ₹5/ tonne for dusty cargo. The revenue from this new item is captured in the revenue estimates. Based on the clarification furnished by the port and recognising that even after capturing on revenue of this new tariff item, the revenue estimates is well within the estimated ARR, the proposed pollution cess on dusty cargoes is approved.

- (b). Tamilnadu Generation and Distribution Corporation Limited sought clarification from the port whether, Pollution cess will apply to coal handled at coal jetty I and II. The VOCPT has clarified that it will not apply. Earlier the port stated that if coal jetty I and II creates pollution, port would like to apply the proposed levy to these two coal jetties as well. So port was requested to propose suitable modification in the conditionality in the proposed SOR. Subsequently, the VOCPT has clarified coal at Coal Jetty-I and II is handled in closed conveyor system and hence the said pollution cess will not apply and hence modification in the proposed SOR does not arise.

- (xxx). The point made by M/s.Coastal Mechanised Sail Vessel Owners Associations (CMSV) who operate in Zone B that the Sailing vessels do not come under jurisdiction of TAMP is not correct. It is relevant to state the statute of this Authority is to determine tariff for vessel related and cargo related services rendered by the Major Port Trusts for services listed in Section 48 of the Major Port Trusts Act. The tariff for sailing vessel is prevalent in vogue for more than a decade in last three general revision Order and falls well within the mandate given to this Authority.

- (xxxi). As regard CHD as stated earlier 51.20% increase is approved as proposed by VOCPT. The proposal of the VOCPT to dispense with the pension fund levy of ₹25.10 is accepted. It is relevant to state here that as per Clause 8.4. of the Tariff Policy 2015, Major Ports shall charge only for services provided for them. No notional booking of labour and other similar notional charges is permitted. The VOCPT to comply with the said provision of the Tariff Policy 2015 issued by the Government of India.

- (xxxii). The TANGEDCO vide its letter dated 27 May 2016 has requested this Authority to instruct VOCPT not to insist on collecting Pension Fund Levy of 6.5% for the period beyond 1 April 2016 without approval of this Authority as the last general revision Order stated that Pension Fund Levy @ 6.50% will cease to apply w.e.f. 1 April 2016. In this context, it is relevant to state that the VOCPT while seeking extension of validity of its Scale of Rates beyond 31 March 2016 had also requested to extend the validity of Pension Fund Levy till revised rates are notified by this Authority. In this regard, the VOCPT was vide our letter dated 11 May 2016 requested to justify the extension sought for the Pension Fund Levy of 6.5% for the period beyond 31 March 2016 while seeking extension of the validity of its SOR.

In response, the VOCPT vide its e-mail dated 12 May 2016 has furnished a statement showing deficit of ₹171.56 crores in pension fund account as on 31 March 2016. As per the statement furnished by the VOCPT, the Actuarial Valuation of pension fund as on 31 March 2016 is reported to be ₹626.68 crores whereas the actual pension fund balance on the corresponding date is reported to be ₹455.12 crores. Thus, in view of the shortfall in the pension fund balance reported by the VOCPT sought extension of pension fund levy of 6.5% as well while seeking extension of validity of its existing SOR till the revised SOR are notified by this Authority.

In view of the submission by the VOCPT, this Authority vide Order No.TAMP/47/2012-VOCPT dated 19 May 2016 while extending the validity of Scale of Rates of VOCPT also extended the validity of the Pension Fund levy of 6.5%. This is elaborately brought out in the said Order. As regards the point made by TANGEDCO about seeking their views referring to the Working Guidelines 2015, it is relevant to state that the matter was related to extension of validity of the existing Scale of Rates and not with reference to any proposal of the port under Tariff Policy, 2015. For extension of validity of the existing rates, consultation process is not required to be initiated. It is not done in any orders pertaining to extension of validity of the existing SOR of any of the Major Port Trusts/ BOT operators.

- (xxxiii). As per clause 4.1. of the Tariff Policy, 2015, (i). the additional surplus assessed by this Authority in earlier tariff Orders which remains unadjusted has to be transferred by Major Port Trusts to any fund as desired by the Port Trust, and, further (ii). additional surplus, if any, accruing to the Major Port Trusts during the period of application of existing Scale of Rates till the effective date of implementation of the new Scale of Rates fixed under this policy should be assessed and transferred to the General Reserve and use the funds for the purpose of development, creation and/ or modernization of the port infrastructure facilities.

It is seen that there is no past period unadjusted surplus in the case of VOCPT as regard (i). As regard (ii) above, for the years, 2013-14, 2014-15 and 2015-16 the port has not assessed the actual net surplus/ deficit after admissible cost and 16% return, despite request. The port has merely stated that the existing SOR is lesser by 21.20% over proposed SOR, hence there shall not be any accrual of additional surplus due to extension of existing tariff till revision of revised rates. The port has not furnished cost statement to assessing additional surplus/ deficit cost position.

The port is advised to assess the net surplus / deficit after admissible cost and 16% return for the period 2013-14 to 2015-16 and also till the revised rates now approved comes into effect and the port to transfer the additional surplus, if any, as per clause 4.1. of the Tariff Policy 2015 and also report the position to this Authority within two months from the date of Order comes into effect.

- (xxxiv). As per Clause 3.1. of the Tariff Policy 2015, the Major Port Trusts shall also commit Performance Standards for cargo related services in terms of average ship berth day output, average moves per hour in case of container handling. For vessel side services, the port shall prescribe Performance Standards in terms of average turnaround time of vessels and average pre-berthing time of vessels and any other parameter which is found relevant by the Port. The VOCPT has committed Performance Standards for cargo related services in terms of average ship berth day output in tonnes / day including container handling and for vessel side services, port has proposed Performance Standards in terms of average turnaround time of vessels and average pre-berthing time of vessels, percentage of idle time at berth. Under any other parameters, the port has also proposed performance standards in terms of Gross Productivity in tonnes/ day for mechanized coal at CJI and II, conventional coal handling at berth no. IX, conventional coal at berth no. III and IV, coal conventional and copper concentrate handled at berth No.VIII by the Container Terminal Operator Dakshin Bharat Gateway Terminal Pvt. Ltd. (DBGTPL).

In this regard, it is relevant to mention here that the Performance Standards committed by the Port is to be considered for the operations carried out exclusively by the Port within the port premises, with its own equipment and will not be applicable to the BOT operator rendering services at the port with his equipment for whom separate performance standards have already been prescribed in the relevant Order. As regards berth No.IX which is reportedly given on License basis to IMCOLA Crane Company Private Limited (ICCPL) for deployment of HMC, the tariff of ICCPL will be governed by separate tariff approved by TAMP for deployment of HMC at VOCPT which is linked to performance norms fixed by TAMP. Hence the performance standards proposed for Berth No. IX is not included here.

Further, Berth No.VIII is given by VOCPT to DBGTPL on BOT basis for handling container. Tariff for DBGTPL will be governed by separate tariff approved by TAMP for container terminal for the said berth. Hence the performance standards proposed for Berth No.VIII also cannot form part of the Performance standards for general revision of the SOR of the port.

Further, the port has mentioned in the proposed performance standards that copper concentrate is handled at berth No.VIII by DBGTPL. It is relevant to state that for berth No.VIII, the proposal of the port was for container handling. The upfront tariff notified by this Authority is for container handling as proposed by the port. The tariff notified in the name of the operator DBGTPL is also for container handling. Tariff for operations, if any, carried out by DBGTPL for cargo other than container handling at the said berth does not have approval of this Authority.

Subject to above modification, the performance standard as proposed by the VOCPT which is found to be marginally higher than the performance standards reported to have been achieved in the year 2015-16 is prescribed along with SOR as proposed by the port.

- (xxxv). As per Clause 2.8. of the Tariff Policy, 2015, SOR will be indexed annually to the inflation to the extent of 100% variation in Wholesale Price Indexed (WPI) announced by the Government of India occurring between 1 January 2014 and 1 January of the relevant year and the adjusted indexed SOR will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year. Further, as per clause 3.2 of the Tariff Policy 2015 to be read with clause 2.8 of the Tariff Policy 2015, annual indexation in SOR at 100% of the WPI is applicable subject to achievement of Performance Standards committed by Major Port Trusts. If a particular port does not fulfil the Performance Standard, no indexation would be allowed during the next year. It is relevant to state that in the instant case indexation for the year 2015-16 is already considered in the ARR and for the purpose of drawing the SOR. The next annual indexation in SOR will be applicable from 1 April 2017 subject to achievement of Performance Standards in the year 2016-17. That being so, a note is inserted in the SOR to the effect that the SOR approved by this Authority is subject to automatic annual indexation at 100% of the WPI to be announced by this Authority.

The annual indexation will be from 1 April 2017 subject to the VOCPT achieving the Performance Standards notified alongwith the SOR. If Performance Standards prescribed in the SOR are not achieved, there will be no indexation in SOR for that particular year. The Tariff Policy, 2015, stipulates that annual indexation in the SOR will be automatic subject to achievement of Performance Standards. It does not require the Major Port Trusts to approach this Authority for the same. In Order to have transparency, the port is advised to declare the Performance Standards achieved for the period 1 January to 31 December vis-à-vis the Performance Standards notified by this Authority at the level committed by the port within one month of end of the calendar year to the concerned users as well as to this Authority. If the Performance Standards as notified by this Authority are achieved by the port, then the port can automatically index the rates prescribed in this SOR at 100% of WPI announced by this Authority and apply the indexed SOR VOCPT to be intimated by the port to the concerned users and to this Authority.

- (xxxvi). The validity of the existing SOR of the VOCPT was last extended till 31 August 2016 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier. The port has vide its letter dated 26 August 2016 sought extension of validity of the existing SOR including pension fund levy beyond 31 August 2016 till the revised rates are notified by this Authority. The SOR has been notified on 10 October 2016 which would come into force after expiry of 30 days from the date of notification of SOR. That being so, the existing Scale of Rates including the Pension Fund levy of 6.5% and the Pension Fund Levy for CHD is deemed to have been extended from the date of expiry till the revised SOR comes into effect as sought by the port. The extension in the validity of the pension fund

levy is based on the deficit position reported by the VOCPT at the time of last extension Order, as stated earlier.

(xxxvii). As per Clause 3.8. of Working Guidelines, the SOR notified shall remain valid for 3 years after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. Therefore, and since the Tariff Policy, 2015 requires computation of tariff based on ARR on the actuals reported in the Audited Accounts for three years, the validity of the revised SOR is prescribed till 31 March 2019.

- (xxxviii).(a). As per clause 8.1. of the Tariff Policy 2015, the rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; rebates and discounts are floor levels. The VOCPT may exercise the flexibility to charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.
- (b). As stated earlier, as per Clause 2.7. the Tariff Policy 2015, it is for the VOCPT to ensure that as a result of revision in the SOR there will not be loss of traffic to the port.
- (c). If there is any error apparent on the face of record, the VOCPT may approach this Authority for review of the tariff fixed, giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.
- (d). The modification proposed by VOCPT in the conditionality governing the Scale of Rates are considered for approval based on justification/ clarification furnished by VOCPT. The VOCPT may also for any justifiable reasons, approach this Authority for review of the tariff fixed giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.

15.1. In the result, and for the reasons give above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the revised SOR and the Performance Standards of the VOCPT which has been notified separately. **The effective date of the revised Scale of Rates and conditionalities governing the application of revised Scale of Rates will remain the same as already indicated in the separate Order dated 17 September 2016 notifying the revised SOR and Performance Standards and shall be in force till 31 March 2019.** The approval accorded will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

15.2. The VOCPT has committed Performance Standard for cargo related services in terms of average ship berth day output, average moves per hour in case of container handling. For vessel side services, the port has committed Performance Standards in terms of average turnaround time of vessels and average pre-berthing time of vessels.

15.3. The indexation of SOR as provided in Clause 2.8 of the Tariff Policy, 2015 is to be read with Clause 3.2. of Tariff Policy, 2015. If VOCPT does not fulfil the Performance Standard, the VOCPT is not eligible for indexation during the next year.

15.4. As per Clause 7.1. of the Tariff Policy 2015, Major Port Trust shall furnish to this Authority annual reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each of its berth. The annual reports shall be submitted by the Ports within 60 days following the end of each of the year. Any other information which is required by this Authority shall also be furnished to them from time to time.

15.5. As per Clause 4 of the Working Guidelines this Authority may publish all the information received by it from Major Port Trusts under clause 7.1. of the Tariff Policy, 2015 on its website.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Ext./319/16(143)]

Annex – I

Form – 1

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2015 furnished by VOCPT for port operations (excluding Cargo Handling Division (CHD)).				
		Rs. in lakhs		
Sl. No.	Description	Y1 (2011-12)	Y1 (2012-13)	Y2 (2013-2014)
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)			

(i).	Operating expenses (including depreciation)	9,081.42	9,618.80	10,479.36
(ii).	Management & general Overheads	5,221.51	5,729.93	6,816.73
(iii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	4,565.21	5,545.57	5,740.22
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)+(iii)	18,868.14	20,894.30	23,036.31
(2).	Less Adjustments:			
(i).	Estate related expenses			
	(a). Operating expenses (including depreciation)	636.24	463.86	1,377.83
	(b). Allocated Management & Administrative Overheads	647.64	619.98	899.99
	(c). Allocated FME	334.39	384.23	428.09
	Subtotal 2 (i)=[(a)+(b)+(c)]	1,618.27	1,468.07	2,705.91
(ii).	Interest on loans	-	-	-
(iii).	4/5th of One time expenses, if any like arrears of wages, arrears of pension / gratuity, arrears of exgratia payment, etc. (list out each of the items)			
	(a).	-	-	-
	(b).	-	-	-
	(c).	-	-	-
	Subtotal 2 (iii) = [(a)+(b)+(c)]	-	-	-
(iv).	4/5th of the Contribution to the Pension Fund	1,300.97	640.00	1,720.00
(v).	Management and General overheads over & above 25% of the aggregate of the operating expenditure and depreciation	1,804.84	2,008.71	2,837.17
(vi).	Expenses relevant for tariff fixation of Captive Berth, if any governed under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.			
	(a). Operating Expenses	-	-	-
	(b). Depreciation	58.54	58.83	76.05
	(c). Allocated Management and Administrative Overheads	-	-	-
	(d). Allocated FME	-	-	-
	Subtotal 2 (vi) = [(a)+(b)+(c)+(d)]	58.54	58.83	76.05
	Total of 2 = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	4,782.62	4,175.61	7,339.13
(3).	Total Expenditure after Total Adjustments (3 = 1-2)	14,085.52	16,718.69	15,697.19
(4).	Average Expenses of Sl. No. 3 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3			15,500.46
(5).	Capital Employed			
	(i). Net Fixed Assets as on 31.03.2014 per Audited Annual Accounts (As		88,644.92	
	(ii). Add: Work in Progress as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)		9,980.39	
	(iii). Less: Net value of Fixed assets related to Estate activity as on 31.03.2014 as per Audited Annual Accounts.		650.69	
	(iv). Less : Net value of fixed assets, if any, transferred to BOT operator as on 31 March 2014 as per Audited Accounts. (VII Berth Rs.2637.70 Lakhs + VIII Berth Rs.2375.04 Lakhs+ NCB-1 1732.05)		6,744.79	
	(v). Less : Net value of fixed assets as on 31 March 2014 as per Audited Accounts relevant to be considered for captive berths, if any, under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.		-	
	(vi). Add : Working Capital as per norms prescribed in clause 2.5. of the Working Guidelines			
	(a). Inventory		257.19	
	(b). Sundry Debtors		228.39	
	(c). Cash		1,534.78	
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)		2,020.35	
	(vii). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)+(d)]		93,250.18	
(6).	Return on Capital Employed 16% on Sl. No. 5(vii)			14,920.03
(7).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2014 [(4)+ (6)]			30,420.49
(8).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 i.e. @ 6% (7*1.06)			32,245.72
(9).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2015-16 i.e. @ 3.82% (7*1.0382)			33,477.51
(10).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)			33,477.51
	Less: Balance available under Escrow A/c as on 31.3.2014			5,637.03
	Net ARR			27,840.48
(11).	Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR by VOCPT within the Ceiling indexed ARR .			27,840.87

Annex – II

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy 2015 furnished by VOCPT and Modified by TAMP for Port operation excluding CHD				
₹ in lakhs				
Sr. No.	Description	Y-1 (Actuals) 2011-12	Y-2 (Actuals) 2012-13	Y-3 (Actuals) 2013-14
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)			

(i).	Operating expenses (including depreciation)	9,081.42	9,618.80	10,479.36
(ii).	Management & general Overheads	5,221.51	5,729.93	6,816.73
(iii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	4,565.21	5,545.57	5,740.22
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)+(iii)	18,868.14	20,894.30	23,036.31
(2).	Less Adjustments:			
(i).	Estate related expenses			
	(a). Operating expenses (including depreciation)	636.24	463.86	1,377.83
	(b). Allocated Management & Administrative Overheads	647.64	619.98	899.99
	(c). Allocated FME	334.39	384.23	428.09
	Subtotal 2 (i)=[(a)+(b)+(c)]	1,618.27	1,468.07	2,705.91
(ii).	Interest on loans	-	-	-
(iii).	4/5th of One time expenses, if any like arrears of wages, arrears of pension / gratuity, arrears of exgratia payment, etc. (list out each of the items)			
	(a).	-	-	-
	(b).	-	-	-
	(c).	-	-	-
	Subtotal 2 (iii) = [(a)+(b)+(c)]	-	-	-
(iv).	4/5th of the Contribution to the Pension Fund	1,300.97	640.00	1,720.00
(v).	Management and General overheads over & above 25% of the aggregate of the operating expenditure and depreciation	833.53	1,206.35	1,849.00
(vi).	Expenses relevant for tariff fixation of Captive Berth, if any governed under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.			
	(a). Operating Expenses	-	-	-
	(b). Depreciation	58.54	58.83	76.05
	(c). Allocated Management and Administrative Overheads	-	-	-
	(d). Allocated FME	-	-	-
	Subtotal 2 (vi) = [(a)+(b)+(c)+(d)]	58.54	58.83	76.05
	Total of 2 = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	3,811.31	3,373.25	6,350.96
(3).	Total Expenditure after Total Adjustments (3 = 1-2)	15,056.83	17,521.06	16,685.35
(4).	Average Expenses of Sl. No. 3 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3			16,421.08
(5).	Capital Employed			
	(i). Net Fixed Assets as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)		88,644.92	
	(ii). Add: Work in Progress as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)		9,980.39	
	(iii). Less: Net value of Fixed assets related to Estate activity as on 31.03.2014 as per Audited Annual Accounts.		650.69	
	(iv). Less : Net value of fixed assets, if any, transferred to BOT operator as on 31 March 2014 as per Audited Accounts. (VII Berth Rs.2637.70 Lakhs + VIII Berth Rs.2375.04 Lakhs+ NCB-1 1732.05)		6,744.79	
	(v). Less : Net value of fixed assets as on 31 March 2014 as per Audited Accounts relevant to be considered for captive berths, if any, under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.		-	
	(vi). Add : Working Capital as per norms prescribed in clause 2.5. of the Working Guidelines			
	(a). Inventory			257.19
	(b). Sundry Debtors			228.39
	(c). Cash			1,534.78
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)			2,020.35
	(vii). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)+(d)]			93,250.18
(6).	Return on Capital Employed 16% on Sl. No. 5(vii)			14,920.03
(7).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2014 [(4)+ (6)]			31,341.11
(8).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 i.e. @ 6% (7*1.06)			33,221.57
(9).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2015-16 i.e. @ 3.82% (7*1.0382)			34,490.64
(10).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)			34,490.64
(11).	Revenue estimated by VOCPT at proposed SOR within the Ceiling indexed ARR.			27,840.87

Annex – III

Form – 1 (CHD)

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2015 furnished by VOCPT for Cargo Handling Division (CHD)				
		Rs. in lakhs		
Sl. No.	Description	Y1 (2011-12)	Y1 (2012-13)	Y2 (2013-2014)
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	5,165.96	5,753.90	5,845.41

(ii).	Management & general Overheads	-	-	-
(iii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME) as per Accounts	1,999.90	1,353.06	1,119.98
(iv).	Less: Contribution to Pension Fund	354.00	294.98	-
(v).	Balance F & M Expenditure	1,645.90	1,058.08	1,119.98
(vi).	Add: Pension Fund shortfall in the opening	6,281.76	10,720.69	21,136.00
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)+(v)+(vi)	13,093.62	17,532.67	28,101.39
(2).	Less Adjustments:			
(i).	Estate related expenses			
	(a). Operating expenses (including depreciation)	-	-	-
	(b). Allocated Management & Administrative Overheads	-	-	-
	(c). Allocated FME	-	-	-
	Subtotal 2 (i)=[(a)+(b)+(c)]	-	-	-
(ii).	Interest on loans	-	-	-
(iii).	4/5th of One time expenses, if any like arrears of wages, arrears of pension / gratuity, arrears of exgratia payment, etc. (list out each of the items)			
	(A). Payment of Wage revision arrears	-	-	-
	(B). Arrears of Pension/Commutation of Pension	-	-	-
	(C). Arrears of Gratuity	-	-	-
	Subtotal 2 (iii) = [(a)+(b)+(c)]	-	-	-
(iv).	4/5th of the Contribution to the Pension Fund	5,025.41	8,576.55	16,908.80
(v).	Management and General overheads over & above 25% of the aggregate of the operating expenditure and depreciation	-	-	-
(vi).	Expenses relevant for tariff fixation of Captive Berth, if any governed under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.			
	(a). Operating Expenses	-	-	-
	(b). Depreciation	-	-	-
	(c). Allocated Management and Administrative Overheads	-	-	-
	(d). Allocated FME	-	-	-
	Subtotal 2 (vi) = [(a)+(b)+(c)+(d)]	-	-	-
	Total of 2 = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	5,025.41	8,576.55	16,908.80
(3).	Total Expenditure after Total Adjustments (3 = 1-2)	8,068.21	8,956.12	11,192.59
(4).	Average Expenses of Sl. No. 3 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3			9,405.64
(5).	Capital Employed			
	(i). Net Fixed Assets as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)		7.77	
	(ii). Add: Work in Progress as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)			-
	(iii). Less: Net value of Fixed assets related to Estate activity as on 31.03.2014 as per Audited Annual Accounts.			-
	(iv). Less : Net value of fixed assets, if any, transferred to BOT operator as on 31 March 2014 as per Audited Accounts.			-
	(v). Less : Net value of fixed assets as on 31 March 2014 as per Audited Accounts relevant to be considered for captive berths, if any, under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.			-
	(vi). Add : Working Capital as per norms prescribed in clause 2.5. of the Working Guidelines			
	(a). Inventory			-
	(b). Sundry Debtors			-
	(c). Cash		580.38	
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)		580.38	
	(vii). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)(d)]		588.15	
(6).	Return on Capital Employed 16% on Sl. No. 5(vii)			94.10
(7).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2014 [(4)+ (6)]			9,499.74
(8).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 i.e. @ 6% (7*1.06)			10,069.73
(9).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2015-16 i.e. @ 3.82% (8*1.0382)			10,454.39
(10).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)			10,454.39
(11).	Revenue Estimation by VOCPT at the Proposed rates for CHD within the Ceiling indexed ARR.			10,454.39

Annex – IV

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2015 furnished by VOCPT for Cargo Handling Division and considered by TAMP				
₹ in lakhs				
Sr. No.	Description	Y-1 (Actuals) 2011-12	Y-2 (Actuals) 2012-13	Y-3 (Actuals) 2013-14
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	5,165.96	5,753.90	5,845.41
(ii).	Management & general Overheads	-	-	-

(iii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME) as per Accounts	1,999.90	1,353.06	1,119.98
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)+(iii)	7,165.86	7,106.96	6,965.39
(2).	Less Adjustments:			
(i).	Estate related expenses			
	(a). Operating expenses (including depreciation)	-	-	-
	(b). Allocated Management & Administrative Overheads	-	-	-
	(c). Allocated FME	-	-	-
	Subtotal 2 (i)=(a)+(b)+(c)	-	-	-
(ii).	Interest on loans	-	-	-
(iii).	4/5th of One time expenses, if any like arrears of wages, arrears of pension / gratuity, arrears of exgratia payment, etc. (list out each of the items)			
	(a). Payment of Wage revision arrears	-	-	-
	(b). Arrears of Pension/Commutation of Pension	-	-	-
	(c). Arrears of Gratuity	-	-	-
	Subtotal 2 (iii) = [(a)+(b)+(c)]	-	-	-
(iv).	4/5th of the Contribution to the Pension Fund	283.20	235.98	-
(v).	Management and General overheads over & above 25% of the aggregate of the operating expenditure and depreciation	-	-	-
(vi).	Expenses relevant for tariff fixation of Captive Berth, if any governed under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.			
	(a). Operating Expenses	-	-	-
	(b). Depreciation	-	-	-
	(c). Allocated Management and Administrative Overheads	-	-	-
	(d). Allocated FME	-	-	-
	Subtotal 2 (vi) = [(a)+(b)+(c)+(d)]	-	-	-
	Total of 2 = 2 (i)+2 (ii)+2 (iii)+2 (iv)+2 (v)+ 2 (vi)	283.20	235.98	-
(3).	Total Expenditure after Total Adjustments (3 = 1-2)	6,882.66	6,870.98	6,965.39
(4).	Average Expenses of SI. No. 3 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3			6,906.34
(5).	Capital Employed			
	(i). Net Fixed Assets as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)			7.77
	(ii). Add: Work in Progress as on 31.03.2014 (As per Audited Annual Accounts)			-
	(iii). Less: Net value of Fixed assets related to Estate activity as on 31.03.2014 as per Audited Annual Accounts.			-
	(iv). Less : Net value of fixed assets, if any, transferred to BOT operator as on 31 March 2014 as per Audited Accounts.			-
	(v). Less : Net value of fixed assets as on 31 March 2014 as per Audited Accounts relevant to be considered for captive berths, if any, under clause 2.10. of the Tariff Policy, 2015.			-
	(vi). Add : Working Capital as per norms prescribed in clause 2.5. of the Working Guidelines			
	(a). Inventory			-
	(b). Sundry Debtors			-
	(c). Cash			580.38
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)			580.38
	(vii). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)-(iv)-(v)+(vi)+(d)]			588.15
(6).	Return on Capital Employed 16% on SI. No. 5(vii)			94.10
(7).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2014 [(4)+ (6)]			7,000.45
(8).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2014-15 i.e. @ 6% (7*1.06)			7,420.47
(9).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2015-16 i.e. @ 3.82% (8*1.0382)			7,703.93
(10).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)			7,703.93
(11).	Revenue Estimated by VOCPT and considered by TAMP (see note)			10,454.39
	Note: Revenue Estimated by VOCPT at proposed increase of 51.20% is ₹10,454.39 lakhs. The same is considered by the Authority taking into consideration that revenue shortfall for the port as a whole. The overall ARR for the port as whole is ₹42,195.57 lakhs (i.e. ₹34,490.64 lakhs for Port + ₹7,703.93 lakhs from CHD). Revenue estimates from the port operation assessed by VOCPT is at ₹27,840.84 lakhs leaving a gap of ₹14,353.70 lakhs. Revenue at proposed tariff for CHD at 51.20% is ₹10,454.39 lakhs is within the overall ceiling indexed ARR for the Port as a whole.			